HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 1-15 जुलाई, 2019

द रीव टाइम्स

The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 24/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

मौसम का हाल

मौसम करवटें बदलता रहेगा। इस सप्ताह मौसम जहां मैदानी एवं मध्यम क्षेत्रों में 1,2,3 जुलाई तक हल्की वर्षा एवं गर्जना भरा रहेगा वहीं उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में एक जुलाई को मौसम हल्की वर्षा भरा होगा जबकि 2 और 3 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद फिर से मौसम बदलेगा तथा मौनसून पूर्व की आहट हल्की वर्षा और गर्जना के साथ होती रहेगी।

www.therievtimes.com कार्य वही उत्तम श्रेणी में स्थान पाता है जिसे आपकी आत्मा भी स्वीकार करें : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... हिमाचल समाचार
- पृष्ठ 3 से 6...ज़िलावार ख़बरें
- पृष्ठ 7...कानुन एवं स्वास्थ्य
- पृष्ठ 8...संपादकीय: CAN HIMACHAL BECOME LIQUOR FREE STATE?
- पृष्ठ 9...अभिव्यक्ति: जलने लगी है धरती...विनाश के स्पष्ट संकेत
- पृष्ठ 10...प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11...राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12...अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13...समसामयिक
- पृष्ठ 14...योजनाएं -सुकन्या समृद्धि योजना, बेटी है अनमोल योजना
- पृष्ठ 15...सोलर चरखा मिशन योजना
- पृष्ठ 16...रोचक समाचार

कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में स्मार्ट क्लास रुम के बाद

आसाम, बिहार व पश्चिम बंगाल में भी आईआईआरडी शुरु कर रहा स्मार्ट क्लास रुम

बेहतर और गुणवत्ता आधारित शिक्षा पर सराहनीय पहल

द रीव टाइम्स: हेम राज चौहान

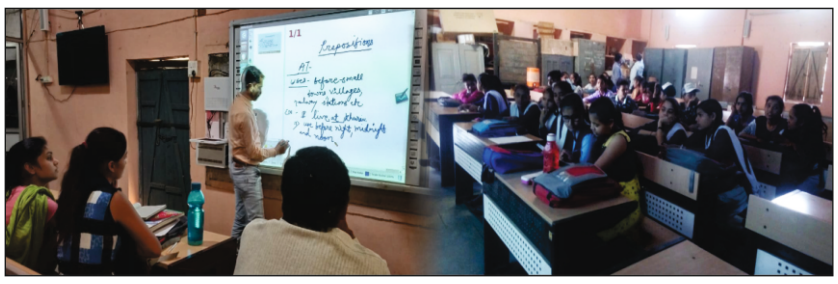

आई आई आर डी के स्मार्ट क्लास रुम पर भारत के विभिन्न राज्यों में किए गए प्रयासों को सराहना मिल रही है। इसी प्रयास में अब आसाम,बिहार और पश्चिम बंगाल में भी सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए संस्था स्मार्ट क्लास रुम शुरु करने जा रही है। आरंभिक तौर पर आसाम के 30 विद्यालय इससे लाभान्वित होंगे। इन स्कूलों में 60 स्मार्टक्लास रुम स्थापित किये जा रहे हैं। इससे सरकारी विद्यालयों के बच्चों को गुणवत्ता तथा तकनीकि शिक्षा का लाभ मिल सकेगा। इन स्मार्ट क्लास रुम में अत्याधुनिक तकनीक से लर्निंग करवाई जाएगी। कंप्युटर, बोर्ड, कैमरा आदि से लैस इन क्लास रुम से उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। आसाम में अंग्रजी और असमिया भाषाओं का प्रयोग होगा। जबकि बिहार एवं पश्चिम बंगाल में स्थानीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाऐगा । इसमें सरकारी स्कूल तो शामिल हैं ही साथ ही ग्रामीण क्षेत्र और दूर-दराज के क्षेत्र भी शामिल है जहां के बच्चे इसका लाभ उठा पाऐंगे। पढ़ाई के अनुभव को और अधिक गुणवत्ता आधारित करने व तकनीक का सदुपयोग करना भी इसका एक बड़ा उद्देश्य है ।

विदित हो कि आईआईआरडी भारत के विभिन्न राज्यों में लगातार इस प्रकार के स्मार्ट क्लास रुम गेल के सौजन्य से स्थापित करने की सफल कोशिश में है। इससे पूर्व कर्नाटक के धारवाड़ में 40, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 20 तथा मध्यप्रदेश के सागर और विदिशा में 20 स्मार्ट क्लास रुम स्थापित कर प्रशंसनीय प्रयास कर चुका है। इसके बाद अब आसाम में भी इसे शुरु किया जा रहा है। अन्य राज्यों में भी भविष्य में इस प्रकार के स्मार्ट क्लास रुम शुरु करने की योजना है ।

बसंतपुर, ननखड़ी और नारकंडा विकास खंड में मिशन रीव का जन-अभियान

पंचायत जन प्रतिनिधियों एवं लोगों से बैठक कर जानकारी की साझा

मिशन रीव और एनएसडीसी प्रशिक्षण के अलावा रीव सलाहकार बोर्ड के गठन पर भी हुई चर्चा

द रीव टाइम्स : हेम राज चौहान

मिशन रीव 2 का गांव-गांव में लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य अपनी नायाब सेवाओं के साथ शिमला ज़िला के विभिन्न विकास खण्डों में जारी है। इस अनूठे प्रयास से लोगों को घर-द्वार पर सेवाओं के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से मिशन रीव के सदस्य विभिन्न विकास खण्डों में जन प्रतिनिधियों से मिले। विगत माह में टीम रीव मशोबरा विकास खण्ड की समस्त 48 पंचायतों में जन प्रतिनिधियों से मिलकर मिशन रीव की जानकारी एवं रीव एसोसियेट की भर्तियों के बारे में चर्चा कर चुकी है जहां से लोगों की बहुत ही सराहनीय प्रतिक्रियाऐं प्राप्त हुई हैं। उसके बाद विकास खण्ड ननखड़ी, नारकंडा एवं बसंतपुर में जनप्रतिनिधियों तथा लोगों से मिलकर चर्चा की गई ।

विकास खण्ड ननखड़ी

विकास खण्ड ननखड़ी के अंतर्गत मिशन रीव की टीम के सदस्यों से विकास खण्ड में जनप्रतिनिधियों से चर्चा की। बैठक में प्रधान एवं अन्य सदस्यगण शामिल हुए। इस अवसर पर स्थानीय पंचायतों के लोगों ने भी भाग लिया। मिशन रीव की जनहित सेवाओं के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया। साथ ही लोगों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का आकलन भी किया गया। लोगों को मिशन रीव की सेवाओं पर विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता से जुड़े लोग भी शामिल थे। ननखड़ी में मिशन रीव की टीम के सदस्यों में आन्नद नायर एवं अंकुश नगरैक शामिल थे। बैठक में शिवदासी, कुलदीप सिंह, शमशेर ठाकुर, मोहन लाल, गोपाल मेहता, देवी सिंह, अंजना नेगी और जवाहर ठाकुर बतौर प्रतिनिधि शामिल रहे।

विकास खण्ड नारकंडा

विकास खण्ड नारकंडा में भी मिशन रीव ने लोगों तथा जन प्रतिनिधियों से मिलकर चर्चा की। मिशन रीव लोगों का घर-द्वार पर समस्त सेवाओं के साथ अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करने में आम लोगों के साथ-साथ जन प्रतिनिधियों के सहयोग को किस प्रकार ले सकता है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में विकास खण्ड अधिकारी सहित सचिव भी शामिल हुए। मिशन रीव की सदस्यता के अलावा रीव ऐसोसियेट्स की भर्ती एवं सलाहकार बोर्ड के गठन पर जानकारी दी गई । इस टीम में मिशन रीव की ओर से एस.के. दत्त एवं मीनाक्षी ने भाग लिया ।

विकास खण्ड बसंतपुर

विकास खण्ड बसंतपुर में भी मिशन रीव ने अपनी सेवाओं को ले जाने के लिए जन प्रतिनिधियों एवं लोगों से चर्चा की। इसके अलावा आम लोग भी इस बैठक में भारी संख्या में शामिल हुए। लोगों ने मिशन रीव संस्करण एक पर भी अपने सवाल किए तथा अपनी जिज्ञासाओं को सामने रखा। कुछ लोगों ने कहा कि सदस्य बनने के बाद भी उन्हें पूर्ण सेवाओं का लाभ नहीं मिल सका। लेकिन मिशन रीव 2 में उन कमियों को पूरा करते हुए 'दिल से सेवा दिल से भुगतान' के प्रारुप को आधार बना कर आम लोगों के दुःख तक़लीफों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है । साथ ही समस्त समस्याओं को 10 प्रभागों में विभाजित कर उनकी जिम्मेवारी को भी साझा करने की कोशिश है। पंचायत स्तर से उपरी स्तर तक रीव सलाहकार बोर्ड का गठन भी होगा जिसमें समाज के बुद्धिजीवियों के साथ-साथ युवाओं, महिलाओं, जनप्रतिनिधियों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। मिशन रीव की सेवाओं व लोगों के बीच रीव सलाहकार बोर्ड पुल का कार्य करेगा।

ग्राम पंचायत पुजारली

ग्राम पंचायत पुजारली में भी मिशन रीव ने अपनी उपस्थिति दर्ज़ कर रीव की जानकारी प्रदान की। पुजारली में प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के अलावा ग्राम सभा सदस्यों ने भी भाग लिया। मिशन रीव पर लोगों ने अपनी बातें साझा की तथा इस नायाब प्रयास की तारीफ की और हर संभव सहयोग की बात भी कही। इस टीम में आन्नंद नायर, मेहरीन इक़बाल, अनुपमा एवं अंकुश ने भाग लिया।

मिशन रीव का स्वच्छता अभियान

शिमला ज़िला के जुब्बल विकास खण्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत बढाल में मिशन रीव के अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में अव्यवस्थित रुप से फैले कूड़े को एकत्रित कर एक स्थान पर इसका निदान किया गया। साथ ही लोगों से मिलकर उन्हें स्वच्छता के प्रति भी जागरुक किया गया। इस अभियान में मिशन रीव टीम के सदस्यों गौरव शर्मा, यशवंत और लेखराज ने भाग लिया ।

THE RIEV TIMES
OFFICIAL MEDIA PARTNER

Dear Industry Colleagues,

We are pleased to inform you that 3rd Krishi and Wellness India 2019 Expo is being held from 06 to 08 August 2019 at Pragati Maidan, New Delhi. The show is organized by Exhibitions India Pvt. Ltd and Co-organised by India Trade Promotion Organisation (ITPO).

BIOTECH

Biotech is the use of living systems to manufacture products intended to improve the quality of life of people. In 2016, Indian biotech industry was US$ 11 billion and is expected to reach annual revenues of US$ 100 billion by 2025.

ORGANIC

Organic products include food and drink, medicines, herbals, textiles, etc., grown or produced without chemicals, synthetic fertilizers/pesticides/other synthetic inputs. In 2017-2018, India produced around 1.70 million MT of certified organic products which includes all varieties of food products namely Oil Seeds, Sugar cane, Cereals & Millets, Cotton, Pulses, Medicinal Plants, Tea, Fruits, Spices, Dry Fruits, Vegetables, Coffee etc. During 2017-18, India exported 4.58 lakh MT. of organic edible products worth 515.44 million USD to USA, European Union, Canada, Switzerland, Australia, Israel, South Korea, Vietnam, New Zealand, Japan etc.

HEALTH & WELLNESS

Indians are moving towards fitness and overall well-being to keep themselves stress free and healthy. In 2015-16, the Indian health & wellness market was estimated at US$ 9.5 billion and is estimated to grow by 20-30 per cent year on year.

ALTERNATIVE MEDICINE

India's alternative medicine market was estimated at US$ 1.8 billion in 2016. The Government of India has set up a dedicated department for Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) to provide impetus to these ancient healthcare systems.

KEY HIGHLIGHTS

Exhibitors	Brands	Delegates
200+	500+	800+
Speakers	Visitors	
65+	10,000+	

We would be delighted to have you as an exhibitor at Krishi and Wellness India Expo 2019

3400 पैट का मानदेय बढ़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 3400 प्राथमिक सहायक शिक्षकों (पैट) का मानदेय 4855 रुपये बढ़ने की अधिसूचना जारी हो गई है। सरकार ने शिक्षकों का मानदेय 27 हजार रुपये प्रतिमाह फिक्स कर दिया है। बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया था। पहले इन शिक्षकों को प्रतिमाह 22,145 रुपये मानदेय मिलता था। मार्च में जारी हुई मानदेय बढ़ोतरी की अधिसूचना से शिक्षकों का मानदेय बढ़ने की जगह करीब साढ़े चार सौ रुपये घट गया था। अधिसूचना में गलत स्केल लगने के चलते मानदेय में कटौती हो गई थी। ऐसे में बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षकों के मानदेय को बढ़ाते हुए 27 हजार रुपये पर फिक्स कर दिया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त 3400 प्राथमिक सहायक शिक्षक बीते करीब 16 सालों से सेवाएं दे रहे हैं।

हिमाचल सरकार ने पूछा, बसों में कितनी हो सकती है ओवरलोडिंग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कुल्लू के बंजार में बस हादसे के बाद ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध के बाद जगह-जगह हो रहे प्रदर्शनों के बीच परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर और मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने परिवहन अधिकारियों के साथ बैठक की। पहले गोविंद ठाकुर ने अधिकरियों की बैठक ली और इसके बाद मुख्य सचिव ने भी अफसरों से चर्चा की। अफसरों से पूछा गया कि बसों में कितनी फीसदी तक ओवरलोडिंग की जा सकती है। इस संबंध में एक दिन के भीतर गणना कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। बैठक में कालाअंब और पांवटा साहिब में इलेक्ट्रॉनिक बूम बैरियर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इससे ओवरलोडिंग बसों के चालान स्वयं होंगे। कुल्लू में बस हादसे के बाद ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध की वजह से यात्रियों को नहीं बैठाया जा रहा। जिस बस में सीट से ज्यादा सवारियां पाई जाती हैं, उनका चालान किया जा रहा है। कई बसों से छात्रों और अन्य लोगों को उतारा जा रहा है, जिस वजह से जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं।

मंत्री के साथ बैठक में हुए ये फैसले

- परिवहन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा
- ग्रामीण क्षेत्रों में 124 नए रूट दिए जाएंगे। ये रूट अगस्त से देना शुरू किए जाएंगे
- प्रदेश की 2982 स्कूल बसों में से 1769 की जांच की जा चुकी है, शेष की अगले 3 माह में जांच पूरी की जाएगी
- सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए प्रदेश के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों की मदद ली जाएगी
- जहां ओवरलोडिंग की समस्या है, उन क्षेत्रों में अस्थायी परमिट जारी किए जाएंगे
- जो निजी बस ऑपरेटर रूट पर नहीं चल रहे हैं, उनके परमिट रद्द किए जाएंगे
- राजस्व में वृद्धि के लक्ष्य को तय सीमा से पूर्व प्राप्त करना
- कांट्रेक्ट कैरेज बसों के संचालन को रेगुलेट किया जाएगा ताकि यात्रियों को असुविधा न हो
- कर जमा करने वाले ट्रांसपोर्टरों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा
- अगले दो वर्षों में मशीनों से वाहनों की फि टनेस जांची जाएगी

हिमाचल में आटा और चावल के कोटे में कटौती

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल सरकार ने आटे और चावल के कोटे में आधा-आधा किलो की कटौती की है। हिमाचल के राशनकार्ड उपभोक्ताओं को जुलाई में साढ़े 12 किलो आटा और साढ़े पांच किलो चावल मिलेंगे। इस महीने उपभोक्ताओं को 13 किलो आटा और छह किलो चावल दिया गया। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने जिला खाद्य नियंत्रक को आदेश जारी कर दिए हैं।

हिमाचल के साढ़े 18 लाख राशनकार्ड उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर सस्ता राशन मिलता है। इसमें साढ़े 12 लाख एपीएल उपभोक्ताओं को आटा और चावल, जबकि बीपीएल परिवारों को 35 किलो चावल और गेहूं दिया जाता है। एपीएल उपभोक्ताओं के राशन कोटे में यह कमी की गई है।

व्हाइट सीमेंट प्लांट लगने की राह हुई मुश्किल, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नौहराधार में व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री लगाने की राह मुश्किल हो गई है। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंच गया है। उच्च न्यायालय ने स्थानीय निवासियों की जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए कंपनी को जारी लेटर ऑफ इंटेंट पर स्टे लगा दिया हैं। मामले की सुनवाई होने तक इस परियोजना की स्थिति यथावत रहेगी। सरकार ने वर्ष 2018 में जोधपुर स्थित अरावली जिप्सम एंड मिनरल लिमिटेड कंपनी को नौहराधार क्षेत्र में व्हाइट सीमेंट प्लांट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया था। इसके बाद स्थानीय लोगों ने निजी भूमि और पर्यावरण बचाव समिति के बैनर तले इस निर्णय का विरोध शुरू किया। समिति ने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेज कर सीमेंट फैक्ट्री न लगाकर कोई अन्य फूड प्रोसेसिंग या पर्यटन विकास परियोजना लगाने की गुहार लगाई थी। प्रभावी कार्रवाई न होने के बाद समिति के अध्यक्ष नौहराधार निवासी दिलीप सिंह चौहान आदि ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। 18 जून को अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए लेटर ऑफ इंटेंट पर रोक लगा दी है। निजी भूमि व पर्यावरण बचाव समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान ने अदालत के निर्णय की प्रति पत्रकारों को देते हुए कहा कि उन्होंने और उनके साथियों जीवन सिंह, जयपाल सिंह, अजय चौहान, राजेंद्र सिंह, यशपाल सिंह और उजागर सिंह आदि ने इस सीमेंट प्लांट लगाने के निर्णय का हर मोर्चे पर विरोध किया।

बंजार बस हादसा : डीसी को सौंपी 58 पन्नों की जांच रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बंजार बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच पूरी हो गई है। गुरुवार को जांच टीम के मुखिया एडीएम कुल्लू ने रिपोर्ट उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा को सौंप दी है। शाम साढ़े चार बजे एडीएम ने 58 पेजों की रिपोर्ट उपायुक्त के सुपुर्द की। हालांकि, रिपोर्ट में क्या है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने 20 जून को बंजार बस हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए थे। इसके दूसरे दिन 21 जून को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू पहुंचकर घायलों का हाल जाना था। इसी दिन सरकार के आदेश पर उपायुक्त कुल्लू ने पांच सदस्यीय टीम का गठन कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। टीम की अध्यक्षता एडीएम कुल्लू अक्षय सूद को दी गई। इसके अलावा एसडीएम बंजार, आरटीओ कुल्लू, डीएसपी कुल्लू और लोनिवि के मेकेनिकल विंग के अधिशासी अभियंता भी टीम में शामिल किए गए। जांच रिपोर्ट में घटना स्थल के साथ प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ, बस हादसे के घायलों, एचआरटीसी के कर्मचारियों और बस को लेकर आरटीओ मंडी से तलब रिकॉर्ड के तथ्य शामिल किए गए हैं। इसके अलावा बस मालिक और बस से छलांग मारने वाले चालक के बयान भी कलमबद्ध किए गए हैं। एडीएम कुल्लू अक्षय सूद ने कहा कि उन्होंने जांच रिपोर्ट उपायुक्त कुल्लू को सौंप दी है। उपायुक्त कुल्लू डॉ. ऋचा वर्मा ने कहा कि उन्होंने अभी जांच रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। बंजार के बयोठ मोड़ पर बस हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए वीरवार को घटनास्थल पर शांति यज्ञ करवाया गया। इस दौरान पाठ किया गया। ज्ञानदीप संस्था की ओर से करवाए गए यज्ञ में बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी भी उपस्थित रहे। शौरी ने मौके पर 21 मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये के चेक वितरित किए। कई पीड़ितों को चार-चार लाख के चेक उनके घर भेज दिए गए हैं। भाजपा मंडल बंजार के अध्यक्ष बलदेव महंत, उपाध्यक्ष श्रवण कुमार, सचिव जय सिंह, प्रधान शेर सिंह, जगदीश ठाकुर, बालक राम ठाकुर, कुलदीप सोनी, दुर्गा सिंह, भीम सेन, ध्यान सिंह मौजूद रहे।

14वें वित्तायोग की धनराशि खर्च न करने वाले प्रधानों पर होगी कार्रवाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ग्राम पंचायतों द्वारा 14वें वित्तायोग के तहत प्रदान की गई धनराशि को समय पर व्यय न करने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। 14वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2015-16 से सभी ग्राम पंचायतों को 1420 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी लेकिन पंचायतें केवल 800 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाई हैं जोकि चिंता का विषय है। मंत्री ने सभी ग्राम पंचायतों से आग्रह किया है कि अपने पास पड़ी धनराशि का उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

उन्होंने चेतावनी दी कि आवंटित धनराशि खर्च करने में विफल रहने पर पंचायत प्रधानों के विरुद्ध नियमों के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें अव्ययित धनराशि पंचायती राज विभाग को वापिस करनी होगी। वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि धनराशि राज्य की सभी 3226 पंचायतों में सीधे हस्तांतरित कर दी गई थी जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों विशेषकर सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाईट, सड़कों के निर्माण व मुरम्मत, सार्वजनिक शौचालय, हैंड पंप व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति के कार्यों के लिए किया जाना था।

उन्होंने सभी खण्ड विकास अधिकारियों को ग्राम पंचायत की मासिक बैठक के दौरान 14वें वित्तायोग के तहत की जा रही विकासात्मक कार्यों की नियमित समीक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए और पंचायती राज निदेशालय को इस संबंध में

मुख्यमंत्री ने महिन्द्रा और गोदरेज ग्रुप के साथ की अहम बैठक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में मुम्बई में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल महिन्द्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिन्द्रा के साथ बैठक की तथा उनसे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के बारे में विस्तार में चर्चा की। मुख्यमंत्री ने श्री महिन्द्रा से पर्यटन ऑटोमोबाईल और सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में विशेषकर निवेश करने पर विचार करने का आग्रह किया। महिन्द्रा ने पर्यटन, रियल इस्टेट जैसे क्षेत्रों में निवेश के प्रति अपनी गहरी रुचि व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ की गई 'नई राहें, नई मंजिलें' योजना की प्रशंसा की तथा इस योजना में सांझेदारी करने की भी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा कि महिन्द्रा ग्रुप ठियोग के कंडाधार में ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए 200 करोड़ रुपये निवेश करने जा रहा है, इससे 200 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उद्योग मंत्री ब्रिकम सिंह ने कूड़े से ऊर्जा बनाने वाली परियोजना के लिए महिन्द्रा ग्रुप के प्रयासों की सराहना की तथा उनसे शिमला व धर्मशाला जैसे शहरों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसी परियोजनाएं लाने का आग्रह किया। महिन्द्रा ग्रुप ने यह भी बताया कि यह ग्रुप हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट सीटी परियोजनाओं के तहत इलेक्ट्रिक बसे चलाने तथा इन्टेलिजेन्ट यातायात व्यवस्था में भागीदार बनने की संभावनाएं तलाश रहा है। बैठक के दौरान, महिन्द्रा ग्रुप ने कूड़े से ऊर्जा बनाने में रुचि दिखाते हुए हिमाचल में निवेश करने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि 'पाईन कोन व पत्तियां' को ऊर्जा में परिवतित करने की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। इसके उपरांत, मुख्यमंत्री और प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष आदी गोदरेज से मुलाकात की और उनसे राज्य में एफएमसीजी व रियल इस्टेट सेक्टर में उनकी उपस्थिति बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने श्री गोदरेज को अवगत करवाया कि राज्य सरकार ने उद्योग के विकास के लिए उत्साहवर्धक और आशाजनक वातावरण बनाया है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि राज्य में 'टूलरूम' स्थापित करने पर विचार किया जाए क्योंकि उनकी कंपनी की इस क्षेत्र में निपुणता है। उन्होंने गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष को धर्मशाला में नवम्बर माह में आयोजित होने वाली ग्लोबल इंवेस्टस मीट के लिए भी आमंत्रित किया। गोदरेज ग्रुप के अध्यक्ष ने प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया कि वह अपने सभी व्यवसायों के बारे में एक उपयुक्त नोट भेजेंगे और राज्य में निवेश के अवसरों का पता लगाएंगे।

एक साथ होंगे शहरी-स्थानीय निकाय के चुनाव, कैबिनेट में होगी चर्चा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कही है, जिस पर बड़े स्तर पर चर्चा चल रही है। भाजपा का कुनबा मोदी के साथ है और जहां-जहां भाजपा नीत सरकारें हैं, वे भी इसका समर्थन कर रही हैं। हालांकि इस पर आखिर होगा क्या यह किसी को पता नहीं, परंतु हिमाचल की जयराम सरकार इस पर गंभीरता से सोच रही है। प्रदेश सरकार का विचार है कि लोकसभा या विधानसभा के एक साथ चुनाव को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर फैसला होगा, लेकिन यहां शहरी व स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ करवाने पर फैसला प्रदेश सरकार कर सकती है, जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में है। दूसरे राज्यों से आगे बढ़कर इस तरह की सोच अपनाने में यहां की सरकार पहले पायदान पर रहना चाहती है और आने वाले समय में इस पर फैसला भी हो सकता है। प्रदेश में वर्तमान में 54 शहरी निकाय हैं, जबकि 3216 ग्राम पंचायतें हैं, जिन्हें दोबारा री-ऑर्गेनाइज करने की सोची जा रही है। यहां दो नगर निगम भी हैं। इन सभी के चुनाव अलग-अलग समय में होते हैं। पंचायतों का चुनाव एक साथ होता है, वहीं शहरी निकायों का एक साथ, परंतु नगर निगम के चुनाव की प्रक्रिया व समय इन सभी से अलग रहता है। इसके चलते पांच साल में अलग-अलग समय पर यहां आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहती है, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसमें धन का अतिरिक्त उपयोग भी शामिल रहता है, वैसे वह ज्यादा अहम नहीं है। प्रदेश सरकार सोच रही है कि शहरी व स्थानीय निकास के चुनाव यदि एक साथ हों, तो एक ही बार आदर्श चुनाव आचार संहिता लगेगी, जिससे लोगों को भी दिक्कत नहीं और सरकार को भी विकास में बाधा नहीं आएगी। इस तरह का प्रस्ताव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सरकार को आने वाले समय में देने की सोची जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को तैयारी के लिए कहा गया है। कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी और यह सब किस तरह संभव होगा, यह देखा जाएगा।

इस मामले में प्रदेश सरकार जहां अपना निर्णय तो लेगी ही, वहीं दूसरे राजनीतिक दलों से भी इस पर चर्चा की जाएगी। सभी की राय को शामिल कर यहां एक साथ चुनाव की सोची जा सकती है। इसे किस तरह सुनिश्चित करेंगे, यह समय बताएगा। बता दें कि नगर निगम शिमला व धर्मशाला के भी चुनाव अलग-अलग समय में होते हैं, वहीं नगर पंचायतों, नगर परिषदों के चुनाव एक साथ होते हैं। पंचायतों के चुनाव की प्रक्रिया अलग से रहती है। इन सभी का समय अलग-अलग निर्धारित है।

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर अब लागू होगा ड्रेस कोड

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर अब ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। उच्च शिक्षा निदेशालय स्कूली बच्चों की तर्ज पर अब अध्यापकों के लिए भी ड्रेस कोड बनाया जा रहा है। निदेशालय के स्तर पर इस पर काम शुरू हो गया है। इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर जल्द सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। सूत्रों की मानें तो प्रस्ताव में शिक्षकों के लिए फॉर्मल ड्रेस और शिक्षिकाओं के लिए साड़ी या साधारण सूट-सलवार की ड्रेस कोड तय किया जाएगा। देश के कई राज्यों में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू है। इसी तर्ज पर अब सूबे में भी यही व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों की ड्रेस के रंग तय करने के लिए अधिकारियों ने अन्य राज्यों का ड्रेस कोड स्टडी करना शुरू कर दिया है। विषय विशेषज्ञों से भी मदद ली जाएगी। बीते दिनों ही उच्च शिक्षा निदेशक ने वीडियो कांफ्रेंस कर सभी जिला उपनिदेशकों को शिक्षक - शिक्षिकाओं के स्कूल में फैशनेबल कपड़े पहनकर आने पर रोक लगाने को कहा है।

कुछ सरकारी स्कूलों में है ड्रेस कोड

हिमाचल के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए अब ड्रेस कोड लागू करने की तैयारी है। प्रदेश के कुछ सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपलों ने सरकार से मंजूरी लेकर अपने स्तर पर ही शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू कर रखा है। सोलन जिले के धुंधन स्कूल में शिक्षकों के लिए तय ड्रेस का शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज कई कार्यक्रमों में उल्लेख करते हुए अन्य प्रिंसिपलों से भी इस बारे अपील कर चुके हैं। स्कूलों में फैशनेबल कपड़े पहनकर आने वाले शिक्षकों पर लगाई रोक का मामला सोशल मीडिया पर छा गया है। कुछ शिक्षक जहां इन आदेशों का विरोध कर रहे हैं, वहीं कुछ शिक्षक ड्रेस कोड की वकालत करते हुए इस आदेश के पक्ष में हैं। निदेशक के इस फरमान को लेकर सोशल मीडिया पर खूब व्यंग्य भी किऐ गए।

किन्नर कैलाश ट्रैक के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर

उपायुक्त किन्नौर गोपाल चंद ने कहा कि किसी भी पर्वतारोही व श्रद्धालु को किन्नर कैलाश ट्रैक पर बिना प्रशासनिक स्वीकृति के जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिले में ट्रैकिंग का आयोजन करने वाले टूअर ऑपरेटरों को पर्यटन विभाग के साथ अपना पंजीकरण अनिवार्य होगा तथा उन्हें ट्रैकिंग गतिविधि शुरू करने से पहले निकटतम पुलिस स्टेशन में ट्रैकर्स की सूचि उपलब्ध करवानी होगी। टूअर ऑपटरों को ट्रैकिंग खत्म होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में ट्रैकरस की सूची जमा करवानी होगी। अवैध साहसिक ट्रैकिंग गतिविधियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विविधक साहसिक गतिविधियां नियम, 2017 के अनुसार जिले में किसी भी ट्रैकिंग गतिविधि पर्यटन अधिकारी को पूर्व अनुमति से की जा सकेगी। इसके अलावा, ट्रैक कैम्पिंग की अनुमति वन विभाग से लेनी अनिवार्य है। उपायुक्त ने स्थानीय नागरिकों से भी जिला प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे बाहर से आने वाले लोगों को किन्नर कैलाश ट्रैक की ओर जाने की सलाह नहीं दें। उन्होंने प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए किन्नर कैलाश प्रवेश द्वार पर सूचनात्मक संदेश लगाए जाएं। पुलिस अधीक्षक किन्नौर को किन्नर कैलाश की तरफ जाने वाले यात्रियों को रोकने के लिए जवान तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। गोपाल चंद ने बताया कि किन्नर कैलाश यात्रा - 2019 मौसम की स्थिति पर विचार करने के बाद ही शुरू की जाएगी। आधिकारिक तिथि से पहले किसी को भी ट्रैक करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, एसडीएम कल्पा सुरेन्द्र ठाकुर, गृह रक्षा के कमांडेंट सुरेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. पदम नेगी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

शिमला के खेतों में जिंक की कमी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शिमला जिला के किसानों बागबानों के खेतों में जिंक की कमी आने वाले पांच से छह साल में बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। कृषि विभाग ने इस समस्या को लेकर किसानों को एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं, केंचुए से बनने वाली खाद के लिए अलग से बॉक्स और बेहतर क्वालिटी के केंचुए मुहैया करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2018–2019 जिला कृषि विभाग ने लगभग 8000 मिट्टी के सैंपल लिए थे कि स्वाइल टेस्टिंग रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दस फीसदी खेतों में जिंक की कमी पाई जा रही है। वहीं कहीं नाइट्रोजन की मात्रा हाई है, तो कहीं मीडियम है। पोषक तत्वों की मात्रा को भी कृषि विभाग ने नोर्मल बताया है, इसके साथ ही पोटाश को भी नोर्मल बताया है। जिला कृषि विभाग ने बताया है कि अपर शिमला के खेतों में अहर्गेनिक खेती के लिए 70 प्रतिशत ठीक है। फिलहाल विशेषज्ञ बतातें है कि जिन भी जगहों से यह आठ हजार सैंपल भरे गए हैं, वहां पर केवल 20 फीसदी ही खेतों में हर फसल की पैदावार के लिए पौष्टिक आहार की मात्रा ठीक है कृषि विभाग ने साफ किया है कि भले ही बारिश की कमी के चलते खेतों में कई जगहों पर नमी की कमी पैदा हो रही हो, लेकिन किसानों द्वारा कई जगहों पर पानी की मात्रा ज्यादा डालने से वहां पर खासा नुकसान हो रहा है। फिलहाल कृषि विशेषज्ञों ने किसान बागबानों को सलाह दी है कि ज्यादा पानी की मात्रा भी आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए यह जरूरी है कि ज्यादा पानी वाली जगहों पर ऐसे प्रोडक्ट ही लगाएं जहां पर पानी की ज्यादा आवश्यकता हो। कृषि विभाग ने पिछले साल लिए आठ हजार किसानों के सैंपल रिपोर्ट तैयार कर उन्हें भेजने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि जिन फार्मर्स ने ऑनलाइन सैंपल व ऑफलाइन सैंपल भरवाएं थे, उन्हें डिजिटल कार्ड मुहैया करवाए जा रहे हैं। इन डिजिटल कार्ड में फार्मर्स को सुझाव भी दिए गए हैं। ये डिजिटल कार्ड फार्मर्स के लिए काफी सहायक भी सिद्ध हो रहे हैं।

तीन साल में एक बार मिट्टी की टेस्टिंग जरुरी

तीन साल में एक बार अपने खेतों में मिट्टी का परीक्षण करना बेहद जरूरी है। विभाग के विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसान समय-समय पर मिट्टी परीक्षण करवाएं तो इससे मिट्टी में होने वाले पौष्टिक आहार की कमी को दूर किया जा सकता है।

सरकार ध्यान दे तो शाली टिब्बा में आएगी बहार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

कृप्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावना के बावजूद भी नए पर्यटन स्थल विकसित नहीं हो पाए। पर्यटन मानचित्र पर उभर चुके पर्यटन स्थल भी सरकारी उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। राजधानी के समीप ही ऐसे कितने ही छोट-बड़े स्थल हैं जिन्हें संवारा जाए तो प्रदेश में पर्यटकों की आमद भी बढ़ेगी और बेरोजगारों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। शिमला ग्रामीण की तहसील सुन्नी में धार्मिक दृष्टि से जिला शिमला में ख्याति अर्जित कर चुके शाली टिब्बा में पर्यटन स्थल की सारी खूबियां मौजूद हैं। बावजूद इसके सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि पूर्व सरकार के कार्यकाल में शाली को पर्यटन की दृष्टि से उभारने के लिए अवश्य कवायदें आरम्भ हुई थी परन्तु वह सब फाइलों में ही बन्द हो गई। प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर मां भीमाकाली के अवलोकनीय स्थल शाली टिब्बा धार्मिक के साथ ऐतिहासिक स्थल के तौर पर भी जाना जाता है। समुद्रतल से लगभग 9600 फुट की ऊंचाई पर स्थित शाली टिब्बा में मां भीमाकाली मंदिर की स्थापना 15 वीं सदी के आरंभ में ठाकुर आलम चंद द्वारा वजीर बदरा पण्डित के सुझाव पर की गई थी। काठकुणी शैली में बने इस मन्दिर का जीर्णोद्वार आसपास के ग्रामीणों ने 1990 में करवाया था। कुछ साल पहले मंदिर में आसमानी बिजली गिरने से अब यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। शाली टिब्बा का महत्व न केवल धर्मिक स्थल के रूप में ही है परंतु चारों ओर घने देवदार के जंगलों से घिरे होने एवं यहां तक पहुंचने वाला कई किलोमीटर का रास्ता प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज होने के कारण पर्यटक स्थल की सारी खूबियां समेटे हैं। यही कारण है कि यहां तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं से लंबे ट्रैकिंग मार्ग पर देश विदेश से ट्रैकर्स पूरा वर्ष आवागमन करते हैं। चैत्र एवं अश्वनी नवरात्रों में यहां पर दूर-दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सरकार एवं पर्यटन विभाग के उदासीन रवैये के कारण पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं के ठहरने एवं खाने पीने की आठ किलोमीटर तक कोई भी व्यवस्था नहीं है। लगभग 8 किमी दूर खटनोल में वन विभाग का वर्षों पुराना विश्राम गृह मौजूद है। हालांकि खटनोल से पहले एक दो लोग निजी स्तर पर होमस्टे योजना के माध्यम से पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

एक और बस हादसे ने लील ली होनहारों की ज़िंदगी

शिमला के झंझीड़ी में बच्चों को ले जा रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

प्रदेश में एक के बाद एक बस हादसा चिंता का सबब बनता जा रहा है। शिमला के झंझीड़ी में एक निजी स्कूल के बच्चों को ले जा रही बस सड़क से बाहर गहरी खाई में गिर गई जिसमें समाचार लिखे जाने तक चालक सहित 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। इस घटना ने सबका दिल दहला दिया है। मौके पर स्थानीय लोगों ने घायल बच्चों को अस्पताल पंहुचाने में मदद की लेकिन लोगों का आक्रोष सड़कों पर दिखा। सरकार लगातार हो रहे हादसों के कारण लोगों की नाराज़गी के बाद भी कड़े क़दम उठाने में नाकामयाब रही है। सरकारी चालकों व परिचालकों पर अभिभावक अक्सर ही बद्तमीजी करने व दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाते रहे हैं।

111 लघु सिंचाई योजनाएं होंगी तैयार: मारकंडा

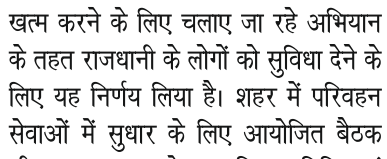

द रीव टाइम्स ब्यूरो, लाहौल-स्पीति

जनजातीय सलाहकार समिति की बैठक काजा में कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉ. रामलाल मारकंडा की अध्यक्षता में हुई। इसमें स्पीति घाटी में गत वित्त वर्ष में किए गए विकासात्मक कार्यों तथा इस वित्त वर्ष में चलाए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई। प्रदेश में 338 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आरंभ की जा रही है। इसमें 111 लघु सिंचाई योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे प्रदेश की 17880 हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिलेगी। मंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन विकास कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूरा करें तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें, जिससे लोगों को सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने गांव में जनसभा को भी संबोधित किया। कहा कि घाटी के हर व्यक्ति को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो तथा किसान के हर खेत तक पानी पहुंचे यह सुनिश्चित किया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री की सोच वर्ष 2022 तक किसानों के आय को दोगुना करना है। इसके लिए हर खेत को पानी उपलब्ध करवाना प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार की हिमकेयर स्वास्थ्य योजना के तहत 5 जुलाई तक अपना पंजीकरण करवा कर अपना हेल्थ कार्ड बनाएं। इसके तहत उन्हें 5 लाख रुपये तक बीमा मिलेगा। इस संदर्भ में संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा - निर्देश दिए गए हैं।

एक महीने के भीतर स्कूलों को खरीदनी होंगी अपनी बसें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

राजधानी शिमला के प्राइवेट और कान्वेंट स्कूलों को एक माह के भीतर स्कूली बच्चों के लिए 4–4 बसों का बंदोबस्त करना होगा। मौजूदा समय में बतौर स्कूल बस सेवाएं दे रहीं एचआरटीसी की बसें शहर के लोकल रूटों पर सेवाएं देंगी। बसों में ओवरलोडिंग खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत राजधानी के लोगों को सुविधा देने के लिए यह निर्णय लिया है। शहर में परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा, विधि एवं संसदीय मामले मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शहर के लोगों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ओवरलोडिंग पर रोक लगाना जरूरी है। लोगों को आवाजाही के लिए पर्याप्त संख्या में बसें उपलब्ध हों इसके लिए एचआरटीसी की 62 बसें जो प्राइवेट और कान्वेंट स्कूलों के लिए बतौर स्कूल बस सेवाएं दे रही हैं उन्हें लोकल रूटों पर चलाया जाएगा।

बस में लिखना होगा ऑपरेटर का नंबर

प्राइवेट बस में अब ड्राइवर की फोटो लगाना अनिवार्य कर दिया है और साथ ही संबंधित बस ऑपरेटर को अपना संपर्क नंबर लिखना जरूरी है। ड्राइवर और कंडक्टरों को वर्दी पहननी होगी। यह फैसला सड़क हादसों से निपटने के लिए लिया है। प्राइवेट बस में स्थायी ड्राईवर कई बार किसी और के हाथ में बस दे देता है जिससे हादसे का अंदेशा बढ़ जाता है। डीसी अमित कश्यप ने बताया कि स्कूलों को बच्चों को लाने ले जाने वाली स्कूल बसों और कैब में सीसीटीवी कैमरे तथा जीपीएस सिस्टम लगाने के आदेश दिए हैं।

एचआरटीसी के पास स्टाफ की कमी

एचआरटीसी के पास चालक परिचालकों की कमी के कारण शहर में अतिरिक्त बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। निगम के लोकल डिपो की 62 स्कूल बसों को अगर लोकल रूटों पर चलाया जाता है तो निगम उन रूटों पर भी सेवाएं दे पाएगा जहां स्टाफ की कमी के कारण बसें नहीं चल पा रहीं।

पांच सौ स्कूलों को नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शिमला जिला के सरकारी स्कूलों में टीचर डायरी मेंटेन न करने पर शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किए हैं। अभी केवल पांच सौ स्कूलों को ही रिमाइंडर जारी हुए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग जिला के सभी स्कूलों को रिमाइंडर भेज रहा है। दरअसल समग्र शिक्षा के तहत सरकारी स्कूलों में छात्रों को टीचर डायरी दी गई थी। इस डायरी में छात्रों को क्या पढ़ाया गया, कितने टेस्ट लिए गए, व दूसरे दिन के लिए क्या कार्य दिया गया है, यह अपडेट करना था। हैरत है कि जिला के जिन स्कूलों ने टीचर डायरी शुरू की भी है, वे हफ्ते में केवल एक या दो बार ही उसमें छात्रों को दिए जाने वाले होमवर्क को अपडेट कर रहे हैं। वहीं, ज्यादातर स्कूलों ने तो टीचर डायरी को शुरू भी नहीं किया है। यह खुलासा जिला उच्च शिक्षा विभाग की टीम द्वारा तब हुआ जब वह फील्ड में उतरे। फिलहाल शिमला उच्च शिक्षा विभाग की उपनिदेशक ने स्कूल प्रबंधन को शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इन निर्देशों को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं, दस दिनों के अंदर रिपोर्ट न भेजने पर स्कूल प्रबंधन व टीचर डायरी मेंटेन न करने पर कार्रवाई करने के भी आदेश हुए हैं। बता दें कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने टीचर डायरी उपलब्ध करवाई है। टीचर डायरी के साथ अब जल्द ही सरकारी स्कूलों में पहली बार छात्रों को निजी स्कूलों की तर्ज पर स्टूडेंट्स डायरी भी दी जाएगी। शिमला के विंटर स्कूलों में अगले सत्र से ही स्टूडेंट्स डायरी को मेंटेन करने के निर्देश दिए जाएंगे। छात्रों व टीचर डायरी शुरू करने का शिक्षा विभाग का यही मकसद था कि छात्रों के सिलेबस को करने संबधित सभी जानकारियां लिखित में हों। डायरी में छात्रों को रोज होमवर्क और एसएमसी की बैठक के बारे में डायरी में बताने के निर्देश स्कूल प्रबंधन को देने होंगे। अभिभावकों को डायरी के माध्यम से स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई की अपडेट देनी होगी। इसके साथ ही पेरेंट्स मीटिंग के बारे में भी स्टूडेंट्स डायरी में नोट लिखकर बताना होगा।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

छह माह से लटका सड़क का काम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

उपमंडल बंगाणा के तहत लोक निर्माण विभाग जोल के अधीन डीहर से राजपुरा सड़क का अधूरा निर्माण कार्य 6 महीने से बंद है। इससे लोगों में भारी रोष है। डीहर, राजपुरा के ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों में पंचायत प्रधान बलदेव सिंह, उपप्रधान रघुवीर सिंह ठाकुर ग्रामीण मस्तराम, बुद्धि सिंह, सुखदेव, रणजीत सिंह, सोहन लाल, रामकिशन, रतन चंद, लटूरिया राम, हजारी लाल, सोहन सिंह ने कहा कि सड़क के टेंडर को 6 महीने हो गए हैं। आधी सड़क पक्की करने के बाद काम छोड़ दिया गया। कई बार पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़क के बारे में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार को इस समस्या के लेकर अवगत करवाया। आज और कल काम शुरू होने आश्वासन ही मिलता है। सड़क की पुलियों, डंगों और सड़क के आसपास की नालियों का काम भी अधूरा है। ग्रामीण का कहना है कि बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। इससे इस मौसम में सड़क का काम पूरा नहीं हो पाएगा। इससे आगे भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि जिस तरह से सड़क के कार्य को बंद किया है, उस हिसाब से ये जल्द पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने विभाग और सरकार से मांग की कि इस कार्य को जल्द से जल्द करवा दिया जाए। लोक निर्माण विभाग जोल के मुताबिक काम शुरू कराने की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और जल्द काम किया जाएगा।

उद्योग लगाने को ऋण के नाम पर फर्जीवाड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो ऊना

क्षेत्र के एक उद्योगपति को दिल्ली की एक फर्म रॉयल एंबिट ने ऋण देने के नाम पर करीब 35 लाख का चूना लगाया है। इस फर्म पर गगरेट की एक फर्म सुमित इंटरप्राइजर के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस ने इस मामले में रॉयल एंबिट फर्म के चार लोगों को नामजद किया है। जानकारी के अनुसार सुमित इंटरप्राइजर के मालिक सुमित खन्ना ने रॉयल एंबिट फर्म को सात करोड़ का ऋण लेने के लिए 35 लाख रुपये बतौर कमीशन दिया था। सुमित खन्ना गगरेट औद्योगिक क्षेत्र के बीजापुर में एक उद्योग लगा रहा था। उक्त उद्योग के लिए 7 करोड़ का ऋण लेना था। सुमित खन्ना का गगरेट के होशियारपुर मार्ग पर एक उद्योग पहले से है और दूसरे उद्योग को वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर लगाना चाहता था। इसके लिए रॉयल एंबिट फर्म को हायर किया गया। 35 लाख लेने के बावजूद उक्त फर्म ने उनके उद्योग के लिए ऋण उपलब्ध नहीं करवाया और न ही इस फर्म के पैसे लौटाए।

उधर, अंब के कार्यकारी डीएसपी धनराज सिंह का कहना है कि रॉयल एंबिट फर्म दिल्ली की है जिसके खिलाफ अदालत की ओर से गगरेट थाने को मामला दर्ज करने के आदेश मिले हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने अदालत के निर्देश पर चार लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

बीबीएन के होटल-ढाबों से छुड़वाए आठ बाल मजदूर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

फार्मा हब बीबीएन के होटलों-ढाबों में काम करने वाले बाल मजदूरों को छुड़वाया गया है। बीबीएन में विभिन्न विभागों की संयुक्त टीम की कार्रवाई में आठ बाल मजदूरों को होटलों-ढाबों में काम करते हुए पाया गया। क्षेत्र के होटल-ढाबों पर काम करने वाले इन बाल मजदूरों पर श्रम विभाग, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड हेल्पलाइन, जिला बाल संरक्षण विभाग ने पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की है। इसके तहत ढाई दर्जन से अधिक होटल-ढाबों को खंगाला गया। इस दौरान आठ बाल मजदूरों को छुड़वाया गया। श्रम विभाग बद्दी के श्रम निरीक्षक कमल सिंह और श्रम निरीक्षक नालागढ़ राकेश खट्टा की अगुवाई वाली टीम में श्रम निरीक्षक नालागढ़ राकेश खट्टा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की चेयरपर्सन विजय लांबा व सदस्य कृष्णा, चाइल्ड हेल्पलाइन की कोऑर्डिनेटर अनीता शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी बीआर वर्मा, प्रोबनशनर ऑफिसर सपना मौजूद रहे। औद्योगिक हब बीबीएन में बाल मजदूरी के मामलों पर विभागों की यह नियमित कार्रवाई अमल में लाई गई। क्षेत्र के करीब 30 होटल व ढाबों पर औचक दबिश दी गई और आठ बच्चों को बाल मजदूरी करते पाया गया। टीम ने इन बाल मजदूरों का नालागढ़ अस्पताल में मेडिकल करवाया। मेडिकल के बाद बाल मजदूरों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सुपुर्द किया गया जो इन्हें बाल संरक्षण गृह में भेजेगी। श्रम निरीक्षक कमल सिंह ने बताया कि यह रूटीन कार्रवाई विभिन्न विभागों के सहयोग से की गई। श्रम निरीक्षक नालागढ़ राकेश खट्टा ने कहा कि जिन होटल व ढाबों से काम करते हुए बाल मजदूर पकड़े गए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं दोषी पाए जाने की सूरत में उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

टेक्नोमैक घोटाला: बिजली बोर्ड के तत्कालीन एसडीओ, एक्सईएन को समन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

बहुचर्चित 4300 करोड़ के टेक्नोमैक घोटाले मामले में स्पेशल कोर्ट ने बिजली बोर्ड के तत्कालीन एसडीओ और एक्सईएन को समन जारी किए हैं। ये दोनों तय तिथि को कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पेशल कोर्ट नाहन के न्यायाधीश जसवंत सिंह की अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि बिजली बोर्ड के तत्कालीन एसडीओ व अधिशासी अभियंता अदालत में पेश नहीं हुए। लिहाजा, अदालत ने उन्हें समन जारी किए हैं। बता दें कि टेक्नोमैक कंपनी के खिलाफ स्टेट सीआईडी ने कर चोरी के साथ पांच करोड़ के फर्जी आरटीजीएस और बिजली बिलों के घोटाले का भी मामला दर्ज किया है। बिजली बोर्ड के दोनों अधिकारियों के समय ही यह घोटाला हुआ। मौजूदा समय में दोनों अधिकारी बोर्ड में ऊंचे पदों पर तैनात हैं। कंपनी में फर्जी आरटीजीएस तैयार कर फर्जी तरीके से बिलों का भुगतान किया जाता था। अब तक स्टेट सीआईडी ने टेक्नोमैक घोटाले में संलिप्त 19 लोगों की गिरफ्तारी की है। सुनवाई के दौरान सीआईडी ने टेक्नोमैक के कर्मी गौतम सेठ, अनूप शर्मा, त्रिलोचन बिल्वास, विवेक गुप्ता व प्रदीप मेहरा को पेश किया गया। उधर, स्टेट सीआईडी क्राइम के एएसपी वीरेंद्र कालिया ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड के दोनों अधिकारियों को समन जारी करने के आदेश हुए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

थानाकलां में बायो गैस प्लांट को मिली मंजूरी

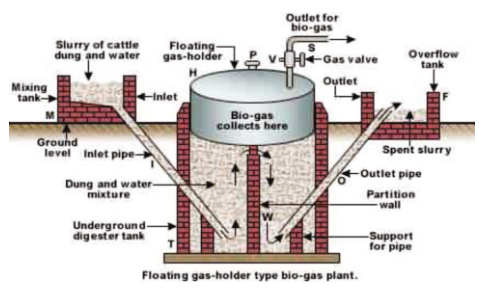

Floating gas-holder type bio-gas plant.

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

उपमंडल बंगाणा के तहत थानाकलां में बायो गैस प्लांट तथा मुच्छाली पंचायत में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने को मंजूरी मिल गई है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सभागार में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत आयोजित समीक्षा बैठक में इन दोनों योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद ऊना की अध्यक्षा सोमा देवी भरवाल ने की। उन्होंने बताया कि थानाकलां में बायो गैस प्लांट लगाने पर लगभग 8 लाख रुपये खर्च होंगे जबकि मुच्छाली ग्राम पंचायत में वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 50 लाख रुपये की लागत से तैयार होगा। इसके लिए भूमि का प्रबंध हो चुका है। सोमा देवी ने बताया कि अंब ब्लॉक की कुठेड़ा खैरला ग्राम पंचायत में भी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का प्रस्ताव है। समीक्षा बैठक के दौरान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों पर भी चर्चा हुई।

बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अरिंदम चौधरी, परियोजना अधिकारी एवं उपनिदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण राजेंद्र गौतम, जिला पंचायत अधिकारी रमन शर्मा, बीडीओ यशपाल, अभिषेक मित्तल, सोनू गोयल, हेम चंद, मनोज कुमार, उपनिदेशक कृषि सुरेश कपूर, जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. संजय मनकोटिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा ग्राम पंचायत मुच्छाली की प्रधान अनीता शर्मा भी उपस्थित रहीं।

गोल्डन कार्ड बनाने की तिथि 5 जुलाई तक बढ़ी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की अंतिम तिथि 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रमन शर्मा ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए पांच लाख रुपये तक के निशुल्क इलाज की सुविधा का प्रावधान है। अब तक ऊना जिला में 4 निजी अस्पतालों सहित कुल 15 अस्पताल इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उन्होंने बताया कि जो परिवार आयुष्मान में कवर नहीं हैं, उनके लिए प्रदेश ने हिमाचल हेल्थ केयर योजना (हिमकेयर) आरंभ की गई। इसके तहत जिला में 10,167 परिवार पहले से पंजीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि योजना के तहत पंजीकरण के लिए अंतिम तिथि 20 जून से बढ़ाकर 5 जुलाई कर दिया है। हिमकेयर के तहत गोल्डन कार्ड बनाने की सुविधा क्षेत्रीय अस्पताल के कमरा नंबर 100, फील्ड के स्वास्थ्य संस्थानों जिनमें अंब, हरोली, गगरेट, दौलतपुर चौक, चिंतपूर्णी, बंगाणा तथा आयुर्वेदिक अस्पताल ऊना और ईसपुर सहित जिला के समस्त लोक मित्र केंद्रों पर उपलब्ध है।

बिना पंजीकरण चल रहे होटलों पर गाज, पौने दो लाख जुर्माना ठोका, एक होटल सील

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

पर्यटन विभाग ने नियमों की अनदेखी करने वाले होटल चालकों पर बड़ी कार्रवाई की है। सोलन में पांच होटलों और तीन रेस्तरां को 1.75 लाख रुपये जुर्माना किया है। धर्मपुर - परवाणू के बीच एक होटल को सील करने के आदेश दे दिए हैं। यह सभी होटल पर्यटन विभाग की अनुमति के बगैर अवैध रूप से चल रहे थे। होटलों का पंजीकरण मेक माय ट्रिप और यो-यो पर तो था लेकिन विभाग के पास इन होटलों के संचालन की कोई जानकारी नहीं थी। पर्यटन विभाग ने यह कार्रवाई पर्यटक स्थल चायल और नेशनल हाईवे पर कंडाघाट, धर्मपुर व परवाणू में की है। इसमें होटल ट्रिप्पल ए का अवैध रूप से संचालन पाए जाने पर उसे सील करने आदेश दिए हैं। वहीं चायल में विलेज रिट्रीट और ए-कॉन होटल कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस वजह से इन दोनों को 19 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। कंडाघाट में पर्यटकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलने की शिकायत पर विभागीय टीम ने दबिश दी थी। यहां जांच के दौरान होटल के दो कमरे अतिरिक्त पाए गए। इस पर होटल मालिक को 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। धर्मपुर से परवाणू के मध्य हाईवे पर दो होटल अवैध रूप से संचालित पाए गए। इनमें से ज्यादा खामियों की वजह से एक होटल को सील करने के आदेश दिए गए। जबकि दूसरे को भारी जुर्माना लगाया गया है। जांच पड़ताल के दौरान पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने हाईवे पर बिना पंजीकरण चल रहे तीन रेस्तरां भी पकड़े हैं। इन सभी के खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पर्यटन विभाग की इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। विभाग ने जिला भर में चल रहे ऐसे होटल मालिकों को पंजीकरण की हिदायत दी है जो नियमों की अनेदखी कर रहे हैं। साथ ही भविष्य में भी इस तरह के अभियान जारी रखने की बात कही।

शूलिनी मेले के आखिरी दिन खरीदारी करने को जमकर उमड़ी भीड़

द रीव टाइम्स ब्यूरो सोलन, शिमला

शूलिनी मेले के अंतिम दिन स्थानीय और बाहरी राज्यों से हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ मेला देखने के लिए उमड़ पड़ी। इससे सोलन शहर में रौनक का आलम बना रहा। शहर के मुख्य द्वारा से लेकर मालरोड, राजगढ़ मार्ग और मेला स्थल ठोडो ग्राउंड में सजी दुकानों पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। झूलों पर झूलकर बच्चों और युवाओं ने खूब मनोरंजन किया। स्टॉलों पर बच्चों, महिलाओं और यहां तक की बुजुर्गों ने खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा। मेले के दौरान शहर में जगह-जगह कड़ी-चावल, राजमा-चावल, हलवा-पूरी, कुल्फी, समोसे के भंडारे में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। मेले में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इसमें हिमाचल, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा से आए पहलवानों ने भाग लिया। इस दौरान मैदान में नौणी विश्वविद्यालय, उद्यान विभाग, हिमाचल प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, आईटीआई, जिला उद्योग केंद्र, कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रदर्शनी में लोगों को जानकारी देने के साथ विभाग की लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया गया। इस प्रदर्शनी में कृषि विभाग के स्टॉल पर किसानों को जीरो बजट पर नेचुरल फार्मिंग करने के बारे में उपयोगी जानकारी दी गई। साथ ही, केमिकल, फर्टिलाइजर इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई।

कालाअंब से पांवटा के लिए कम होगा चार किलोमीटर का सफर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब से खजुरना वाया नागल-सकेती संपर्क सड़क का सुधार कार्य अंतिम चरण में है। लोक निर्माण विभाग की ओर से 15 किलोमीटर लंबी सड़क के एक तिहाई हिस्से पर टारिंग का कार्य पूरा हो चुका है। खजुरना से त्रिलोकपुर वाया नागल-सकेती-कालाअंब कुल 22 किलोमीटर लंबी सड़क को पक्का करने के लिए प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ 74 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है। इसमें खजुरना से कालाअंब 15 किलोमीटर और कालाअंब से त्रिलोकपुर सात किलोमीटर का भाग शामिल है। कालाअंब के नजदीक सकेती में स्थित एशिया का प्रसिद्ध शिवालिक जीवाश्म संग्रहालय भी इसी संपर्क मार्ग से जुड़ा है। लिहाजा, चार ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के साथ-साथ फॉसिल पार्क आने वाले पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस मार्ग को अब कालाअंब से पांवटा साहिब, देहरादून, मसूरी और हरिद्वार जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग किया जा सकेगा। ऐसे में कालाअंब-पांवटा राष्ट्रीय उच्च मार्ग - 07 पर भी यातायात में कमी आएगी। सड़क के मरम्मत कार्य के बाद राष्ट्रीय उच्च मार्ग - 07 की अपेक्षा लगभग चार किलोमीटर की दूरी भी कम होगी। कालाअंब - पांवटा साहिब नेशनल हाईवे की कुल दूरी लगभग 57 किलोमीटर है। जबकि, कालाअंब - खजुरना संपर्क मार्ग से ये दूरी 53 किलोमीटर है। उधर, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल शर्मा ने बताया कि खजुरना से त्रिलोकपुर वाया सकेती-कालाअंब संपर्क सड़क का निर्माण कार्य 70 फीसदी पूरा हो गया है। शेष कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर हल्के वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सूचना न देने पर जिला राजस्व अधिकारी को दो हजार जुर्माना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर। जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) बिलासपुर को राज्य सूचना आयुक्त ने समय पर सूचना न देने का दोषी पाते हुए दो हजार रुपये प्रार्थी को अदा करने के आदेश दिए हैं। डीआरओ को यह जुर्माना प्रार्थी मदन लाल शर्मा को दस दिन के अंदर देना होगा। फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल शर्मा ने कीरतपुर नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान अधिकृत की गई भूमि की धारा 3डी के हो जाने के उपरांत जब अर्जित की गई भूमि का तबदीली मलकीयत इंतकाल होकर तस्दीक हो जाता है और असल इंतकाल संबंधित तहसीलों में जमा हो जाते हैं, उसके उपरांत भू-अर्जन अधिकारी कार्यालय में नियुक्त तहसीलदार को इंतकाल में गलती पाए जाने पर उसकी दुरुस्ती करने की शक्तियां होती हैं या नहीं आदि के बारे में जानकारी मांगी थी। उसके बाद भी उक्त अधिकारी के कार्यालय से सूचना नहीं दी गई थी। इसके बाद प्रार्थी ने इस संबंध में राज्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील दायर की थी। राज्य सूचना आयुक्त ने मामले की सुनवाई के बाद डीआरओ बिलासपुर को दो सप्ताह के अंदर सूचना प्रार्थी को निशुल्क मुहैया करवाने के आदेश दिए थे लेकिन सूचना आयुक्त के आदेश के बाद भी डीआरओ बिलासपुर ने कई महीनों तक सूचना मुहैया नहीं करवाई।

बीमा उद्योग व वित्तीय क्षेत्र में निजीकरण का किया विरोध

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

उत्तरी जोन इंश्योरेंस इंप्लाइज एसोसिएशन मंडल शिमला का 13वां मंडलीय सम्मेलन हमीरपुर में शुरू हुआ। इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रदेश के 25 कार्यालयों में से 150 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन एसोसिएशन के अध्यक्ष कामरेड अनिल कुमार भटनागर ने किया। सम्मेलन को अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष कामरेड बीएस रवि, सीटू महासचिव डॉ. कश्मीर सिंह, एसोसिएशन के महासचिव कामरेड नवीन चंद, जोनल उपाध्यक्ष कामरेड आरसी शर्मा, कामरेड अनिल मनकोटिया, डीवाईएफाई राज्याध्यक्ष कामरेड अनिल मनकोटिया और पेंशनर एसोसिएशन से कामरेड एससी चौहान ने संबोधित किया। मंडलीय सचिव देवीदास ने बताया कि इस सम्मेलन में आगामी दो दिनों तक प्रदेश से आए सभी प्रतिनिधि केंद्र सरकार की ओर से बीमा उद्योग और वित्तीय क्षेत्र में किए जा रहे निजीकरण के विरोध और नई भर्ती आदि मांगों पर विस्तार से चर्चा होगी।

पेयजल कनेक्शन देते नियमों को भूला आईपीएच विभाग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

बल्ह बिहाल क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए उपमंडल बड़सर के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। हालांकि, अभी तक किसी भी युवा को उद्योग विभाग की ओर से प्लाट आवंटित नहीं किए जा सके हैं। अब इसी औद्योगिक क्षेत्र के लिए खुले में पाइपें बिछाकर पेयजल सप्लाई प्रदान करने की कोशिश आईपीएच विभाग कर रहा है। नियमों को ताक पर रख कर सड़क के ऊपर ही खुले में विभाग की ओर से पाइपें बिछा दी गई हैं। जिस पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। पेयजल पाइपों को भूमिगत करके पेयजल सप्लाई की जा सकती है, लेकिन आईपीएच विभाग नियमों को ताक पर रख खुले में पाइपें बिछाकर पानी की सप्लाई कर रहा है। सड़क के ऊपर डाली गई इन पाइपों के कारण दोपहिया वाहन चालक दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। लोगों ने विभाग से समस्या समाधान की मांग की है। इस संबंध में सहायक अभियंता अनिल शर्मा का कहना है कि समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा।

अब हाथ से नहीं एंड्रॉयड मोबाइल से करेगी पुलिस चालान

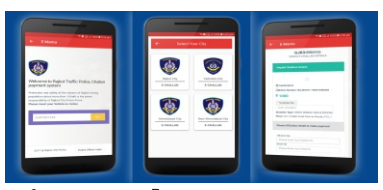

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगडा

यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिस अब हाथ से चालान नहीं करेगी। एंड्रॉयड फोन के साथ पुलिस ई-चालान करेगी। इसके लिए सरकार ने पुलिस को एंड्रॉयड फोन उपलब्ध करवा दिए हैं। इसमें ई-चालान की एप होगी और एप से ही चालान होंगे। मोबाइल पर गाड़ी का नंबर डालते ही एक क्लिक करते ही गाड़ी और चालक का पूरा डाटा उसमें आ जाएगा, जबकि गाड़ी के मालिक के पास चालान की रसीद एसएमएस से पहुंच जाएगी। प्रदेश पुलिस विभाग अब मोबाइल से ई-चालान एप से ही चालान करेगा। थाना प्रभारी से लेकर हवलदार तक यह एंड्रॉयड फोन पहुंच गए हैं। इसमें खास बात यह है कि यह मोबाइल गाड़ी चालक का पिछला रिकॉर्ड भी बता देगा कि उसका पहले चालान हुआ है कि नहीं। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। सब ई-चालान के जरिये पता चलेगा, जबकि गाड़ी का किस आधार पर चालान कटा है, उसका जुर्माना भी इस ई-चालान से लगेगा। उधर, डीएसपी पालमपुर अमित शर्मा ने कहा कि पुलिस अब ई-चालान के जरिये एंड्रायड मोबाइल से चालान काटेगी। इसमें एड्रांयड फोन से गाड़ी से लेकर चालक के लाइसेंस तक की सभी जानकारी मिल जाएगी। कितना चालान होगा यह भी एड्रांयड मोबाइल बताएगा, जबकि इसकी रसीद सीधे एसएमएस के जरिये वाहन मालिक के पास पहुंच जाएगी।

एंटी रेबिज इंजेक्शन न मिलने से लोग परेशान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगडा

सरकारी अस्पतालों में एंटी रैबीज की दवाई उपलब्ध न होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला के अधिकांश सरकारी अस्पतालों में वर्तमान में एंटी रैबीज की दवाई की उपलब्धता न के बराबर है। कुत्ते और बंदरों के काटने पर प्रयोग में लाए जाने वाले ये इंजेक्शन उपलब्ध न होने के कारण लोगों को टांडा मेडिकल कॉलेज में दस्तक देनी पड़ रही है। उन्हें टीएमसी में जाकर इंजेक्शन लगवाना पड़ा। लंघु गांव के जगदीश, रमेश और राधा देवी आदि का कहना है कि इंजेक्शन के उपलब्ध न होने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा है। डेढ़ साल से सरकार ने इस दवाई की उपलब्धता मात्र सरकारी अस्पतालों में ही रखने का निर्णय लिया था।

अस्पताल में दाखिल मरीजों को देखने भी नहीं गए डॉक्टर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगडा

हिमाचल मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के आह्वान पर चिकित्सकों की दो घंटे की पेन डाउन हड़ताल का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा। धर्मशाला अस्पताल में सुबह नौ बजे से पंजीकरण शुरू हुआ लेकिन ओपीडी में डॉक्टर न होने के कारण मरीजों को साढ़े 11 बजे तक इंतजार करना पड़ा। दूसरी ओर अस्पताल के वार्डों में दाखिल मरीजों को भी डॉक्टरों ने नहीं देखा। इसके कारण दाखिल मरीज व तामीरदार आपातकाल ओपीडी में ही चेकअप करवाने पहुंच गए जिन्हें बिना चेकअप के वापस वार्ड में भेजा गया। इसके अलावा धर्मशाला अस्पताल की सरकारी लैब में भी मरीजों के सैंपल कम ही लिए गए, क्योंकि लैब में सैंपल लेने का समय सुबह आठ बजे से साढ़े 11 बजे तक है। लेकिन साढ़े 11 बजे तक न ओपीडी, न ही वार्ड में किसी मरीजों की जांच हो पाई थी। इसके कारण जिन मरीजों को सैंपल देने के बारे में डॉक्टर ने लिखा था, बुधवार सुबह उन्हीं मरीजों से सैंपल दिए।

कामधेनु का खुला दूध 11 रुपये सस्ता मिलेगा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

जिले में दुग्ध कारोबार करने वाली कामधेनु हितकारी मंच ने दूध के दामों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोत्तरी कर दी है। दूध के बढ़े हुए दाम 25 जून से लागू कर दिए हैं लेकिन बढ़े हुए दामों के बावजूद भी कामधेनु का खुला दूध अन्य पैकेट बंद दूध से 11 रुपये सस्ता लोगों को मुहैया हो रहा है। खुला दूध अब 37 रुपये की बजाय लोगों को 39 रुपये लीटर मिलेगा। जबकि कामधेनु का पैकेट बंद दूध के दाम 46 रुपये लीटर हो गया है। जबकि शिमला में दूध के दाम 49 रुपये लीटर हुआ है। कामधेनु संस्था ने करीब अढ़ाई साल बाद अपने दूध के दामों में इजाफा किया है। बाहरी राज्यों की दुग्ध कंपनियों के दाम बढ़ाने के बाद जिले में दुग्ध कारोबार करने वाली सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी संस्था कामधेनु ने भी दूध के रेट में दो रुपये की बढ़ोत्तरी की है। इससे अब उपभोक्ताओं को खुला दूध 37 रुपये प्रति लीटर के बजाय 39 रुपये प्रति लीटर मिलेगा लेकिन उसके बाद भी कामधेनु का खुला दूध अन्य कंपनियों के दुध के मुकाबले 11 रुपये सस्ता लोगों को मिलेगा। खुला दूध संस्था केवल बिलासपुर व सोलन में भी बेचती है। कामधेनु संस्था बिलासपुर और सोलन जिला के गांव से दूध एकत्रित करती है। कामधेनु संस्था प्रतिदिन 28 हजार लीटर दूध एकत्रित करती है। इसके बाद 23 हजार लीटर दूध को बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, शिमला व सोलन के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है।

हर माह सफाई पर खर्च होंगे 4.30 लाख रुपये

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई। इस बार सफाई की जिम्मेदारी एक बार फिर से ठेकेदार विशाल कुमार निवासी सुजानपुर को सौंपी गई है। नई जिम्मेदारी को निभाने के लिए नए नियम एवं शर्तें भी लागू की गई हैं। नगर परिषद अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे तहसीलदार सुजानपुर अशोक पठानिया, नगर परिषद अध्यक्ष अशोक मेहरा, लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंता सुशील सोनी एवं नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष रमन भटनागर की अगुवाई में तमाम औपचारिकताएं पूरी करवाई गईं। नगर परिषद अधिकारी ने बताया सुजानपुर शहर की सफाई व्यवस्था जो 1 जुलाई से 30 मार्च 2020 तक रहेगी, उसके लिए टेंडर आवेदन का कार्य किया गया था। जिसे सुजानपुर निवासी विशाल कुमार को 4.30 लाख रुपये प्रतिमाह के तहत जारी किया है। नगर परिषद के पास 3 आवेदन पहुंचे थे। जिसमें सिंधूर सिंह चार लाख 35 हजार, महर्षि गवर्नमेंट कांट्रेक्टर देहरा चार लाख 95 हजार राशि के साथ जमा हुए थे। सुजानपुर के विशाल कुमार ने 4.30 लाख रुपये में काम करने के लिए सहमति जताई थी। सबसे कम दरें होने के चलते सफाई का जिम्मा विशाल कुमार को सौंपा गया है। इस बार सफाई कर्मचारियों में इजाफा किया गया है। पहले शहर की सफाई व्यवस्था ठेकेदार के करीब डेढ़ दर्जन कर्मचारी करते थे। वहीं इस बार यह संख्या ढाई दर्जन तक पहुंच गई है। दिन में दो बार कूड़ा इकठ्ठा करने के लिए तीन गाड़ियों का प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त 3 सफाई कर्मचारी तैनात रहेंगे।

मेडिकल कॉलेज व आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों के टेस्ट में आ रही परेशानी दूर करे प्रशासन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

मेडिकल कॉलेज और आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में मरीजों के टेस्ट न हो पाने के कारण मरीजों को जो परेशानी हो रही है, उसे तुरंत प्रभाव से अस्पताल प्रशासन दूर करने का प्रयास करे। हमीरपुर उपभोक्ता संरक्षण संगठन की हुई मासिक बैठक में यह मामला उठाया गया। सदस्यों ने कहा कि दूर-दूर से आने वाले मरीज खाली पेट टेस्ट करवाने के लिए आते हैं लेकिन, इन अस्पतालों की लैब में टेस्ट के लिए जरूरी केमिकल ही उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण मरीजों को निजी प्रयोगशालाओं में महंगे टेस्ट करवाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संगठन के प्रतिनिधियों ने हमीरपुर से सुजानपुर रोड पर बस स्टॉप नगर से बहुत दूर होने से लोगों, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को आ रही परेशानी से भी जिला प्रशासन को अवगत करवाने का निर्णय लिया है। आम लोगों से इस संदर्भ में शिकायत आई है कि बस स्टॉप बहुत दूर होने के कारण कई बार उनकी बस छूट जाती है। इसके लिए संगठन ने जिला प्रशासन को सुझाव देने का निर्णय लिया है कि बस स्टॉप के लिए हमीरपुर उपायुक्त कार्यालय के पास वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। संगठन में सदस्यों की ओर से शिकायत दर्ज की गई कि जिले की कुछ पंचायतों में कागज की प्लेट के इस्तेमाल पर पंचायत द्वारा जुर्माने लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में जिला प्रशासन से आह्वान किया गया है कि कागज की प्लेट और पॉलिथीन युक्त प्लेट पर प्रतिबंध की भ्रांति को दूर किया जाए।

तीन हजार मीटर दौड़ में मुंबई की साक्षी और जबलपुर की प्रार्थना बनी विजेता

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगडा

सिंथेटिक ट्रैक धर्मशाला में 50वीं केंद्रीय विद्यालय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंडर-19 वर्ग में 3000 मीटर दूरी दौड़ में मुंबई संभाग की भांडुप शिफ्ट-1 स्कूल की साक्षी राजे विजेता रहीं। वाराणसी संभाग के बीएचयू शिफ्ट-1 स्कूल की हर्षिता दूसरे स्थान पर रहीं। अंडर-17 में जबलपुर संभाग के जबलपुर सीओडी स्कूल की प्रार्थना जैन विजेता, वाराणसी संभाग के बीएचयू शिफ्ट की वर्षा उपविजेता, अंडर-17 लंबी कूद में एरनाकुलम संभाग की कंजिकोड़े स्कूल की पार्वती एम विजेता, गुड़गांव संभाग के चंडीमंदिर स्कूल नंबर-2 की प्रतिमा उपविजेता रहीं। अंडर-19 लंबी कूद में गुड़गांव संभाग के रेवाड़ी स्कूल की मनाली प्रथम, चेन्नई संभाग के आईलैंड ग्राउंड्स स्कूल की गीतहरुका जी उपविजेता, अंडर-19 रिले दौड़ में दिल्ली संभाग की मानसी, भाविका, पूजा, मानसी और बनदुनी को विजेता घोषित किया गया।

इसके अलावा अंडर-19 डिस्कस थ्रो में चंडीगढ़ संभाग के बरनाला स्कूल की जसकिरण कौर विजेता बनीं। प्रतियोगिता के पहले चरण में देश भर के 25 संभागों के 437 खिलाड़ी छात्राएं भाग ले रही हैं। बीते दिनों को अंडर-14, 17 और 19 आयु वर्ग के मुकाबले हुए।

नकल जमाबंदी लेने में लोगों को हो रही परेशानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगडा

परागपुर उपतहसील को सीधे उपायुक्त कांगड़ा कार्यालय के सर्वर के साथ तो जोड़ दिया गया है, लेकिन अपना सर्वर न होने की वजह से लोगों को ऑनलाइन अधूरी जानकारी ही मिल रही है। राजस्व विभाग की नकल जमाबंदी पर जमीन के खेवट, खतौनी और खसरा नंबर की जानकारी नहीं मिल पा रही है। बिना जानकारी के नाम पर सर्च करने से नकल जमाबंदी की जानकारी नहीं मिल पा रही है।इस पर परागपुर पंचायत प्रधान सुदेश कुमारी, उपप्रधान मदन गोपाल, अपर परागपुर पंचायत प्रधान मीना कुमारी, उपप्रधान सुरेश पटियाल, बणी पंचायत प्रधान ध्यान सिंह, उपप्रधान विनोद कुमार, गरली पंचायत प्रधान तिलक राज, उपप्रधान निखिल चौहान, सेहरी पंचायत प्रधान हंसराज भारद्वाज, उपप्रधान तरसेम कुमार, नाहन-नगरोटा पंचायत प्रधान बचित्र सिंह, उपप्रधान सूरज राणा, मनियाला पंचायत प्रधान अंजना, उपप्रधान नरेश कुमार, धजाग पंचायत प्रधान पुष्पा देवी, उपप्रधान शेर सिंह, नलसूहा पंचायत प्रधान मेहर चंद, उपप्रधान सुरिंद्र सिंह ने जिलाधीश कांगड़ा राकेश प्रजापति से आग्रह किया है।

सामार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

बसों में सीट न मिलने पर स्कूल नहीं पहुंच पा रहे विद्यार्थी, निकाली रोष रैली

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

बंजार बस हादसे के बाद प्रदेश में ओवरलोडिंग पर पुलिस और परिवहन विभाग ने शिकंजा कसा है। इससे कुल्लू जिले में छात्रों को स्कूल पहुंचने में परेशानी हो रही है। बसों में न बैठाए जाने से नाराज विद्यार्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।

पाहनाला व दोहरानाला क्षेत्र के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने विधायक सुंदर ठाकुर की अगुवाई में एक रोश रैली निकाली। इसके बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की। बसों में सीट न मिलने के कारण पाहनाला और दोहरनाला के अधिकतर विद्यार्थी कई दिनों से स्कूल नहीं जा सके। कई छात्रों को दस से 15 किमी सफर कर स्कूल पहुंचना पड़ता है। बसों में सीट टू सीट सवारियां बिठाने से उन्हें बस से उतारा जा रहा है। ऐसे में पाहनाला से कुल्लू पहुंचने में उन्हें काफी वक्त लग रहा है। एक बस बुधवार को पाहनाला के लिए आई। लेकिन इसमें आधे बच्चे ही आ सके, जबकि आधे से अधिक वहीं रह गए।

इसके बाद विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा और ढालपुर में आकर रोश रैली निकाली। विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। विद्यार्थी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि अतिरिक्त बसें रूटों पर चलाएं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने भी आश्वासन देते हुए कहा है कि जल्द ही समस्या का हल निकाला जाएगा।

कुल्लू के आठ अतिरिक्त रुटों पर चलेंगी बसें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिले में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आठ विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच कोठी -सोलंगनाला के लिए बस चलेगी। इसी प्रकार, दोपहर बाद 3.30 बजे से 5.30 बजे के बीच कोठी-सोलंगनाला के लिए हिमपनि हमीरपुर क्षेत्र की सुजानपुर से मनाली बस सेवा को 4.20 बजे कोठी-मनाली-कोठी के बीच चलाया जाएगा।

चालक प्रशिक्षण स्कूल बस के चालक को कुल्लू से कराल के लिए चक्कर लगाएंगे। लगघाटी की यदि बात की जाए तो थनोग से कुल्लू बस सेवा जो कुल्लू पांच बजे पहुंचती है, उसको शाम 5.30 बजे भेखली तक चलाया जाएगा। शाम 5 बजे संधोल से कुल्लू पहुंचने वाली बस को शाम 5.30 बजे भेखली तक चलाया जाएगा। पीज के लिए हिमानि केलरंग क्षेत्र की उदयपुर व दारचा से कुल्लू बस सेवाओं को शाम पांच बजे कुल्लू से पीज व वापस संचालित की जाएगी। शाम 5.30 बजे पठानकोट से कुल्लू पहुंचने वाली बस को शाम छह बजे चंसारी मार्ग पर पेच्छा तक चलाया जाएगा। इसी प्रकार कुल्लू सुबह चार बजे पहुंचने वाली शिमला-मनाली डीलक्स बस सेवा को सुबह 7.45 बजे कुल्लू से अरछंडी तक व वापस 8.30 बजे कुल्लू के बीच संचालित किया जाएगा। उपायुक्त डॉ. ऋचा वर्मा ने बताया कि इस संबंध में सभी डिपो संचालकों व चालकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से जिले के सभी स्थानों में बसों की समस्या को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में लोगों से भी सहयोग की अपील की है।

सेब पर स्कैब का हमला, बागवान चिंतित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू के कई क्षेत्रों में बगीचों में स्कैब का कहर बरपने लगा है। बताया जा रहा है कि अभी बीमारी का प्रकोप आंशिक रूप से फलों पर दिखाई दे रहा है। समय रहते सेब बगीचों में उपयुक्त दवा का छिड़काव नहीं किया गया तो जिले के करीब 700 करोड़ के सेब कारोबार पर संकट पड़ सकता है।

बागवानों की शिकायत के बाद प्रदेश सरकार ने डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी और उद्यान विभाग के वैज्ञानिकों को फील्ड में निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे सेब के रोग पर नियंत्रण किया जा सके। कुल्लू जिला के मणिकर्ण, लगघाटी, बंजार, आनी, सेउबाग, थरमाण, निरमंड आदि इलाकों में भी बीमारी का कहर बरपा है। बागवानों का कहना है कि अभी रोग कुछ सेब के दानों पर दिखा है। लेकिन समय रहते बीमारी का उपचार नहीं हुआ तो बड़ा नुकसान हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सेब के पौधों पर समय रहते फफूंदनाशक दवा का छिड़काव न होने के कारण कुल्लू के कई क्षेत्रों में आंशिक बीमारी का प्रकोप दिखा है। बताते है कि लंबे समय तक बारिश होने और तापमान नीचे गिरने के कारण सेब पर स्कैब ने हमला बोल दिया है। इसकी रोकथाम के लिए जितना जल्दी हो सके, इसके लिए फफूंदनाशक का छिड़काव करने की सिफारिश की जा रही है। उद्यान विकास अधिकारी उत्तम पराशर ने कहा कि स्कैब के रोकथाम के लिए हर ब्लाहक में बागवानों को कैंप के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है और दवा की जानकारियां मुहैया करवाई जा

दो दर्जन वाहनों के रुट परमिट रद्द करने की सिफारिश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

चंबा पुलिस ने ओवरलोडिंग करने पर दो दर्जन वाहनों के रूट परमिट रद्द करने की सिफारिश सक्षम अधिकारी को भेजी है। पिछले पांच दिनों से बंजारघाटी के बाद पुलिस ने ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है। इस अभियान के तहत पुलिस बसों सहित अन्य परिवहन वाहनों पर शिकंजा कसा। जिसमें ओवरलोडिंग की जा रही थी। पुलिस इन सभी वाहनों को चलाने वाले चालकों के लाइसेंस जब्त कर लिए। लाइसेंस और वाहनों के रूट परमिट को पुलिस ने रद्द करवाने के लिए सक्षम अधिकारी को भेजे हैं।

जिला कुल्लू के बंजार में हुए बस हादसे के बाद जिला पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है। इसके तहत परिवहन वाहनों में सीटों की क्षमता से अधिक सवारी बिठाने वाले ऑपरेटरों पर शिकंजा कस रही है। वाहन चालकों के लाइसेंस जब्त किए जा रहे हैं। चंबा पुलिस पांच दिनों में दो दर्जन परिवहन वाहनों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। पुलिस वाहन ऑपरेटरों पर कार्रवाई करने के साथ वाहनों में सफर करने वाले लोगों को भी जागरूक कर रही है।

जिससे लोग ओवरलोडिंग होने पर पुलिस को सूचना दें। ऐसा होने से जिले में वाहन दुर्घटनाएं काफी हद तक कम हो जाएंगी। पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका ने बताया कि पांच दिनों में पुलिस ने दो दर्जन परिवहन वाहनों के चालान काटे गए हैं। चालकों के लाइसेंस और वाहनों के रूट परमिट रद्द करने की सिफारिश पुलिस ने सक्षम अधिकारी से की है।

स्कूल बैग में चावल ढुलवाने के मामले पर प्रशासन ने शुरु की जांच

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

हिमाचल में चंबा जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे राशन ढुलवाया का मामला सामने आया। दरअसल भरमौर क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों ने राशन ढुलवाने के लिए बच्चों के बैग से किताबें निकलवाईं और उसमें चावल भरकर ढुलवाए।

मामले की सूचना जैसे ही स्कूल प्रबंधन समिति को मिली तो पदाधिकारियों ने इसका कड़ा विरोध किया और अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दूसरी ओर, भरमौर प्रशासन मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं।

भरमौर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगर ऐसा हुआ तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों जब बच्चे स्कूल गए तो शिक्षकों ने बच्चों से मिड डे मील का राशन ढुलवाने को कहा। बैग से किताबें खाली करवाईं और उसमें चावल भर दिए।

नन्हें बच्चों ने अध्यापकों का आदेश मानते हुए चावल ढोने का कार्य शुरू किया। इस दौरान बच्चों से कई बार बैग में चावल ढुलवाए गए। ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने एसएमसी अध्यक्ष को सूचित किया। स्कूल प्रबंधन समिति और अभिभावकों ने मौके पर पहुंचकर इसका विरोध किया।

स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हेम सिंह ने बताया कि बच्चों से स्कूल बैग में चावल ढुलवाए गए। उन्हें जैसे ही मामले की जानकारी मिली तो वे स्कूल पहुंचे। प्रशासन से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। एडीएम भरमौर पीपी सिंह ने बताया कि इस मामले के बारे में सूचना मिली है। जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर है तो शिक्षकों पर कार्रवाई होगी।

विद्युत परियोजना की सुरंग में फिर रिसाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पार्वती जल विद्युत परियोजना के तृतीय चरण की ओर से पांच करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी टनल की लीकेज दुरुस्त नहीं हो पाई है। बिहाली की पहाड़ी में परियोजना की हेड रेस टनल से फिर पानी का फुवारा फूट पड़ा है।

हाल ही में तीन माह बिजली का उत्पादन बंद कर टनल की मरम्मत की गई है। दो माह पहले काम पूरा कर सिउंड डैम में पानी का भराव शुरू किया गया था। टनल में पानी भरते ही बिहाली और सपांगनी की पहाड़ी से लीकेज शुरू हो गई थी। सोमवार देर शाम से यहां भारी मात्रा में पानी निकलना शुरू हो गया है। ऐसे में परियोजना का संचालन कर रही कंपनी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 520 मेगावाट की इस परियोजना में 2016 से बिजली उत्पादन को रहा है। लेकिन शुरूआती दौर में ही टनल से रिसाव होने से सैंज घाटी की जनता और परियोजना प्रबंधन दोनों को चिंता में डाल दिया था। पांच माह पूर्व परियोजना प्रबंधन ने उत्पाद बंद कर टनल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया था। साथ ही बिजली उत्पाद से होने वाले करोड़ों के मुनाफे से सरकार और कंपनी को वंचित रहना पड़ा। जानकारी के अनुसार बिजली उत्पादन बंद रहने से शेयर बाजार में भी एनएचपीसी का शेयर कमजोर हुआ था। कंपनी को बिजली उत्पादन में करीब 3.51 करोड़ इकाई और संयंत्र उपलब्धता फैक्टर में 6.9 फीसदी नुकसान झेलना पड़ा है। कंपनी को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग सीईआरसी की ओर से निर्धारित अंतरिम ठेके के आधार पर 24.04 करोड़ और सीईआरसी की ओर से अंतिम टैरिफ निर्धारण पर आधारित 30.14 करोड़ का नुकसान हुआ है। जनता ने भी परियोजना प्रबंधन पर सवाल उठाए हैं। सियुंड से लारजी तक की पहाड़ियों के भीतर बनी आठ किमी लंबी टनल में बिहाली गांव के पास फिर रिसाव होने से ग्रामीणों ने सुरक्षा की गारंटी देने की आवाज उठाई है।

जिले के आठ निजी स्कूलों को नोटिस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

जिले के निजी स्कूलों में बेशक छात्रों से मोटी फीस वसूली जा रही है। मगर सुविधाओं के नाम पर अभिभावकों को ठगा जा रहा है। इसका खुलासा हाल ही में हुए शिक्षा विभाग के निरीक्षण में हुआ है। इसको लेकर विभाग ने आठ स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें स्कूल प्रबंधनों को विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें राजनगर, सरोल और कियाणी क्षेत्र के स्कूल शामिल हैं। नोटिस जारी कर विभाग ने एक सप्ताह के भीतर स्कूल की खामियों दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार जिला उपशिक्षा अधिकारी की अगुवाई में बीते दिनों विभागीय टीम ने सरोल, राजनगर, भद्रम और कियाणी में औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान निजी स्कूलों में सुविधाओं को जांचा गया। इसमें निजी स्कूलों में कई खामियां पाई गई।

निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में शौचालय तक की सुविधा नहीं होने की बात सामने आई है। जबकि कई स्कूलों में तय मानकों के आधार पर कक्षाएं ही नहीं थी। यहां तीन कमरों में दो-दो कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा था। इसके अलावा योग्य अध्यापकों की कमी भी सामने आई। विभाग ने साफ किया है कि स्कूल प्रबंधनों ने ने आरटीई नियमों की अवहेलना की है। ऐसे में विभाग ने स्कूल प्रबंधकों को नोटिस जारी कर खामियों को दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। जिला उपशिक्षा अधिकारी ने कहा कि राजनगर, सरोल और कियाणी क्षेत्र के आठ निजी स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं। उन्होंने कहा कि सात दिनों के भीतर निजी स्कूल प्रबंधन आरटीई के नियमों को पूरा नहीं करते है तो स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा।

पंचायतीराज में ई-टेंडरिंग प्रणाली का प्रधानों ने किया विरोध

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चम्बा

पंचायतीराज में ई-टेंडरिंग प्रणाली के विरोध को लेकर पंचायत प्रधान संघ ने उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पंचायतों में ई टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय पंचायतों में लागू नहीं किया जाना चाहिए। पंचायतों में 60 प्रतिशत भाग स्थानीय मजदूरों के वेतन का तय किया है। लोक निर्माण और आईपीएच की तर्ज पर पंचायतीराज में ई टेंडरिंग प्रक्रिया जारी करने से ग्रामीणों को रोजगार के अवसर पर छिन जाएंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार फंड समय पर खर्च करने की आड़ में ई-टेंडरिंग को लागू कर रही है, जबकि फंड खर्च में विभाग स्वयं जिम्मेदार है। पंचायतों के एक जेई को एक दर्जन पंचायतें, तकनीकी सहायक को आधा दर्जन पंचायतें और जीआरएस को चार-चार पंचायतों का जिम्मा दिया है, जिसके चलते पंचायतों के काम अधिकारियों को समय न मिलने से बंद रहते हैं और आरोप प्रधानों पर जड़ा जा रहा है।

संघ ने पंचायतों में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की है। संघ ने इस नीति को तुरंत प्रभाव से बंद करने की मांग की है।

प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर नपेंगे कारोबारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मण्डी

प्लास्टिक का इस्तेमाल करके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का उल्लंघन किया गया तो व्यापारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह बात खाद्य आपूर्ति निगम सुरक्षा अधिकारी मंडी प्रताप ठाकुर ने नेरचौक में व्यापारियों के साथ बैठक में कही। उन्होंने व्यापारियों को कड़े निर्देश दिए कि नेरचौक और आसपास के घरों, दुकानों, बैंक, शिक्षण संस्थानों को अब सूखा और गीला कूड़ा अलग-अलग सफाई कर्मचारी को देना होगा। प्लास्टिक का इस्तेमाल हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह बंद है, लेकिन अभी भी कुछ व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं किया जाएगा। इस अवसर पर नेरचौक के व्यापारियों ने अपनी शिकायत में कहा कि वे गीला और सूखा कचरा किसे दें? क्योंकि कोई भी कर्मचारी उनसे कचरा लेने के लिए बाजार में आता ही नहीं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अल्सर – लक्षण, उपचार और कारण

- यद्यपि छोटी आंत और पेट में अल्सर हमारे आधुनिक समाज में सामान्य है, लेकिन इस बीमारी के लिए मुख्य कारण शराब, सिगरेट, खाने में अधिक मसालों का सेवन एवं फास्ट फूड और तनाव हैं। वैश्विक स्तर पर हर दस नागरिकों में से एक में जीवन के किसी बिंदु पर अल्सर की वजह से पेट दर्द के दौरान पीसने और जलने की उत्तेजना से पीड़ित होते हैं।
- पैपेटिक अल्सर पेट या डुओडेनम की सुरक्षात्मक अस्तर में ब्रेक या छेद होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो एंजाइम और एसिड से संपर्क में आते हैं जो पेट से छिपे होते हैं। यह देखा गया है कि पेट के अल्सर से डुओडनल अल्सर अधिक आम हैं। तुलनात्मक रूप से दुर्लभ, एसोफेजल अल्सर, जो एसोफैगस (निगलने वाली ट्यूब) में होते हैं, अक्सर अल्कोहल के दुरुपयोग या कुछ एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं और एंटीबायोटिक दवाओं जैसे दवाओं के संपर्क में आते हैं।
- अल्सर पर हाल के शोध में, अतिरिक्त पेट एसिड का स्राव वास्तव में इस बीमारी के विकास में एक भूमिका निभाता है। इसके अलावा, यह भी पाया गया है कि जीवाणु संक्रमण पैपेटिक अल्सर का मुख्य कारण है। फिर भी, 1980 के दशक के मध्य से चिकित्सा प्रमाण थे कि हेलिकोबैक्टर पिलोरी (एच. पिलोरी) बैक्टीरिया 80% से अधिक पेट अल्सर और 90% डुओडनल अल्सर में मौजूद है।

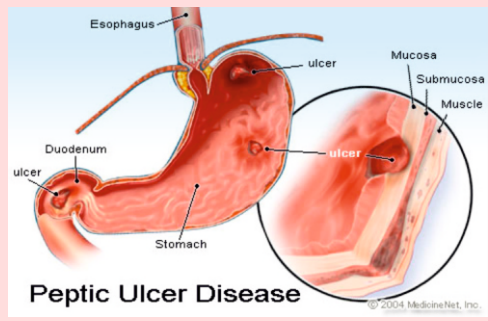

एक्सपर्ट क्या कहते हैं

- विशेषज्ञों ने यह भी देखा है कि ए ब्लड ग्रुप वाले लोग पेट के अल्सर से अधिक प्रभावित होते हैं, जो कभी-कभी कैंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह भी देखा गया है कि डुओडनल अल्सर अक्सर 'ओ' ब्लड ग्रुप वाले लोगों के साथ होता है। चूंकि इस रक्त समूह से पैदा होने वाले लोग अपने रक्त पर पदार्थ नहीं पैदा करते हैं, जो उनके डुओडेनम की अस्तर की रक्षा में मदद करता है।

हालांकि, इस बीमारी के बारे में अच्छी बात यह है कि पेप्टिक अल्सर का इलाज करना आसान होता है, और कई मामलों में एंटासिड्स और एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक हो सकता है।

- ऐसी कई दवाएं भी हैं जो पेट द्वारा उत्पादित एसिड की मात्रा को भी कम करती हैं।

तो यदि आप अल्सर से पीड़ित हैं, तो अपने चिकित्सक से परामर्श करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि इलाज न किए गए सभी अल्सर से एनीमिया और पेट कार्सिनोमा जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं।

इलाजः चिकित्सा पेशेवर द्वारा इलाज योग्य

निदानः चिकित्सा निदान की आवश्यकता है

लैब टेस्टः लैब टेस्ट आवश्यक है

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें- thenevtime@iirdshimla.org

कविता – कुटुम्ब वृक्ष

हे ! सर्जक
मेरे
ये कुटुम्ब वृक्ष
तेरा उजड़ चला - ये
बिखर चला
काल चक्र
के पाटों में
कोई पिस गया
कोई पीस चला ... ?
धराशाई सब

शाख़, टहनी, पात-दम्भ
मैं भी हूं
इसी में दबा- उफ्फ...
ये बोझ सब, मौन-गुम्म...

अस्तित्व की तलाश में
अपनी स्वाभाविक छवि और
पुनः सृजन की आस में
पुकार बस एक ही
न्याय अब-न्याय बस

न्याय ही .....?
निखरना किसे
बिखरना किसे.....?
हे! कुटुम्ब वृक्ष
सर्जक मेरे.....
शत् शत् नमन !
शत् शत् नमन !!

गिरीराज शर्मा
गांव धायला, डा० कालीहट्टी
शिमला, हि.प्र.

कानून की इस धारा के तहत मिल सकती है सजा-ए-मौत

हम अक्सर सुनते और पढ़ते हैं कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी यानी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या का दोषी पाया है। ऐसे में दोषी को सजा-ए-मौत या फिर उम्रकैद की सजा दी जाती है। लेकिन धारा 302 के बारे में अभी भी काफी लोग नहीं जानते।

आपको यहां बताते हैं कि क्या है भारतीय दण्ड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड और उसकी धारा 302

भारतीय दण्ड संहिता यानी Indian Penal Code, IPC भारत में यहां के किसी भी नागरिक द्वारा किये गये कुछ अपराधों की परिभाषा और दण्ड का प्रावधान करती है। लेकिन यह जम्मू एवं कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता (RPC) लागू होती है।

अंग्रेजों ने बनाई थी भारतीय दण्ड संहिता

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिश काल में सन् 1862 में लागू हुई थी। इसके बाद समय-समय पर इसमें संशोधन होते रहे। विशेषकर भारत के स्वतन्त्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दण्ड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, बरुनेई आदि में भी लागू कर दिया गया था।

भारतीय दंड संहिता की धारा 302

आईपीसी की धारा 302 कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कत्ल के आरोपियों पर धारा 302 लगाई जाती है। अगर किसी पर हत्या का दोष साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद या फांसी की सजा और जुर्माना हो सकता है। कत्ल के मामलों में खासतौर पर कत्ल के इरादे और उसके मकसद पर ध्यान दिया जाता है। इस तरह के मामलों में पुलिस को सबूतों के साथ ये साबित करना होता है कि कत्ल आरोपी ने किया है। आरोपी के पास कत्ल का मकसद भी था और वह कत्ल करने का इरादा भी रखता था।

कई मामलों में नहीं लगती धारा 302

हत्या के कई मामले मामलों में इस धारा को इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह ऐसे मामले होते हैं जिनमें किसी की मौत तो होती है पर उसमें किसी का इरादतन दोष नहीं होता। ऐसे केस में धारा 302 की बजाय धारा 304 का प्रावधान है। इस धारा के तहत आने वाले मानव वध में भी दंड का प्रावधान है।

भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 299 के अलावा धारा 300 में भी हत्या के मामलों को परिभाषित किया गया है। जिनका विवरण अदालती कार्रवाई के दौरान मिल जाता है। लेकिन हत्या के मामलों में धारा 302 को सबसे अधिक गंभीर और मजबूत मानी जाती है। जिसके तहत दोषी को दंडित किया जाता है।

एडवोकेट प्रदीप वर्मा
कानूनी सलाहकार, आईआईआरडी, 94180 25649

पाठकों के प्रश्न एवं कानूनी समस्याऐं सादर आमंत्रित है। आपके प्रश्नों के उत्तर हमारे कानून विशेषज्ञ ऐडवोकेट प्रदीप वर्मा अगले अंक में देंगे। प्रश्न हमारी मेल आई डी पर पूछे जा सकते है।

स्वच्छता क्यों और कैसे ?

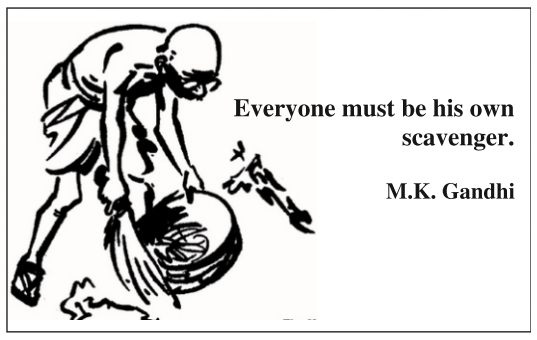

शारीरिक स्वच्छता

- शारीरिक स्वच्छता के विषय में हिन्दुस्तान का एक वर्ग तो ठीक तौर से ध्यान दे रहा है , पर साधारण जनता में इस विषय में अभी बहुत काम करना है।
- बच्चे की सफाई पर तो कई वर्गों में भी बहुत कम ध्यान दिया जाता है। बालक के खुद सफाई रखने के लायक होने के पहले उसके माँ-बाप उसे साफ-सुथरा रखने की फिक्र रखते हों, यह नहीं दिखाई देता ।
- नित्य स्नान करना चाहिए, इसे एक धर्म विशेष वर्ग का बहुत बड़ा भाग धार्मिक नियम की भाँति मानता है, पर इसे मानने वाला यही एक वर्ग है मात्र, यह नहीं कह सकते। दूसरे हिन्दुस्तानियों में रोज नहाने की आदत आम नहीं है। हिन्दुस्तान में रोज नहाना स्वच्छता और साथ ही आरोग्य के लिए आवश्यक है।
- नहाने का मतलब सिर्फ बदन गीला कर लेना नहीं है। बहुतेरे नित्य नहाने वाले इससे आगे नहीं बढ़ते। नहाने के माने हैं शरीर का मैल साफ करके त्वचा के छिद्रों को खोल देना। अतः नहाने का पानी पीने के पानी जितना ही साफ होना चाहिए। ऐसा पानी काफी मात्रा में रोज न मिल सके, तो गंदे पानी में नहाने की बनिस्बत साफ पानी में कपड़ा भिगोकर उससे शरीर को रगड़कर पोंछ डालना कहीं अच्छा है। हमारे देश के गाँवों में ही नहीं, बड़े-बड़े कस्बों में भी लोग जैसे पानी से नहाते हैं, उसे नहाने लायक नहीं कह सकते।
- कपड़ों की सफाई भी शारीरिक स्वच्छता का ही भाग है। कपड़ों की गंदगी का कारण केवल दरिद्रता ही नहीं कही जा सकती। बहुतेरी गंदगी तो अच्छी आदतें न पड़ी होने से और आलस्य के कारण रहती है।

साफ-सुथरी आदतें

- शारीरिक स्वच्छता के सिवा और भी साफ-सुथरी आदतें डालने की ज़रूरत है। इनके अभाव में हम उन लोगों के दिलों में नफरत पैदा करते हैं, जिनकी आदतें साफ-सुथरी हैं।
- हमारी आँखों को ऐसा अभ्यास होना चाहिए कि वे गन्दगी को देखकर खामोश न रह सकें। इसका अर्थ यह नहीं है कि गंदगी को देखकर हम वहाँ से खिसक जाऐं, बल्कि फौरन उस गन्दगी को दूर करने का उपाय करें।

साफ-सुथरी आदतें लगाने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए

- पानी लिए बिना पाखाने नहीं जाना चाहिए।
- पानी के पानी के मटके में डुबोने को अलग बरतन रखना चाहिए। जूठा बरतन तो उसमें कदापि न डालना चाहिए। मटके के पास इस तरह खड़े रहकर पानी नहीं पीना चाहिए कि पानी के छींटे मटके पर पड़ें।
- जहाँ बहुत से लोगों के लिए पीने का एक ही बरतन हो, वहाँ प्याले या गिलास को मुँह से लगाकर पानी पीना अनुचित है। ऊपर से पीने की आदत डालनी चाहिए और जो इस तरह न पी सकें, उन्हें अपना बरतन अलग रखना चाहिए या चुल्लू या अंजली से पीना चाहिए।

बाह्य-स्वच्छता

- जहाँ-तहाँ थूकने, मल-मूत्र त्याग करने, कूड़ा फेंकने और उसे इकट्ठा होने देने की आदत हिन्दुस्तान के गाँव, शहर, तीर्थक्षेत्र, रास्ते, नदी, तालाब, धर्मशाला, स्टेशन, रेल, जहाज वगैरह को कलंकित कर डालती है।
- इस आदत की जड़ में अस्पृश्यता समायी हुई है। आदमी जहाँ रहेगा, वहाँ गंदगी के निमित्त तो पैदा होंगे ही। पर हिन्दुस्तान के स्पृष्य वर्गों ने खुद गंदगी साफ करने के काम को हलका समझकर और उस परोपकारी काम के करने वालों को अस्पृष्य मानकर, जहाँ वे नहीं जा सकते वहाँ से गंदगी को नियमित रीति से दूर करने के बदले इकट्ठी करने का रिवाज डाल रखा है और अस्पृष्यों से सहयोग न करके मत्थे इतना ज्यादा काम मढ़ दिया है, जो उनके किए हो नहीं सकता । परिणामस्वरूप देश में अनेक प्रकार के उपद्रवों को बसा रखा है और आम इस्तेमाल के स्थानों को ऐसा बना दिया है कि देखकर रोऐं भी खड़े हो जाऐं ।

शौच

- सड़क पर पाखाना फिरने की आदत तो हर्गिज नहीं होनी चाहिए । खुली जगह में लोगों के देखते पाखाना फिरना, बल्कि बच्चों तक को फिराना असभ्यता है।
- इसलिए प्रत्येक गाँव में पाखाने बनवाने चाहिए और उन्हें नियमित रूप से रोज साफ कराना चाहिए। भारत सरकार का पूरा प्रयास ही इस ओर है।

जलाशय

- तालाब, कुएँ और नदी का पानी साफ रहे, इस ओर ग्राम-पंचायतों और ग्राम-सेवकों को खूब ध्यान देना चाहिए।
- जलाशयों की आज की स्थिति बहुत शोचनीय है। तालाब में ही बरतन साफ किए जाते हैं, नहाया और कपड़ा धोया जाता है, मवेशी भी उसी में पानी पीते हैं, नहाते है और पड़े भी रहते हैं, उसमें बच्चे और बड़े तक आबदस्त लेते हैं। उसके पास की जमीन पर तो मल-त्याग करते ही हैं। यही पानी पीने, खाना पकाने के काम में लाया जाता है। यह सब पाप माना जाना और बन्द होना चाहिए।
- गाँव के तालाब/बावड़ियों के चारों ओर बाँध बना देना चाहिए, जिससे मवेशी उसमें न जा सकें और उसके नजदीक खेल (लम्बी हौज) पशुओं के पानी पीने को बनाना चाहिए।
- इसी प्रकार कपड़े धोने के लिए तालाब के पास एक टंकी होनी चाहिए और उस पर ऐसी पक्की जगह बना देनी चाहिए, जिससे उसका पानी फिर तालाब में न पहुँचकर दूर निकल जाय।

इस तरह पानी को दूर ले जाने के लिए घर, कुएँ आदि के समान बनी हुई नालियों में काई और घास-पात जम जाता है। उनमें से बदबू निकलती है और मच्छरों को बढ़ने की जगह मिलती है। अतः इन नालियों की सफाई पर निरन्तर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्हें रोज कूँचे से रगड़कर साफ कर देना चाहिए।

CAN HIMACHAL BECOME LIQUOR FREE STATE?

प्रधान संपादक की कलम से.....

The practice of government machinery to keep people in illusion is not new and the country has been witnessing the same for long. Political parties used to keep on fueling the burning social issues and seek public support to resolve such issues. However, there is little change in the thought of the newly emerging leadership unlike Pakistan where any political party wins in the name of making Kashmir free from India, seriousness of making the country or state progressive is reflected. However, the outcome depends upon the dynamism of the leadership. The voters of the country are also gradually becoming more awakened. But the problem lies somewhere else. In fact, the country is getting distortion, not because of the mischievous thoughts of the people with ugly attitude, but because of the silence of the good people. Majority of the reasonable and genuine people Just change their route when encountered with some social irritants and remain busy in their own affairs while keeping on cursing the system which is left to its fate for manipulation by the so called clever class managing all affairs.

In its role to manage finance for the development of the state, the government tries to mobilise the resource as per available avenues apart from loans from international bodies. One of the prominent sources of the revenue collection (in case of Himachal Pradesh) is the revenue from the auction of the Liquor shops which counts to more than 5% of the total estimated annual revenue collection of the state (as per budget 2019-20).

As it is an established fact that our society has culture of getting highly intoxicated in drink parties. Majority of the crimes and quarrels are result of the drinking parties. Apart from this, the consumption of heavy doses of liquor create individual health hazards and further disturb family life besides extra pressure on the hospitals.

Ironically, there are many campaigns run by the government on drug addiction and awareness against wine and others. IIRD through Mission RIEV has also completed first phase of the state wide "say no to drugs" campaign during the year 2018 as its voluntary action.

Recently there was a case of removing wine shop set up in front of a Satsang Ashram in Shimla.

Despite people's agitation and dharna pradarshan, the government did not wind up the wine shop until got removed by the nature's intervention in shape of heavy landslide.

There are usually dharnas especially by the women to remove the wine shops from their villages but the success rate of such dharnas is very low.

This is just like creating problem and then working towards its remedies. This is unfortunate part that the government machinery tries to earn by sale of wine. It is yet to be understood that whether government needs well-being of the people or revenue. Wine with well-being objective cannot travel together. If the revenue generation is the only objective, why should not we allow the opium and cannabis grower to earn money publically, which few are still doing it silently. Why should not the wine makers in villages be licensed to produce and sell wine publically and pay tax to the government. Let government declare wine making as SME. By issuing licenses to sell the red wine produced by big industrialists through big machineries and treating culprits for suing the poor people producing wine through conventional methods, the government is bringing disparity to support the rich and harass the poor. This dilemma will always remain.

Why should not government ban on the sale of the liquor in the state and make the state "Liquor Free". But such action requires political will and exceptional dare in the people in governance which is yet to be witnessed by the people of Himachal Pradesh.

कच्ची घाटी में आश्रम के पास ठेके का विरोध
लोगों ने की दूसरी जगह खोलने की मांग, कहा, आश्रम में सत्संग के लिए आते हैं सैकड़ों श्रद्धालु
रातों रात टीन के ढारे में खोल दिया ठेका, सुबह लोग भड़के
कच्चीघाटी में सत्संग भवन के गेट के साथ खोल दिया शराब का ठेका
ठेके के विरोध में सड़कों पर
कच्ची घाटी में शराब पर बवाल
ठेके के विरोध में महिलाओं सहित सड़कों पर उतरे ग्रामीण
ठेका खुलने पर भड़के कच्चीघाटी के लोग
कच्चीघाटी में ठेका खुलने के विरोध में प्रदर्शन
धार्मिक संस्थानों के आसपास भी सरकार खुलवा रही है शराब के ठेके, जन विरोध भी सरकार की नींद नहीं जगा पाता

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

जीवन के लिए घातक है शराब ....जानें कुछ रोचक तथ्य

प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया और तेज कर दी। इसी युद्ध को जीतने के बाद **East India Company** का एक अफसर फ्रांसिस ब्रेकन भारत आया जिसने बंगाल को लूटने में कंपनी की सहायता की, वह ब्रिटेन वापिस गया और समय-समय पर संसद में होने वाली बहस में हिस्सा लेता रहता था। एक ऐसी ही बहस में, जिसमें मुद्दा था कि भारत के चारित्रिक पतन की प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं, उसने हिस्सा लिया। भारत भूमि में जन्मा व्यक्ति कोई श्री कृष्ण तो कोई, श्री राम, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, कोई ऋषि मुनि, तो कोई क्रान्तिकारी बन जाता है। चूँकि भारत सांस्कृतिक और अध्यात्मिक धरातल पर बेहद शक्तिशाली राष्ट्र है इसलिए वे उसे तोड़ने में कुछ खास तो नहीं कर पाये हैं परंतु इस विशालकाय मजबूत दीवार में एक छोटे से छेद के तौर पर उन्होंने बंगाल में एक शराब का ठेका खुलवा दिया है। उसने आगे कहा कि 1760 से पहले भारत में कोई शराब नहीं पीता था। 1760 के बाद उन्होंने शराब की पहली दुकान का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया। ब्रेकन ने ठेकेदार से पूछा कि क्या भारतीय शराब पीते थे तो उसने जवाब दिया कि नहीं!

क्यों नहीं पीते थे? ठेकेदार बोला उसके 3 कारण हैं: भारतीयों के लिए शराब पीने का मतलब अपना धर्म भ्रष्ट करना है। भारत की जलवायु उन्हें शराब पीने से रोकती है। शराब सबसे तुच्छ पेय है जो मनुष्यों के लिए नहीं है। इस शराब की दुकान की कई अन्य शाखाएं कुछ ही सालों में पूरे बंगाल में खुल गयीं। यह वार्ता है सन् 1832 की जिसमें ब्रेकन ठेकेदार से हुई बातचीत के अंश प्रस्तुत कर रहा है। ठेकेदार से आगे पूछने पर पता चला कि भारतवासी अब कितनी शराब पी रहे हैं? जवाब मिला कि इस दुकान के पिछले मालिक तक यहाँ सिर्फ अंग्रेज ही आकर शराब पीते थे लेकिन अब यहाँ भारतीयों की भरमार है। इन्होंने कब से इतनी शराब पीनी शुरू कर दी और क्यों? ठेकेदार बोला कि इनके चरित्र तो ऊंचे थे परंतु ये हमारे बहकावे में फँस गए हमने इन्हें तरह तरह के लालच देकर इनकी वासना को अग्नि दी जिसके कारण ये ठेकों की तरफ आकर्षित हैं। आरम्भ में भारतीय चोरी छिपे पीते थे और बाद में धीरे धीरे ये खुले आम होता चला गया। आज मंजर यह है कि शराब न पीने वाला नास्तिक समझा जाता है। हमारा अधिकांश युवा समुदाय इसकी चपेट में है। 1832 तक भारत में शराब की 350 दुकानें थीं और जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए तब भारत में 1500 शराब के ठेके थे। एक अनुमान के मुताबिक आज ऐसी करीब 30 हजार दुकानें हैं। ये तो वैध दुकानें हैं, अवैध दुकानें इनसे भी ज्यादा हैं। हर मोहल्ले में एक ठेका आपको मिल जाएगा। दूध मिले न मिले पर शराब आपको मिल ही जाएगी। शराब पीकर आदमी बेटी, बहु, बहन और पत्नी में अंतर भूल जाता है 98 से 100 फीसदी बलात्कार शराब के नशे में होते हैं और इनका लाइसेंस आज भी सरकार से ही मिलता है। अंग्रेज ये बात जानते थे कि शराब देवता को दानव बनाने में देर नहीं लगाती, इसीलिए उन्होंने सबसे पहला काम हमें तोड़ने की दिशा में जो किया वह था शराब का हमसे परिचय। गोरे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने की नीति बनाई और सरकार उसी नीति का पूर्ण निष्ठा से पालन कर रही है। भारत में लगभग 80 करोड़ लीटर शराब पैदा की जाती है, लगभग 5–7% भारतवासियों में शराब की ऐसी बुरी लत है कि वे उसके बिना जी नहीं सकते।

साभार : फेसबुक पेज सनातनधर्म महाधर्म

कार्यस्थलों पर शोषण का ख़ात्मा कब होगा...

आदमी की शक़्ल में भेड़ियें सड़कों से कार्यस्थलों तक लार टपकाना कब करेंगे बंद

——— मनु के भारत में रोज़ शर्मसार होती नारी

यत्र पुज्यंते नारी रमंते तत्र देवता.....कहावत है, कहावत में ही ठीक लगती है। देश में नारी अस्तित्व का अपना एक स्वर्णिम इतिहास है जिसे आज की लार टपकाती पुरुष प्रधान कुंठित और हवस संचित समाजिक सोच से तहस-नहस किया जा रहा है। पैदा होती बच्चियां उधेड़ी जा रही हैं तो सड़क पर महिलाओं को खेलने की वस्तु समझने वालों की भी एक लंबी भीड़ है। लेकि़न सबसे बड़ी समस्या में एक तो ये भी है कि महिलाओं के सशक्तिकरण का ढोल पीटने वाले समाज में आज कार्यस्थलों पर सेवाऐं दे रही महिला कर्मचारियों एवं अधिकारियों तक को किसी न किसी प्रकार के शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। कार्यालयों में बैठे इन वहशी सोच के दरिंदों को न तो क़ायदे-कानून की फिक्र है न ही मर्यादाओं की समझ। ऐसे में एक महिला जो किसी भी घर-परिवार का आधार स्तंभ है, नौकरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है । उसे कार्यालयों में अपने शीर्ष अधिकारियों अथवा साथ काम करने वालों की शारीरिक एवं सांकेतिक प्रताड़ना सहने के लिए विवश होना पड़ता है ।

ऐसी ख़बरों की बहुतायत रोज़ सूर्खियां बनती है जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं को इस प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। यहां प्रश्न यह है कि कुछ महिलाऐं तो इसका विरोध करती हैं लेकि़न अधिकतर अपनी नौकरी और अपमान को देखते हुए आगे नहीं आ पाती है जिससे अकारण ही ये सब सहना पड़ता है। सरकार की भूमिका इसमें यदि केवल नियम बनाने तक सीमित है तो क्या उन नियमों पर अमल की कोई उम्मीद रखी जानी चाहिए ? यहां सरकार का पक्ष भी नाउम्मीदों को जन्म देता है। क्योंकि यदि वरिष्ठ अधिकारियों के पास कोई इस प्रकार की शिकायत आती भी है तो उस पर कोई ठोस अथवा पारदर्शी कार्यवाही होगी...इसमें शंका ही रहती है ।

मुझे याद है एक घटना जो कि किसी विभाग के एक ऐसे अधिकारी की है जिसने अपने ही विभाग की एक कर्मचारी को मानसिक एवं अन्य प्रकार की प्रताड़ना करने के लिए हमेशा परेशान किया। इतना ही नहीं कार्यालय दूर-दूर होने के बावजूद वो अधिकार महिला कर्मचारी को उनके कार्यालय में बेवक्त ही रोज़ पहुंचकर मानसिक प्रताड़ना देता रहा । इस प्रकार के अनैतिक व्यवहार से वो महिला मानसिक रुप से परेशान रहने लगी और परिवार और नौकरी में सामजस्य बिठाना उसके लिए मुश्किल सा हो गया। क्योंकि वो अधिकारी कभी भी उनके कार्यालय में पहुंच जाता और कभी भी फोन पर तंग करने से बाज नहीं आता था। इससे वो महिला कर्मचारी ही नहीं बल्कि उनका परिवार भी परेशान हो गया । और उस महिला कर्मचारी को परामर्श केन्द्रों और दवाईयों की सहायता लेनी पड़ी। एक महिला के लिए उसका सम्मान और निर्भिक जीवन बहुत मायने रखता है लेकि़न उस नीची सोच के अधिकारी ने इस प्रताड़ना को जारी रखा। महिला के शिकायत करने के बाद भी वो अधिकारी बाज नहीं आया और न ही उच्च अधिकारियों ने इस पर कोई भी

कार्यवाही की। उस महिला से स्वयं मैंने जब बात की तो वो और उनका परिवार इस बात से परेशान थे कि उस अधिकारी को किस प्रकार सबक सीखाया जाए जबकि उस पर शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होती है । यहां प्रश्न यह है कि जो मानसिक प्रताड़ना उस अधिकारी के कारण महिला कर्मचारी को हुई है, उसकी भरपाई क्या इस प्रकार के लोलुप अधिकारी से की जा सकती है ? क्या ऐसे अधिकारियों पर ठोस कार्यवाही करते हुए उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए ?

ऐसे ही एक अन्य संस्थान में एक घटना में मुझे स्वयं भी शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ा क्योंकि वहां भी महिला कर्मचारी से स्टाफ देर रात तक काम लेता था तथा एक दिन कुछ इस प्रकार की घटना हो जाती है कि महिला कर्मचारी अपने कार्यालय में जाने से भी डरती है । क्या इस प्रकार के माहौल में महिलाओं को कार्यस्थल पर शोषण हमें नीचता ही हदों से बाहर नहीं ले जा रहा है ? क्या 21वीं शताब्दी के भारत में महिलाओं को कहने की आज़ादी है और जब वास्तविकता से सामना हो तो उन्हें हवस की गंदी आंखों का सामना क्षण-प्रतिक्षण करना पड़ेगा ? क्या इस प्रकार हम आधी आबादी को सुरक्षित करने के खोखले वायदों को निभाने में पौरुष का परिचय देंगें ? यह बेहद शर्मनाक है।

भारत को विश्व में पहले से ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई शर्मनाक तमके मिल चुके हैं। यहां तक कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भारत को सुरक्षित नहीं माना जाता है। इस पर जो फज़ीहत होती रही है उससे कई बार हमें वैश्विक स्तर पर शर्मसार होना पड़ा। जिस आधी आबादी को हम बराबरी का हक़ देने की बात करते हैं उसे इस प्रकार यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, इस पर मंथन करना आवश्यक हो जाता है। जहां तक सरकार की बात है तो समय-समय पर कानून और नियमों में महिलाओं को

सुरक्षा की गारंटी की फुलझड़ियां छोड़ दी जाती है। अमल के नाम पर कुछ अधिक उम्मीदें बांधना ग़लत ही होगा। कार्यस्थल पर तनावमुक्त माहौल और प्रताड़ना से सुरक्षा हेतु विधेयक पास किया गया जिसके अंतर्गत शिकायतों का निपटारा 90 दिनों के भीतर किया जाना है। प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों पर 50 हज़ार का जुर्माना लगाने की व्यवस्था है । इस विधेयक में घर में काम करने वाली सहायिकाओं को भी शामिल किया गया है ।

देश में 'मी टू' अभियान ने बड़े-बड़ों की पोल जब खोली तो कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें आरोप लगे कि किस प्रकार महिलाओं का यौन शोषण किया जाता रहा है। अब इसमें सबकी ओर से कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय हो सकता है लेकि़न धुंआ उठने का तात्पर्य आग लगने से ही होता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि कार्यस्थल पर कार्य करने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है तथा इस बात को सुनिश्चित बनाने में भरसक प्रयास कढ़ाई से लागु किए जा रहे हैं कि कोई भी इस प्रकार घटना घटित न हो। साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देकर इसे सरकार की प्राथमिकता कहा। तो क्या प्रधानमंत्री की ये बाद आज हुबहू लागु भी हो रही है। कार्यस्थलों पर अथवा इसके दायरे से बाहर भी महिलाओं के शोषण के मामलों में कमी तो दिखाई नहीं दे रही है । निचले स्तर से उपरी स्तर तक कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी नैतिकता को ताक पर रख कर महिलाओं को अपनी गंदी सोच के कारण प्रताड़ित करने से बाज नहीं आते । ऐसी विक्षिप्त सोच के लोगों पर कानून का कोई असर नहीं होता क्योंकि उन्हें मालूम है कि महिला या तो सामाजिक डर और निंदा के कारण या तो शिकायत ही नहीं करेगी अथवा शिकायत होने पर कार्यवाही न के बराबर ही होनी है ।

महिलाओं को हमारा कानून दस्तावेज़ों में कई महत्वपूर्ण शक्तियों से नवाज़ता है। इन कानून को जानना आज महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। महिला अपनी शिक़ायत को दर्ज़ करवा सकती है। यदि वो थाने में नहीं जाना चाहती है तो डाक द्वारा भी अपनी शिक़ायत को प्रेषित कर सकती है। यदि महिला अपना नाम नहीं बताना चाहती तो भी शिक़ायत दर्ज़ होगी। गोपनीयता के लिए महिला अकेले महिला पुलिस अधिकारी अथवा दंडाधिकारी के पास ब्यान दर्ज़ करवा सकती है। यदि लोकलाज या निंदा की चिंता कर महिला चुपचाप कार्यस्थल अथवा अन्यत्र इस शोषण को सहती रही तो आने वाले समय में असुरक्षा का ऐसा माहौल तैयार होगा कि इसे रोकना दस्तावेज़ी कानूनों के बस की बात नहीं रह जाएगी ।

ये भी रखें ध्यान.....कार्यस्थल पर प्रोटेक्शन

वर्क प्लेस पर भी महिलाओं को तमाम तरह के अधिकार मिल हुए हैं। सेक्शुअल हैरेसमेंट से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थीं। इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइंस तमाम सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में लागू है। इसके तहत एंप्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वह गुनहगार के खिलाफ कार्रवाई करे ।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिशानिर्देश बनाए हैं। एंप्लॉयर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी की ड्यूटी है कि वह सेक्शुअल हैरेसमेंट को रोके। सेक्शुअल हैरेसमेंट के दायरे में छेड़छाड़, गलत नीयत से स्पर्श करना, सेक्शुअल फेवर की डिमांड या आग्रह करना, महिला सहकर्मी को पॉर्न दिखाना, अन्य तरह से आपत्तिजनक व्यवहार करना या फिर इशारा करना आता है। इन मामलों के अलावा, कोई ऐसा ऐक्ट जो आईपीसी के तहत ऑफेंस है, की शिकायत महिला कर्मी द्वारा की जाती है, तो एंप्लॉयर की ड्यूटी है कि वह इस मामले में कार्रवाई करते हुए संबंधित अथॉरिटी को शिकायत करे।

कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि विक्टिम अपने दफ्तर में किसी भी तरह से पीड़ित-शोषित नहीं होगी। इस तरह की कोई भी हरकत दुर्व्यवहार के दायरे में होगा और इसके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। प्रत्येक दफ्तर में एक कंप्लेंट कमिटी होगी, जिसकी चीफ महिला होगी। कमिटी में महिलाओं की संख्या आधे से ज्यादा होगी। इतना ही नहीं, हर दफ्तर को साल भर में आई ऐसी शिकायतों और कार्रवाई के बारे में सरकार को रिपोर्ट करना होगा। मौजूदा समय में वर्क प्लेस पर सेक्शुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए विशाखा जजमेंट के तहत ही कार्रवाई होती है। इस बाबत कोई कानून नहीं है, इस कारण गाइडलाइंस प्रभावी है। अगर कोई ऐसी हरकत जो आईपीसी के तहत अपराध है, उस मामले में शिकायत के बाद केस दर्ज किया जाता है। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई होती है।

बहरहाल, महिलाओं के प्रति इस दुर्व्यवहार और सोच को बदलने की आवश्यकता है। महिलाओं को भी अपने अधिकारों के प्रति सजग रह कर अपने प्रति हो रही हर ग़लत हरक़त का विरोध करना होगा। विशेषकर कार्यस्थल पर इस प्रकार की प्रताड़ना का पुरजोर विरोध एवं उचित तरीके से उसका प्रतिकार कानून का सहारा लेकर सबक सिखाने की आवश्यकता है।

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

हिमाचल में शिशु मृत्यु दर घटी, पर लिंगानुपात बिगड़ा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश में शिशु मृत्यु दर घटी है, जबकि लिंगानुपात बिगड़ गया है। नीति आयोग के 'हेल्थ इंडेक्स जून 2019' में तीन साल के अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यहां शिशु मृत्यु दर जहां 1000 शिशुओं पर तीन घट गई है, वहां पांच साल तक के बच्चों पर यह 6 तक घटी है। हालांकि लिंगानुपात की बात करें तो 1000 लड़कों के अनुपात में अध्ययन वर्ष तक 917 लड़कियां पैदा हो रही हैं, जबकि इससे तीन साल पहले यह आंकड़ा 924 था। इस तरह से इस आंकड़े के अनुसार सात लड़कियां पैदा होनी और कम हो गई हैं।

इस रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में जहां आधार वर्ष 2015–16 में शिशु मृत्यु दर 1000 शिशुओं पर 19 थी, वहीं यह संदर्भ वर्ष 2017–18 में घटकर 16 रह गई है। पांच साल तक के बच्चों की मृत्यु दर भी जहां पहले 33 थी, अब यह 27 रह गई है। आधार वर्ष 2015–16 में जहां एक हजार लड़कों पर 924 लड़कियां पैदा हो रही थीं, वहीं संदर्भ वर्ष 2017–18 में 7 लड़कियों की गिरावट दर्ज की गई है। यह लिगांनुपात एक हजार लड़कों पर 917 लड़कियों का रह गया है। यह रिपोर्ट नीति आयोग ने देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मानकों पर जारी की है। प्रति व्यक्ति राज्य सकल घरेलू उत्पाद और संदर्भ वर्ष के कंपोजिट इंडेक्स स्कोर में भी हिमाचल टहप 10 राज्यों में शामिल है। हिमाचल प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। एसपेरेंट्स, अचीवर्स और फ्रंटरनर्स की तीन श्रणियों में इन राज्यों को रखा गया है।

हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इस दिन से शुरु होंगी मानसून की छुट्टियां, अधिसूचना जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 जून से दो अगस्त तक मानसून की 38 छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छुट्टियों के शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। बीते साल 25 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां हुई थीं। सरकार ने इस साल छुट्टियों में एक-दो दिन का बदलाव किया है।

कुल्लू जिला के स्कूलों में 23 जुलाई से 14 अगस्त तक 23 दिनों की मानसून छुट्टियां रहेंगी। शीतकालीन स्कूलों में 22 से 27 जुलाई तक छह दिनों की मानसून ब्रेक होगी। बीते कुछ दिनों से मानसून ब्रेक को लेकर असमंजस बना हुआ था।

मार्च महीने में निदेशालय ने 25 जुलाई से 31 अगस्त तक छुट्टियां करने की अधिसूचना जारी करने के बाद वापस ले ली थी। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि मानसून ब्रेक कब से होगी।

अधिकांश शिक्षक संघ अगस्त महीने के दौरान छुट्टियां करने के पक्ष में थे। संघ के पदाधिकारियों का तर्क था कि अगस्त महीने में ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में स्कूलों को बंद करना पड़ता है।

बॉन्ड तोड़ बाहरी राज्यों में सेवाएं दे रहे 34 डॉक्टर, 15 बर्खास्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बॉन्ड तोड़कर अच्छे पैकेज के लिए बाहरी राज्यों में सेवाएं दे रहे 15 डॉक्टरों को सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। पीजी करने के बाद 34 डॉक्टर बाहरी राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी को हिमाचल लौटने का नोटिस दिया है, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर 15 को बर्खास्त कर दिया है जबकि अन्य के मामलों में छानबीन जारी है। सरकार ने साफ किया है कि अब इन डॉक्टरों को प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।

हिमाचल में डॉक्टरों के पीजी करने पर लाखों रुपये खर्च होते हैं। इन डॉक्टरों ने हिमाचल में पीजी की और वरिष्ठता समेत अन्य वित्तीय लाभ लेकर बॉन्ड तोड़कर बाहरी राज्यों में चले गए। नियमों के मुताबिक पीजी करने के बाद डॉक्टरों को पांच साल तक हिमाचल में सेवाएं देनी होती हैं। उन्हें हिमाचल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि पीजी करने के बाद डॉक्टरों को रोकना आवश्यक हो गया है। डॉक्टर बाहर न जाएं, इसके चलते नियम कठोर किए जा रहे हैं।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई में रोड शो आयोजित

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बीते दिनों दुबई में सी.आई.आई, हिमाचल चैप्टर के सहयोग से रोड शो आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में निवेश की अपार संभावनाएं विद्यमान है तथा सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने उद्यमियों से आगे आकर इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस समारोह का आयोजन इंडियन बिजनेस एण्ड प्रोफेशनल कहउंसिल (आई.बी.पी.सी) द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पास राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रतिष्ठित संस्थान विद्यमान हैं जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश में बेहतर प्रशिक्षित एवं शिक्षित मानव संसाधन शक्ति उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, मेडिकल व मैनेजमैंट कहलजों की काफी संख्या होने के कारण यह प्रदेश उद्योग जगत की जरूरतों के अनुसार कुशल मानव शक्ति की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देशी और विदेशी पर्यटकों द्वारा देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य है और यह आगंतुकों को मनोरंजन के लिए एडवेंचर, वाईल्ड लाईफ, ईका-टूरिज्म, हेरिटेज, धार्मिक एवं आध्यात्मिक तथा स्किइंग आदि सभी प्रकार के अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस प्रदेश को एक सत्त पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है ताकि हिमाचल को भविष्य में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर एक बेहतरीन स्थल बनाया जा सके।

उद्योग मंत्री ब्रिकम सिंह ने यू.ए.ई में रह रहे विभिन्न राज्यों के भारतीयों की अपने देश के सत्त विकास के प्रति भावनाओं की सराहना की। उन्होंने यू.ए.ई में भारतीय व्यापारिक समुदाय को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए उनका आह्वान किया कि वे यहां निवेश करके राष्ट्र के विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में अपना योगदान दें।

हिमाचल में पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति के लिए बनेगा नियम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति को लेकर सरकार नियम को अंतिम रूप देगी। प्रदेश में पंचायत सचिवों की सीधी भर्ती को नियुक्ति नियम को फाइनल किया जाना है।

पंचायत सचिवों की शैक्षणिक योग्यता और भर्ती प्रक्रिया को भी तय किया जाएगा ताकि यह प्रक्रिया आरंभ की जा सके।

अभी तक तदर्थ और अनुबंध आधार पर प्रदेश में पंचायत सचिव तैनात होते रहे हैं। सरकार ने पंचायत सचिवों की स्थायी नियुक्ति को लेकर रूल को अंतिम रूप देने से पहले प्रभावितों से एक माह के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

राज्य सरकार ने प्रकाशित राजपत्र में रूलों को अंतिम रूप देने की अधिसूचना जारी की है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज रूल 2019 में जिला परिषदों में पंचायतों सचिवों की नियुक्ति नियमों अंतिम रूप दिया जाना है। राज्य सरकार समय-समय पर पंचायत सचिवों के पदों को भरने के लिए मंजूरी देगी। स्थायी पंचायत सचिवों का वेतनमान 5910–20200 जमा 1900 ग्रेड पे और दो साल के बाद 13300–34800 जमा 3200 ग्रेड पे दी जाएगी। अनुबंध पंचायत सचिव को 5910 जमा 1900 कुल 7810 प्रति माह वेतन मिलेगा। पंचायत सचिव पद के लिए उम्र 18 से 45 साल होनी चाहिए।

जो पंचायत सचिव अनुबंध या तदर्थ आधार पर लगे हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वर्ग के लिए इस पद के वास्ते तय सीमा के अनुसार छूट के हकदार रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता स्नातक या एमबीए होना चाहिए। टाइपिंग गति अंग्रेजी 30 शब्द और हिंदी 25 शब्द प्रति मिनट हो। स्थायी नियुक्ति वाले पंचायत सचिवों का दो साल की प्रोबेशन अवधि रहेगी। 77 फीसदी सीधी भर्ती अनुबंध आधार पर होगी और तीन फीसदी ग्रामीण विकास विभाग में एमबीए से सीधे भर्ती करेगा। आवेदक हिमाचल का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

यह नियुक्ति हिमाचल प्रदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से की जाएगी। इनको नेशनल पेंशन स्कीम से जोड़ा जाएगा। इस नियुक्ति और अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दी जाएगी। नियुक्ति के बाद सरकार से अनुबंध करना होगा।

मुख्य सचिव का एडीबी मिशन टीम से एचपी शिवा को शीर्ष पूर्ण करने का आग्रह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एशियन विकास बैंक (एडीबी) मिशन टीम ने परियोजना अधिकारी सुनेई किम के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल, बागवानी, सिंचाई तथा वैल्यू एडिशन परियोजना (एचपी शिवा) के तहत मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल के साथ बीते दिनों बैठक की।

सुनेई किम ने मुख्य सचिव को बताया कि इस परियोजना के तहत प्रदेश में 20 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अमरूद, अनार, लिची तथा नींबू प्रजाति के फलों की उच्च घनत्व सब ट्रॉपिकल फसलें लगाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के तहत आरंभ में प्रदेश के बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी तथा कांगड़ा जिलों में विभिन्न फसल मॉडलों के लिए 15 प्रायोगिक उप-परियोजनाओं तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की पांच उप-परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा।

परियोजना अधिकारी ने मुख्य सचिव से आग्रह किया कि एचपी शिवा के तहत चयनित खण्डों में सभी रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए ताकि परियोजना का कार्यन्वयन सुचारू रूप से किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में जल उपभोक्ता संघ को प्रभावशाली बनाने के लिए एक नीति तैयार करने को भी कहा।

मुख्य सचिव ने परियोजना अधिकारी को सभी मुद्दों पर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया तथा वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारियों से निष्ठा से काम करने को कहा। उन्होंने परियोजना अधिकारी से प्रोजेक्ट कंसैप्ट पेपर तथा प्रोजेक्ट रेडिनेस फार्नेसिंग को पूर्ण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया तथा बताया कि प्रदेश इस परियोजना को लागू करने के लिए खास रुचि रखता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर का सपना है। एडीबी मिशन के एसोसिएट परियोजना अधिकारी कृष्ण रोटेला, एचपी शिवा परियोजना निदेशक डॉ. एम.एम. शर्मा, उप निदेशक देवेन्द्र ठाकुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इस दिन से शुरु होंगी मानसून की छुट्टियां, अधिसूचना जारी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हिमाचल के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 26 जून से दो अगस्त तक मानसून की 38 छुट्टियां रहेंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छुट्टियों के शेड्यूल की अधिसूचना जारी कर दी है। बीते साल 25 जून से 31 जुलाई तक छुट्टियां हुई थीं। सरकार ने इस साल छुट्टियों में एक-दो दिन का बदलाव किया है।

कुल्लू जिला के स्कूलों में 23 जुलाई से 14 अगस्त तक 23 दिनों की मानसून छुट्टियां रहेंगी। शीतकालीन स्कूलों में 22 से 27 जुलाई तक छह दिनों की मानसून ब्रेक होगी। बीते कुछ दिनों से मानसून ब्रेक को लेकर असमंजस बना हुआ था।

मार्च महीने में निदेशालय ने 25 जुलाई से 31 अगस्त तक छुट्टियां करने की अधिसूचना जारी करने के बाद वापस ले ली थी। इससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि मानसून ब्रेक कब से होगी।

अधिकांश शिक्षक संघ अगस्त महीने के दौरान छुट्टियां करने के पक्ष में थे। संघ के पदाधिकारियों का तर्क था कि अगस्त महीने में ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में स्कूलों को बंद करना पड़ता है।

बीते साल भी कई जिलों में उपायुक्तों ने भारी बारिश के चलते स्कूलों को बंद किया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने शिक्षक संघों की मांग की जगह पुरानी व्यवस्था को ही बरकरार रखते हुए हल्का बदलाव किया है।

हिमाचल के एक मात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में बढ़ेंगी 15 सीटें

द रीव टाइम्स ब्यूरो

डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रदेश के एक मात्र सरकारी डेंटल कॉलेज में 15 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के भेजे गए प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।

डीसीआई ने प्रस्ताव अब केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया है।

प्रदेश के छह मेडिकल कॉलेजों में इसी सत्र से 720 एमबीबीएस की सीटें भरी जा रही हैं। शिमला स्थित डेंटल कॉलेज में 60 छात्रों के चल रहे बैच में भी 15 और सीटें बढ़ाने को मंजूरी मिलने युवाओं को अधिक मौका मिलेगा।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. रवि चंद ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को दस फीसदी आरक्षण इसी सत्र से लागू करने के केंद्र और प्रदेश सरकार के फैसले के बाद सरकार ने आरक्षण लागू होने से किसी अन्य वर्ग को नुकसान न हो, इसलिए अलग से सीटें बढ़ाकर आरक्षण सुविधा देने का फैसला लिया था।

एमबीबीएस कोर्स में 120 अतिरिक्त सीटें भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों कोर्स में सीटें बढ़ने से प्रदेश के युवाओं का लाभ होगा।

मुख्य सचिव ने की सड़क सुरक्षा स्थिति की समीक्षा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल ने बीते दिनों परिवहन, पुलिस तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ प्रदेश में सड़क सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने परिवहन तथा पुलिस विभाग द्वारा की जाने वाली वाहनों की जांच की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि पुलिस तथा परिवहन विभाग चालान करने की प्रक्रिया को सख्त बनाए। उन्होंने कहा कि ओवर-लोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाना, तेज गति व लापरवाह ढंग से गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते हुए मोबाईल का इस्तेमाल, सीट बेल्ट न लगाना तथा गाड़ी चलाते हुए म्युजिक स्सिटम चलाने से सम्बन्धित उल्लंघनों को रोकने पर बल देना चाहिए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

बी.के. अग्रवाल ने निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा अभियान में ओवर-लोडिंग पर बल देने के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम को किसी स्थान पर फंसे हुए लोगों को परिवहन का अन्य विकल्प प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए तथा आमजन को किसी भी प्रकार की मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने हिमाचल पथ परिवहन निगम को निर्देश दिए कि वर्तमान में अक्रियाशील पड़ी सभी 99 जेएनएनयूआरएम बसों को शीघ्र क्रियाशील किया जाए तथा इस संबंध में प्रतिदिन रिपोर्ट दी जाए।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

ICC World Cup 2019: इयोन मोर्गन ने रचा इतिहास, जड़े 17 छक्के

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने छक्कों का एक विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इयोन मोर्गन वनडे मैच की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। इयोन मोर्गन ने अफगानिस्तान के विरुद्ध अपनी पारी का 17वां छक्का लगाते ही विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप 2019 के 24वें मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन ने अफगानी कप्तान गुलबदीन नईब की गेंद पर अपनी पारी का 17वां छक्का लगाते ही एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इयोन मोर्गन ने 57 गेंदों में शतक बना दिया। इसमें 3 चौके और 11 छक्के शामिल थे।

44 साल पहले 25 जून के दिन ही लगी थी इमरजेंसी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत में 25 जून 1975 की आधी रात को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। ये दिन भारत के इतिहास में कभी भी ना बदलने वाला दिन बन गया हैं। भारत में 21 माह तक आपातकाल लगा रहा। भारत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक आपातकाल था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1975 में इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली करने का दोषी पाया था। उसके बाद उन पर 6 सालों तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने कोर्ट के इस फैसले को इंकार कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की घोषणा की।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कैसे हुई, भारत के नाम दर्ज रिकॉर्ड

द रीव टाइम्स ब्यूरो

योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग न केवल आपके शरीर को रोगों से दूर रखता है बल्कि आपके मन को भी शांत रखने का काम करता है। योग एक प्राचीन कला है जिसकी उत्पत्ति भारत में करीब 5000 साल पहले हुई थी। पहले समय में, लोग अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान, पूरे जीवनभर स्वस्थ और ताकतवर बने रहने के लिए किया करते थे। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। भारत ने पहले योग दिवस पर दो शानदार रिकॉर्ड भी बनाए थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन 35 हजार से ज्यादा लोगों के साथ राजपथ पर योग किया था। पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के साथ योग करना और दूसरा रिकॉर्ड 84 देशों के लोगों द्वारा इस समारोह में हिस्सा लेना।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इन प्रतिबंधों से ईरान के सर्वोच्च नेता और अन्य अधिकारी अमेरिकी क्षेत्र में किसी भी बैंकिंग सुविधा के लाभ नहीं उठा पाएंगे। ईरान ने कहा था कि उसने 20 जून 2019 को क्षेत्र में अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया गया है जिसके कुछ दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नए प्रतिबंध लगाने का कदम उठाया है। हाल के दिनों में ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने साल 2018 में ईरान परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया था। अमेरिका ईरान पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाता रहा है।

कारगिल युद्ध के 20 साल : वायुसेना ने ग्वालियर हवाई अड्डे को 'युद्ध थियेटर' में बदला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय वायुसेना ने 24 जून 2019 को ग्वालियर हवाई अड्डे को एक युद्ध थियेटर में तब्दील कर दिया है। इस दौरान जम्मू और कश्मीर के द्रास - कारगिल क्षेत्र में टाइगर हिल हमले का एक प्रतिकात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया। इसमें साल 1999 में हुए अभियान की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का नाटकीय रूपांतरण पेश किया गया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ थे। भारतीय वायुसेना ने युद्ध के 20 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हवाई अड्डे पर कई गतिविधियों की योजना बनाई है और टाइगर हिल हमले का प्रतीकात्मक 'रूपांतरण' उनमें से एक है। हवाई अड्डे पर स्थित प्रदर्शनी में पांच मिराज 2000, दो मिग 21 और एक सुखोई 30 एमकेआइ तैनात किया गया है

जी-20 शिखर सम्मेलन: जापान पहुंचे पीएम मोदी, इन मुद्दों पर करेंगें चर्चा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री मोदी जी 20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 26 जून 2019 की रात रवाना हुए। पीएम मोदी जी 20 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद और प्रमुख वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर सकते हैं। वह इस सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण बहुपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगे। जापान के ओसाका में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जिन देशों के साथ दस द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वो फ्रांस, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका और तुर्की हैं. इसके साथ ही, ब्रिक्स यानि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका और रिक अर्थात रूस-चीन-भारत के नेताओं के बीच बैठक होगी।

बीजेपी सांसद ओम बिड़ला बने 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष, पीएम मोदी ने दी बधाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो

बीजेपी नेता ओम बिड़ला ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कोटा में कांग्रेस उम्मीदवार रामनारायण मीणा को हराया था। उन्होंने रामनारायण मीणा को 2.5 लाख से भी ज्यादा वोटों से हराया था। लोकसभा स्पीकर के लिए बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के नाम चर्चा में थे।

इसमें मेनका गांधी, राधामोहन सिंह, एस. एस. आहलूवालिया, वीरेंद्र कुमार और रमापति त्रिपाठी का नाम शामिल था। ओम बिरला का जन्म 04 दिसंबर 1962 को कोटा राजस्थान में हुआ था। ओम बिरला वर्तमान में कोटा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से 17वीं लोकसभा के सांसद हैं।

ओम बिरला अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वे अपने राजनीतिर सफर के दौरान नेशनल कोल इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली और नेहरू युवा केन्द्र, नई दिल्ली के डायरेक्टर रह चुके हैं।

अब बैंकों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

केंद्रीय बैंक की वेबसाइट पर शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की शुरुआत की गई है। आरबीआई का इसके पीछे मकसद समय से शिकायतों को हल कर ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाना है। इस सिस्टम के लॉन्च होने के बाद बैंक ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। उन्हें हर हाल में शिकायत पर कार्रवाई तय समय में करनी होगी। किसी भी शिकायत का समाधान तय समय में होगा। आरबीआई इस बात को सुनिश्चित करेगा कि शिकायत का हल तय समय में निकले और बैंक उस पर कार्रवाई ले। अगर समस्या का निवारण तत्काल नहीं हुआ तो फिर आरबीआई के नियम के तहत उसमें संबंधित बैंकर या कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीएमएस को लॉन्च करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि यह एप्लीकेशन पारदर्शिता को और बेहतर बनाती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे ताकतवर व्यक्ति चुना गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री मोदी कों ब्रिटिश हेराल्ड ने एक रीडर्स पोल में 2019 का सबसे ताकतवर शख्स चुना है। इस रीडर्स पोल में मोदी ने विश्व के अन्य नेताओं जैसे व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग को पीछे छोड़कर यह स्थान हासिल किया है। इस सूची में विश्वभर की 25 से अधिक शख्सियतों को शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर ब्रिटिश हेराल्ड मैगजीन के जुलाई संस्करण के कवर पेज पर भी प्रकाशित की जाएगी। यह संस्करण 15 जुलाई को प्रकाशित होगा। ब्रिटिश हेराल्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित लेख के अनुसार पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी को भारतीयों की ओर से बेहद ज्यादा अप्रूवल रेटिंग्स मिली हैं।

एमपी सरकार ने गौरक्षा के नाम पर हिंसा पर 5 साल जेल के प्रस्ताव को दी मंजूरी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गाय के नाम पर होने वाली हिंसा पर रोक लगाने हेतु गोवंश वध निषेध अधिनियम 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार, गो हिंसा निरोधक अधिनियम के तहत यदि कोई शख्स हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो उसे छह महीने से लेकर तीन साल की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही उस पर 25,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा।

रत ने परमाणु सक्षम मिसाइल पृथ्वी-दो का सफल परीक्षण किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने हाल ही में सेना द्वारा उपयोग में लाये जाने के संदर्भ में प्रयोग के तौर पर परमाणु सक्षम पृथ्वी-दो मिसाइल का ओड़िशा तट के परीक्षण रेंज से सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के लांच कॉम्प्लेक्स-तीन से किया गया। इस मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल सतह से सतह तक मार करने वाली है। यह परीक्षण सेना के यूजर ट्रायल का हिस्सा है। पृथ्वी-दो का 21 फरवरी 2018 को भी चांदीपुर में आईटीआर से सफल परीक्षण किया गया था। यह मिसाइल 500/100 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है। यह तरल प्रणोदन दो इंजनों द्वारा संचालित है।

चमकी बुखार का कहर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार के कारण भयावह स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने हाल ही में मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एसकेएमसीएच) का दौरा किया था और ये भरोसा दिलाया कि इस बीमारी से निपटने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि साथ ही लोगों को बीमारी के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। चमकी बुखार से पीड़ित मासूमों की सबसे ज्यादा मौतें रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच अस्पताल में हुई हैं। वहीं चमकी बुखार अब मोतिहारी तक पहुंच गई है, जहां एक बच्ची बुखार से पीड़ित है. पूर्वी चम्पारण जिले में भी चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। इस बीमारी से 1 साल से 15 साल की उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं।

आरबीआई डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इस्तीफा दिया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विरल आचार्य ने अपने निर्धारित कार्यकाल से छह महीने पहले इस्तीफा दे दिया है। आचार्य की नियुक्ति तीन साल के लिये हुई थी। विरल आचार्य को तीन साल के कार्यकाल के लिए 23 जनवरी 2017 को आरबीआई में शामिल किया गया था। उनका तीन साल का कार्यकाल जनवरी, 2020 में पूरा होना था। इससे पहले आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने दिसंबर 2018 में निजी कारण बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।

जेपी नड्डा बने BJP के कार्यकारी अध्यक्ष

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की संसदीय बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष बने रहेंगे। भाजपा संसदीय बोर्ड ने जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष चुना है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा राज्यसभा के सदस्य हैं। जेपी नड्डा का जन्म 02 दिसंबर 1960 को पटना, बिहार में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा और बीए की पढ़ाई पटना से हुई। उन्होंने एलएलबी की डिग्री हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से हासिल की। वे पहली बार साल 1993 में हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए थे। बीजेपी ने साल 2012 में जेपी नड्डा को राज्यसभा सांसद बनाया था।

फेसबुक ने लॉन्च किया 'लिब्रा' क्रिप्टोकरेंसी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फेसबुक ने हाल ही में 'लिब्रा' क्रिप्टोकरेंसी को लॉंच किया। इस कदम के पीछे कंपनी का मुख्य उद्देश्य एक लो कॉस्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम बनाना है, जो स्मार्ट डिवाइसेज के जरिए उपलब्ध हो सके। इस क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कंपनी के विश्व भर में मौजूद दो सौ करोड़ यूजर्स कर सकेंगे। फेसबुक लिब्रा को अगले साल (2020) लॉन्च करेगी। इसे नई ग्लोबल करेंसी करार दिया गया है। फेसबुक को भरोसा है कि वो लिब्रा से लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद करीब 100 करोड़ डॉलर की कमाई कर लेगी। कंपनी के अनुसार, इससे वो लोग भी व्यापार कर सकेंगे जिनका बैंक खाता नहीं है या फिर वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फेसबुक ने कहा की लिब्रा की वैल्यू यूएस डॉलर, यूरो या फिर अन्य करेंसियों के समकक्ष होगी।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

मोदी-ट्रंप की मुलाकात, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

जापान के ओसाका में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बैठक हुई। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत की बधाई दी और कहा कि भारत व अमेरिका अच्छे दोस्त हो गए हैं।

बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि आपको आम चुनावों में जीत की बधाई। आप इस जीत के योग्य हैं। आप शानदार काम कर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। हम भारत के साथ अमेरिका की दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त बन गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का धन्यवाद करते हुए कहा कि हम लोकतंत्र और शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा मंत्र सबका साथ-सबका विकास का है। हम मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत के प्रति प्रेम जताने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

FATF प्रमुख ने टेरर फंडिंग के मुद्दे पर पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने के दिए संकेत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आतंकवाद की फंडिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अध्यक्ष मार्शल बिलिंग्सले ने पेरिस में बैठक के बाद आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के मुद्दे पर पाकिस्तान को काली सूची में डालने के संकेत दिए हैं।

एफएटीएफ प्रमुख मार्शल बिलिंग्सले ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान ने जून 2018 में एक कार्ययोजना पर सहमति जताई थी लेकिन इस पर वह खरा नहीं उतरा। इस बारे में पाकिस्तान को फरवरी में चेतावनी दी गई थी। वह कार्ययोजना के अंतर्गत जनवरी तक के लिए निर्धारित अधिकांश लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाया था। इसके बाद उसने आग्रह किया था कि वह आतंकी फंडिंग की बाबत मई तक के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों को हासिल कर लेगा। लेकिन वह अपने वादे पर एक बार फिर खरा नहीं उतरा। मार्शल बिलिंग्सले ने कहा कि यदि पाकिस्तान कार्ययोजना को अंजाम देने में असफल होता है तो संस्था उस पर अगली कार्रवाई पर विचार करेगी। उन्होंने इस बात की भी पड़ताल की है कि पाकिस्तान कार्ययोजना को पूरा में कितना पीछे है। जांच में पाया गया कि वह इस पर काम करने में बेहद पीछे है। पाकिस्तान को इस साल सितंबर तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी होगी।

अमेरिकी शहरों में 'अतुल्य भारत' भारतीय सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों का रोड शो

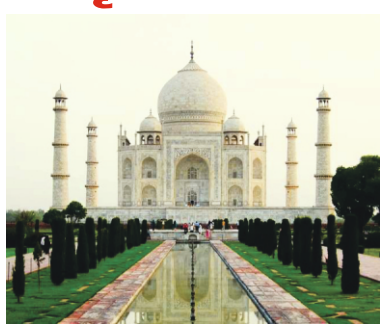

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत-अमेरिका के बीच कनेक्टीविटी सुविधाजनक होने के साथ ही अमेरिकी पर्यटकों को लुभाने के लिए अतुल्य भारत के विभिन्न सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को दर्शाते हुए विभिन्न अमेरिकी शहरों में रोड शो आयोजित किया जा रहा है। बीते दिनो चार दिवसीय रोड शो का आयोजन उद्योग जगत के हितधारकों के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा कराया गया है। डायरेक्टर जनरल मीनाक्षी शर्मा ने कहा, 'रोड शो से यह संकेत मिला है कि अमेरिकियों के बीच भारत को लेकर काफी उत्साह है वे मेडिकल पर्यटन समेत यहां के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने के लिए तत्पर हैं।' मीनाक्षी शर्मा अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को, सिएटल, बोस्टन, वाशिंगटन डीसी और कनाडा के वैंकुवर में भारतीय पर्यटन प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं।

हर साल औसतन 1.2 मिलियन अमेरिकी पर्यटक भारत आते हैं। टूरिज्म विभाग ने इसे हर साल 10 फीसद बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए मीनाक्षी शर्मा ने सही तरह के पार्टनरशिप पर जोर दिया। और अब दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ने के कारण कनेक्टीविटी अच्छी हो गई है इसलिए उन्हें उम्मीद है कि अधिक अमेरिकी पर्यटक भारत आसानी से पहुंच सकेंगे।

पिछले साल भी इसी तरह का रोड शो न्यू यार्क में हुआ था और इस साल यह नए शहरों में हो रहा है। अमेरिकी हितधारकों व टूरिज्म पार्टनरों के समक्ष प्रेजेंटशन में मीनाक्षी शर्मा ने कहा कि अमेरिकी पर्यटक भारत में विभिन्न संस्कृतियों, पारंपरिक उत्सवों, अनेकों तरह के खाने का स्वाद के साथ ऐतिहासिक अनुभवों का आनंद ले सकेंगे।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2019

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के रांची तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के रोहतक में योग किया। इसके अलावा पूरी दुनिया में योग किया जा रहा है। योग फॉर हार्ट केयर की थीम पर इस बार आयोजित होने वाले पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगाभ्यास की दिलचस्प तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं।

भारतीय नौसेना के आईएनएस रणवीर पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर नौसेना के जवानों ने योग का प्रदर्शन किया। आईएनएस रणवीर उस समय बंगाल की खाड़ी में तैनात था।

देश की सबसे ऊंची और बेहद संवेदशील सीमा सियाचिन पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मौके पर भारतीय सेना के जवानों ने योग किया तो वहीं सेना के डॉग स्वाक्यड के कुत्तों ने भी योग किया जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुंई।

हांगकांग के मुद्दे पर क्यों पश्चिमी देशों को आंख दिखा रहा है चीन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हांगकांग चीन के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। लगातार हो रहे प्रदर्शनों की वजह से चीन के लिए यह अब बड़ी समस्या बन चुका है। आलम ये है कि लगातार विदेशी मीडिया में प्रकाशित हो रही खबरों के बाद अब चीन ने इसका जवाब देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स से हुई है। अखबार ने इस मामले में सरकार के पक्ष को रखते हुए इसको अंतरराष्ट्रीय नहीं बल्कि चीन का अंदरुनी मामला बताया है। अखबार ने लिखा है कि हांगकांग के मामले से अमेरिका समेत पूरी दुनिया का कोई लेना-देना नहीं है। यह चीन का अंदरूणी मामला है। इससे कैसे निपटना है इससे भी किसी अन्य देश को कोई मतलब नहीं होना चाहिए।

चीन की सरकार की तरफ से इसमें कहा गया है पश्चिमी देश हमेशा से ही चीन के मसलों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश करते रहे हैं। चीन का कहना है कि ट्रेड वार के दौरान अमेरिका कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता है। हांगकांग चीन का स्पेशल एडमिनिसट्रेटिव रीजन (Special Administrative Region) या स्वायत्त क्षेत्र है। चीन इसे अपने संप्रभु राज्य का हिस्सा मानता है। हांगकांग के लोग कई बार इसको चीन से आजाद करने की मांग कर चुके हैं। 12 जून को हांगकांग में हुए विशाल प्रदर्शन में भी कहीं न कहीं इसकी चिंगारी ने काम किया। इस दिन जो विशाल प्रदर्शन हांगकांग की सड़कों पर देखने को मिला वह एक नए कानून को लेकर था। दरअसल, हांगकांग के लोग प्रत्यर्पण कानून में संशोधन के प्रस्ताव का जमकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इसके बाद हांगकांग के लोगों पर चीन का कानून लागू हो जाएगा और लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया जाएगा और उन्हें यातनाएं दी जाएंगी।

पूरी दुनिया में हांगकांग को सुर्खियों में लाने वाले इस प्रदर्शन की वजह थी कि एक शख्स ताईवान में एक महिला की हत्या कर हांगकांग वापस आ गया था। मुकदमा चलाने के लिए जरूरी था कि उसको ताइवान भेजा जाए, लेकिन ताइवान के साथ हांगकांग की प्रत्यर्पण संधि नहीं है। इस वजह से शख्स को ताइवान भेजना मुश्किल है। वर्तमान में हांगकांग का जो कानून है वह अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ है। इसकी करीब एक दर्जन से अधिक देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर शामिल हैं। चीन ने मौजूदा कानून में जो बदलाव किया है उसके तहत चीन को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करने उसको वापस भेजने संबंधी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इसका ही हांगकांग के लोग विरोध कर रहे हैं।

50 साल बाद नासा खोलेगा चंद्रमा के गहरे राज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

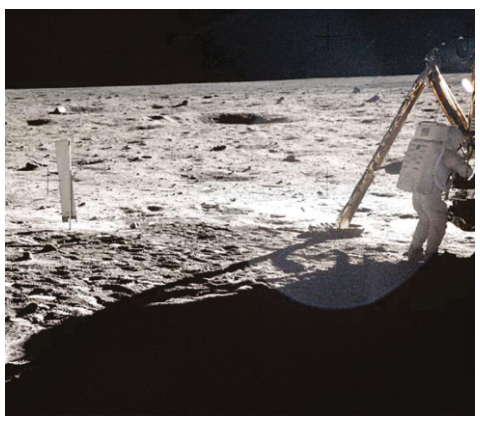

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने अपोलो मिशन द्वारा चंद्रमा की सतह से जुटाए गए कई नमूनों को 50 सालों के बाद पहली बार खोलने जा रहा है। जानसन स्पेस सेंटर की लेबोरेटरी में सैंपल के रूप में नासा का यह खजाना रखा गया है। जिसमें से कुछ सैंपल को पहले छुआ गया है और कुछ अभी तक अनछुए हैं। प्रतिबंधित प्रयोगशाला अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा चंद्रमा से इकट्ठा किए गए उन सैकड़ों पाउंड की चट्टानों का घर है, जिन्हें लगभग आधी सदी पहले यहां बंद कर दिया गया था। नासा अब उन प्राचीन नमूनों में से कई पर शोध करने जा रहा है। नासा का कहना है कि भू-वैज्ञानिक 21वीं की नई तकनीक से उन नमूनों का परीक्षण कर अंतरिक्ष के नए रहस्य खोलेंगे। बता दें कि 20 जुलाई को अपोलो मिशन को पूरे 50 साल हो रहे हैं।

नासा के अपोलो मिशन के सैंपल क्यूरेटर रेयान जिगलर ने बताया कि यह एक संयोग ही है कि हम सैंपलों को अपोलो मिशन की पचासवीं वर्षगांठ के मौके पर खोल रहे हैं।

उन्होंने बताया कि हमें बहुत सतर्कता बरतनी होगी क्योंकि हम फिर से चांद पर जा रहे हैं। बता दें कि नासा का लक्ष्य है कि 2024 तक चंद्रमा की धरती पर फिर से अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाए।

नई तकनीक से पता चलेंगे रहस्य

नासा के जानसन स्पेस सेंटर में 1969 से 1972 तक चंद्रमा से इकट्ठा किए गए सैंपल को रखा गया है। इनका भार 842 पाउंड (382 किग्रा) है। मिट्टी और चट्टानों के कुछ सैंपल वैक्यूम पैक रखे गए हैं जो अभी तक पृथ्वी के वायुमंडल में खोले तक नहीं गए हैं। शोधकर्ताओं ने बताया कि ओपोलो के युग में तकनीक इतनी सक्षम नहीं थी जितनी आज है। पिछले समय में जिस परीक्षण को हम एक ग्राम सैंपल के साथ करते वह अब एक मिलीग्राम के साथ कर सकते हैं। साथ ही नई तकनीक से कई सारे रहस्य सुलझाए जा सकते हैं।

चीन के सिचुआन प्रांत में भूकंप के तेज झटके, 6.0 रिक्टर का भूकंप

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चीन के सिचुआन प्रांत में 17 जून 2019 को रात में और 18 जून 2019 को सुबह भूकंप के तेज झटके आये। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस झटके में लगभग 11 लोगों की जान चली गई और करीब 122 लोग घायल हो गये।

चीनी भूकंप केंद्र (सीईएनसी) के अनुसार रिक्टर पैमाने पर 6.0 की तीव्रता का पहला भूकंप 17 जून 2019 को ईबिन शहर के चांगिंग इलाके में आया था। 18 जून 2019 को रिक्टर पैमाने पर 5.3 की तीव्रता का दूसरा झटका महसूस किया गया।

भूकंप का केंद्र

सीईएनसी के अनुसार, भूकंप का केंद्र 28.34 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 104.90 डिग्री पूर्वी देशांतर में सतह से 16 किलोमीटर अंदर दर्ज किया गया।

आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय और आपातकालीन प्रबंधन के प्रांतीय विभाग ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया है। सिचुआन प्रांत में दमकल विभाग की करीब 63 गाड़ियां और लगभग 302 बचावकर्मी मौके पर तैनात हैं। वहीं ईबिन

में भी स्थानीय दमकल विभाग ने बचाव कार्य के लिए अपने दल भेजे हैं।

भारतीय मूल की प्रिया ने पहना 'मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया' का ताज

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुबई व ओमान के बाद ऑस्ट्रेलिया में रह रही भारतीय मूल की प्रिया सेर्राव ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीता है।

भारतीय मूल की 26 वर्षीय प्रिया सेर्राव ने मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब जीत लिया है। यह जीत उन्होंने देश भर की 27 युवतियों को पीछे कर हासिल किया है। अगले साल मिस यूनिवर्स कंपटीशन में प्रिया ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगी।

मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया वेबसाइट के अनुसार, भारत के कर्नाटक स्थित बेलमान्नु में जन्मी प्रिया का पालन - पोषण मिड्ल ईस्ट में हुआ और 11 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ वे आस्ट्रेलिया आ गईं।

लॉ ग्रेजुएट प्रिया ने कहा कि उनके लिए ईस्ट तिमोर में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इंटर्नशिप करना गर्व का मौका रहा।

लॉ से ग्रेजुएशन कर चुकी प्रिया मेलबर्न में नौकरी करतीं हैं। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले उनका परिवार ओमान व दुबई में रह चुका है। प्रिया ने कहा, 'यह जीत उनके लिए किसी आश्चर्य की तरह है।' प्रिया की यह पहली सौंदर्य प्रतियोगिता है। उन्होंने कहा, 'इसके पहले मैंने न तो किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है और न ही कभी मॉडलिंग की है।'

पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की बेल्ला कासिंबा व विक्टोरियाई मारिजाना राडमानोविक ने 2019 के टॉप 3 में स्थान हासिल किया है।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- गूगल ने इस नाम से साल के सबसे लंबे दिन जून 21 के उपलक्ष्य में डूडल जारी किया है – Happy Summer 2019
- वह राज्य जिसने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा नाम से परियोजना आरंभ की है - महाराष्ट्र
- नेपाल में काठमांडू घाटी तथा उसके साथ लगे कई बड़े निजी स्कूलों ने अपने विद्यार्थियों के लिये यह भाषा सीखना अनिवार्य कर दिया है - मंदारिन
- हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने टी-20 में सबसे अधिक स्कोर अर्जित करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया - युगांडा
- महाराष्ट्र और कर्नाटक को संयुक्त रूप से इस उत्पाद के लिए जीआई टैग दिया गया है - कोल्हापुरी चप्पल
- नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में जिस वर्ष तक भारत के 21 शहरों में जलस्तर की कमी होने की बात कही गई है - 2020
- वह राज्य सरकार जिसने वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराने की घोषणा की है - राजस्थान
- वह देश जिसने अमेरिका के एक टोही ड्रोन को मार गिराया जिससे दोनों देशों के मध्य तल्खी बढ़ गई - ईरान
- हाल ही में वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि जिस देश का अनाज उत्पादन जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है तथा चरम मौसमी स्थितियों के चलते चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय रूप से गिरावट आने की संभावना है- भारत
- हाल ही में जिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत में वित्त वर्ष 2020 में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में सुधार की संभावना व्यक्त की है - इक्रा
- वह देश जिसके राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारत के नागरिक शेख मोहम्मद मुनीर अंसारी को स्टार ऑफ यरुशलम से सम्मानित किया है - फिलिस्तीन
- यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर केतन शर्मा के परिवार को जितने लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है - 25 लाख रुपये
- केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिदेशक आलोक वर्धन चतुर्वेदी का कार्यकाल अगले जितने महीने तक बढ़ा दिया है - तीन महीना
- जिसे हाल ही में जामनगर कोर्ट द्वारा एक कस्टोडियल डेथ मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है - संजीव भट्ट
- हाल ही में जिस यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये शोध में पाया गया है कि इस सदी में हिमालय के ग्लेशियर के पिघलने की गति दोगुनी है - कोलंबिया यूनिवर्सिटी
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 का विषय था - Yoga with Gurus
- हाल ही में जिस देश की महिला टीम ने सबसे कम स्कोर अर्जित करने का रिकहर्ड बनाया है - माली
- जिस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान पहुंचने पर किसानों के लिए 5,000 रुपये न्यूनतम मुआवजा तय किया है - मध्य प्रदेश
- जापान के उत्तर - पश्चिमी तट के निकट जिस द्वीप पर आए 6.5 तीव्रता के भूकंप के बाद देश के यामागाटा, निगाटा और इशीकावा प्रांत के लिए सुनामी अलर्ट जारी कर दिया गया है - होंशू द्वीप
- फेसबुक ने दुनियाभर के अपने यूजर्स के लिए जिस नाम से डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की - लिब्रा
- वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष (2019-20) के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को लगातार दूसरी बार घटाकर जितने प्रतिशत कर दिया है - 6.6 प्रतिशत
- जिस देश के ऑल-राउंडर शाकिब अल हसन वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे तेजी से 6,000 रन और 250 विकेट का डबल पूरा करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं - बांग्लादेश
- हाल ही में जिस देश की पर्यटन परिषद् ने अगले तीन महीने (वर्ष के पीक समय) के लिये सभी पर्यटकों का मंदिरों में प्रवेश बंद कर दिया है - भूटान
- विश्व बैंक ने हाल ही में जिस देश को कर सुधारों के लिए 6,400 करोड़ रुपये का ऋण दिया है - पाकिस्तान
- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में निजी क्षेत्र के जिस बैंक पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया है- एचडीएफसी बैंक
- जिस राज्य सरकार ने अब संस्कृत में भी प्रेस रिलीज जारी करने की घोषणा की - उत्तर प्रदेश
- अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए विश्व कप मैच में इंग्लैंड के कप्तान ऑइन मॉर्गन ने जितने छक्के जड़कर एक वनडे पारी में सर्वाधिक छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया - 17
- साल 2005 में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में हुए आतंकी हमले में प्रयागराज (यूपी) की विशेष अदालत ने जितने दोशियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और एक आरोपी को रिहा कर दिया है - चार
- क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने जिस टीम के द्वारा बनाया गया 322 रनों का लक्ष्य हासिल कर विश्व कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज पूरा किया - वेस्टइंडीज
- वह बॉलीवुड एक्टर जिसने उत्तर प्रदेश में आंख की बीमारियों के बचाव को लेकर अभियान 'See Now' लॉन्च किया है - अमिताभ बच्चन
- हाल ही में जिस देश के सिचुआन प्रांत में आए 6.0 तीव्रता वाले भूकंप के कारण करीब 12 लोगों की मौत हो गई हैं - चीन
- हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जिस राज्य में 1000 अतिरिक्त विदेशी अधिकरणों की स्थापना को मंजूरी दी है - असम
- जर्मनी तथा वह देश जिसके वैज्ञानिकों की एक संयुक्त टीम स्पेक्ट्रम - रॉन्टजेन - गामा नामक अंतरिक्ष दूरबीन लॉन्च करने की योजना बना रही है - रूस
- हाल ही में जिस राज्य में भीषण गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी करते हुए कुछ स्थानों पर धारा - 144 लागू की गई है - बिहार
- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉसपेक्ट्स 2019 रिपोर्ट के मुताबिक चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत जिस वर्ष तक विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा - 2027
- जिस दिन विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है - 17 जून
- जिसे हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चयनित किया गया है - जेपी नड्डा
- 17वीं लोकसभा के लिए एनडीए द्वारा जिसे लोकसभा स्पीकर के पद हेतु नामांकित किया गया है - ओम बिड़ला
- वह बैंक जिसने हाल ही में यशोवर्धन बिड़ला को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है- यूको बैंक
- विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र जिस स्थान पर स्थापित किया गया है - माउंट एवरेस्ट
- जिसे हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा आईएसआई का चीफ नियुक्त किया गया है - फैज हमीद
- विश्व कप 2019 के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला छक्का लगाते ही रोहित शर्मा ने एक भारतीय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का जिसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने नाम कर लिया - महेंद्र सिंह धोनी
- किम्बर्ले प्रक्रिया की अंतर-सत्रीय बैठक का आयोजन 17 जून से 21 जून 2019 के बीच जिस शहर में किया जा रहा है - मुंबई
- 17वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन जिसने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की - प्रोटेम स्पीकर
- हाल ही में Femina Miss India 2019 का खिताब जिसने जीता है - सुमन राव
- हाल ही में भारत के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जिस अनाज की फसल में एक प्रमुख रोगजनक कवक 'राइजोक्टोनिया सोलानी' की आक्रामकता से जुड़ी आनुवंशिक विविधता को उजागर किया है - चावल
- वह राज्य जिसमें चमकी बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इस बुखार से मरने वाले बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है - बिहार
- भारतीय क्रिकेट टीम के जिस ऑल-राउंडर ने अपने विश्व कप करियर की पहली गेंद पर पाकिस्तानी ओपनर इमाम-उल-हक का विकेट ले लिया - विजय शंकर

हिमाचल सामान्य ज्ञान

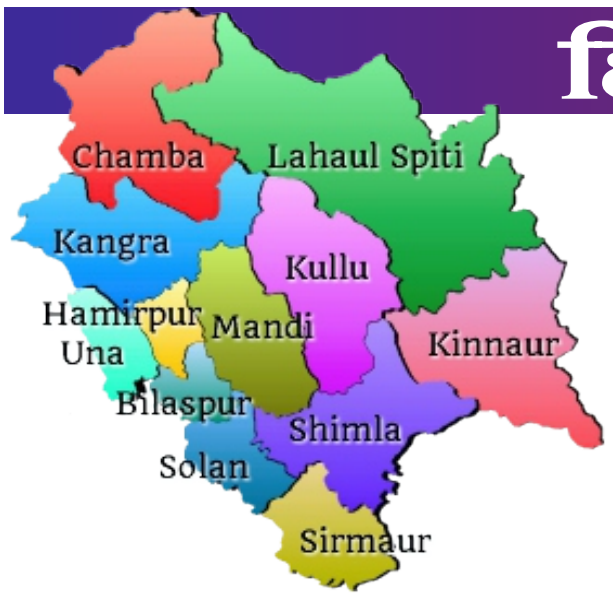

- हिमाचल में बेस्ट परफोर्मिंग अवार्ड किस जिले को दिया गया है - सोलन
- मानव संसाधन मंत्रालय के मुताबिक स्कूल स्तर पर किन कक्षाओं में समेस्टर सिस्टम लागू करने की योजना है - 12वीं तक
- हिमाचल की किस चीज को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है- किन्नौर के काला जिरे को
- अंतर्राश्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव के मौके पर कितनी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने एक साथ नाटी प्रस्तुत की - 650
- हिमाचल में जल्द ही किस विकास कोष का गठन किया जाएगा - फिल्म विकास कोषा
- प्रदेश में पंचायतों को ऑनलाइन करने के लिए कितने करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है - 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट प्रदेश की 3226 पंचायतों के लिए मंजूर किया गया है।
- हिमाचल में पंचायतों के प्रस्तावित पुनर्गठन के मुताबिक एक पंचायत में अधिकतम वोटरों की संख्या कितनी होगी - 1200, पंचायतों का पुनगर्ठन 2014 में किया गया था
- किस आईआईटी ने यूएसए में इंडस्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का अवार्ड जीता है - आईआईटी मंडी
- स्वच्छ भारत मिशन के लिए हिमाचल को केंद्र सरकार की ओर से कितने करोड़ रूपये जारी किए गए हैं - 450 करोड़
- हिमाचल प्रदेश पर्यावरण पुरस्कार किस स्कूल को प्रदान किया गया है - राजपुरा
- पिपलु मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है - ऊना के बंगाणा जिले में
- प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर एयरबस उतारने की तैयारी की जा रही है - कांगड़ा के गगल हवाई अड्डे पर।
- प्रदेश में किन दो जिलों के बीच जल्द ही रेल निर्माण कार्य शुरू करने की योजना है - ऊना और हमीरपुर
- हिमाचल प्रदेश में कौन सा देश कृषि क्षेत्र में निवेश करेगा - नीदरलैंड
- हिमाचल के किस जिले में स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने विदेश में एमओयू साइन किया है - कांगड़ा
- हिमाचल में ड्राई पॉट कान्सेप्ट क्या है और इसे कौन बनाएगा - दुबई की कंपनी शाराफ समूह हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ड्राई पोर्ट का निर्माण करेगी। इन पोर्ट के माध्यम से रेलों द्वारा कच्चा माल उद्योगों तक पहुंचाया जाएगा और तैयार माल का निर्यात भी किया जाएगा।
- शाराफ समूह के साथ प्रदेश सरकार ने कौन से पार्क बनाने के लिए एमओयू किया है - लॉजिस्टिक पार्क
- शाराफ समूह किन तो राज्यों में पहले से कार्य कर रहा है - पंजाब और हिरयाणा में
- डाक्टर थनी अल जियोदी कौन है - यूएई के र्प्यावरण मंत्री। डाक्टर थनी को हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन्वेटस्टर मीट में आने का निमंत्रण दिया है।
- हाल में बस हादसा प्रदेश के किस जिले में हुआ - कुल्लू के बंजार में
- राइजिंग हिमाचल : ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 पर रोड शो का आयोजन कहां पर किया गया - यूएई
- ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा - 8 व 9 नवंबर 2019 को कांगड़ा के धर्मशाला में
- हाल में इंटरनेशल लिट फेस्ट का आयोजन कहां पर किया गया और इसकी क्या थीम थी - इस फेस्ट का आयोजन शिमला में किया गया और थीम थी - द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स एंड इमेजिनेशन। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पौत्री विशेष तौर पर इस फेस्ट में भाग लेने पहुंची।
- नालदेहरा हाल ही में क्यों चर्चा में रहा - भाजपा नेता लालकृष्ण आडवानी निजी दौरे पर यहां पहुंचे। नालदेहरा समुद्र स्तर से 2044 मीटर की ऊंचाई पर गोल्फ के मैदान के लिए प्रसिद्ध हैं। लॉर्ड कर्जन के सुझाव पर 1920-22 में यहां 18 होल्स गोल्फ कोर्स तैयार किया गया था। वह इस स्थान की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने बेटी एलेगजेंडरा का दूसरा नाम ही नालदेहरा रख लिया।
- हाल ही हिमाचल के किस कलाकार को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है - कवि व कथाकार गुरमीत बेदी को।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

'सुकन्या समृद्धि योजना'

केंद्र की मोदी सरकार ने 4 दिसंबर 2014 को बेटियों के लिए छोटी बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के मकसद से विशेष जमा योजना 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत की। सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए है। हाल ही में किए गए बदलाव के तहत अब इस योजना में न्यूनतम जमा राशि को 1,000 रुपए से घटाकर 250 रुपए कर दिया गया है। इसमें बालिका के माता–पिता या संरक्षक बेटी के नाम से खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के कई प्रमुख हैं बिंदु हैं जिसके बारे में द रीव टाइम्स के इस अंक में हम आपको जानकारी दे रहे हैं।

सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में जानकारी

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष तक की आयु तक के बीच खुलवाया जा सकता है। जमाकर्ता बेटी नाम से सिर्फ एक ही खाता खोल सकता है। माता–पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग–अलग एक खाता खोल सकते हैं। यदि जुड़वा बेटियां हैं तो जन्म संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके बाद तीसरा खाता खोला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों को मोदी सरकार की तरफ से मिला बड़ा तोहफा

खाता खोलने के लिए जरूरी राशि

सुकन्या समृद्धि का एक खाता 1000 रुपए में शुरुआती जमा राशि पर खोला जा सकता है। इससे पहले इस खाते में प्रति वर्ष 1000 रुपए न्यूनतम जमा राशि जमा करनी होती थी जो अब सिर्फ 250 रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में इस खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपए जमा किया जा सकेगा। यह पैसा अकाउंट खुलने के 14 साल तक ही जमा करवाना होगा।

खाता संचालन बालिका के 10 वर्ष तक की आयु होने तक माता–पिता खाते को संचालित कर सकते हैं इसके बाद बेटी खुद खाता संचालित कर सकती है।

इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच और सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाया जा सकता है।

जमा राशि निकालने की शर्तें

बालिका के 18 वर्ष की आयु पूरा कर लेने के बाद ही सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा राशि की केवल 50 फीसदी राशि निकाली जा सकती है। यदि किसी कारणवश बालिका की मृत्यु हो जाती है तो संरक्षक द्वारा खाता बंद कर दिया जाएगा और पूरी जमा राशि ब्याज के साथ निकाल ली जाएगी।

खाता कब होगा मेच्योर

बेटी का खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष पूरा होने पर ही खाता मेच्योर होगा। बालिका का विवाह यदि 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष से पहले होता है तो शादी की तारीख के बाद खाता बंद कर दिया जाएगा। खाता बंद होने के बाद जमा रकम ब्याज समेत निकाली जा सकती है।

आयकर में छूट का लाभ

सुकन्या समृद्धि योजना का खाता देश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलने वाले खातों को टैक्स से छूट मिलेगी। इस योजना के तहत खुलने वाले खातों को आयकर कानून की धारा 80–जी के तहत छूट दी जाएगी।

अनियमित भुगतान पर जुर्माना

अनियमित भुगतान अगर खाते में अनियमित भुगतान किया जाता है तो प्रति वर्ष कम से कम 50 रुपए का जुर्माना निर्धारित राशि के साथ लिया जाएगा। विड्रॉल (पैसा निकालना) 50 प्रतिशत राशि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में 18 वर्ष की आयु होने के बाद उच्च शिक्षा और शादी की के लिए इस्तेमाल होगी।

पीपीएफ से ज्यादा ब्याज

सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश राशि पर ही पहले टैक्स छूट थी लेकिन इस बजट में इसके ब्याज और परिपक्वता पर मिलने वाली राशि पर भी टैक्स छूट दी गई है। इस मामले में यह PPF के बराबर हो गया जिस पर तीन स्तरों पर टैक्स छूट मिलती है। लेकिन ब्याज के मामले में सुकन्या समृद्धि योजना PPF से ज्यादा आकर्षक है। PPF पर 8 फीसदी ब्याज मिल रही है जबकि सुकन्या समृद्धि योजना पर 8.5 फीसदी ब्याज है।

ऐसे खुलवाएं खाता

आप दो तरह से सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाने के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पहला– कि आप अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाएं और वहां शाखा

प्रबंधक से इस विषय में जानकारी मांगे। शाखा प्रबंधक आपको इस योजना के विषय में हर बात बताएंगे। दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट के माध्यम से सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करें।

पोस्ट ऑफिस में ऐसे खोले खाता

अपने निकटतम पोस्टऑफिस में जायें और वहां से सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म प्राप्त करें। अगर समय नहीं है, तो आप इंटरनेट से इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। बेटी की फोटोग्राफ लगाकर व फॉर्म भर कर उसे पोस्ट ऑफिस में जमा कर दीजिये। फॉर्म भरें और उसमें सही – सही हस्ताक्षर करें अपना आईडी और एड्रेस प्रूफ की फोटोकॉपी संलंग्न करें अगर आधार कार्ड है, तो उसकी कॉपी संलंग्न करना ज्यादा बेहतर होगा। बेटी के जन्म प्रमाण पत्र की कॉपी, अपनी और अपनी बेटी की दो–दो पासपोर्ट साइज फोटो। अकाउंट या खाता खुलने के बाद आप पैसे चेक या डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी जमा कर सकते हैं।

अधिकतम तीन खाते

एक व्यक्ति द्वारा अधिकतम दो से तीन खाते खोले जा सकते हैं। इस योजना में दो ही खाते का प्रावधान है लेकिन अगर जुड़ुवा लड़की है तो इस संबंध में आपको प्रमाण पत्र पेश करना होगा जिसके बाद आप तीसरा खाता खुलवा सकते हैं। किसी भी दशा में 3 से अधिक खाता नहीं खोला जा सकता है। खाते में न्यूनतम राशि 250 रुपए या अधिकतम राशि 1,50,000 वार्षिक जमा की जा सकती है।

योजना की ब्याज दर घटाए

इस खाते की कुल अवधि 21 साल है और इस खाते पर ब्याज 8.40 प्रतिशत का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं से 0.1 फीसदी ब्याज की कटौती की थी जिसके

बाद इन खातों पर भी मिलने वाला ब्याज कम हो गया है। इस योजना के तहत मिलने वाला ब्याज परिवर्तनीय होता है। योजना में आपको आयकर अधिनियम, 1961 की धारा (सी) के अंतर्गत टैक्स की छूट दी जाती है।

'बेटी है अनमोल योजना'

"बेटी हैं अनमोल योजना" हिमाचल प्रदेश की यह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हैं। इस योजना के तहत सरकार बीपीएल परिवारों की लड़कियों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है। सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से स्नातक स्तर पर समकक्ष पाठ्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों में पढ़ाई करने वाली लड़कियों को 5000 हजार रूपये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

"बेटी हैं अनमोल योजना" के अंतर्गत बीपीएल परिवारों से संबंधित लड़कियों को राज्य सरकार से छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता और राज्य में बालिका के जन्म के समय और फिर वार्षिक छात्रवृत्ति के रूप में भी सहायता प्रदान की जाती है।

"बेटी हैं अनमोल योजना" का मुख्य उद्देश्य लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत 01– 12 वीं कक्षा में पढ़ रही लड़कियों को सरकार 300 से 1200 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। इसके अलावा बीपीएल परिवारों की लड़कियों को स्नातक स्तर या समकक्ष कोर्स कर रही बीपीएल परिवार की लड़कियों को सरकार की तरफ से पढ़ाई के लिए 5000 रुपये वार्षिक छात्रवृति देने का प्रावधान है। जो छात्रायें बीए, बीटेक, कॉमर्स, एमबीबीएस,एलएलबी तथा बीएड की पढ़ाई करने वाली छात्रायें है वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं।

बेटी हैं अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ

हिमाचल प्रदेश में बेटी हैं अनमोल योजना से छात्राओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। जिनके बारे में नीचे विवरण दिया गया हैं। "बेटी हैं अनमोल योजना" हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों के लिए है, इस योजना का लाभ परिवार की दो लड़कियों के लिए है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पोस्ट ऑफिस /बैंक खाते में 12,000 रूपये प्रति लड़की के खाते में जमा किए जायेंगे।

बेटी हैं अनमोल योजना के तहत छात्रवृत्ति 300 से 1200 रूपये पहली क्लास से 12 वीं कक्षा तक लड़कियों को उनकी पुस्तकों /कपड़े आदि के लिए दिया जायेगे।

इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों और स्नातक स्तर में पढ रही लड़कियों को 5000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

बेटी हैं अनमोल योजना के अंतर्गत 05 जुलाई 2010 के बाद पैदा हुई सभी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों के इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र हैं।

बेटी हैं अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लाभ लेने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं।

आधार कार्ड की फोटो कॉपी
आय प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
बीपीएल राशन कार्ड
निवास प्रमाण पत्र

बेटी हैं अनमोल योजना ऑनलाइन आवेदन

- यदि आप "बेटी हैं अनमोल योजना" हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले राज्य की ऑफिसियल वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद "ई डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश" का होम पेज खुल जायेगा।
- इसके बाद होमपेज पर वेबपेज के दाईं ओर "लॉगिन" अनुभाग के नीचे "नया

पंजीकरण" लिंक पर क्लिक करें।
- उसके बाद अगले पेज पर एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यान पूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद "रजिस्टर बटन" पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदक व्यक्ति आवेदन पत्र भर सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक व्यक्ति को होम पेज पर जाना होगा। होम पेज पर बाईं ओर "सेवा की सूची" अनुभाग पर क्लिक करें।
- इसके बाद सेवाओं की सूची में "महिला और बाल कल्याण विभाग" अनुभाग के अंतर्गत "बेटी है अनमोल योजना" के विकल्प पर क्लिक करें।
- अब अगले पेज पर "यूजर आईडी" और "पासवर्ड" का प्रयोग करके अगला लॉगिन करें और "आगे बढ़ें" बटन पर क्लिक करें।
- उसके बाद एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। इस आवेदन पत्र में आवेदक को माता का विवरण, लड़की बाल विवरण, पता विवरण, बैंक विवरण भरना होगा और नीचे दिए गए समर्थन दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा।
- आवेदक द्वारा आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "सबमिट करें बटन " पर क्लिक करना होगा और अब आप पुष्टि की रसीद का प्रिंटआउट ले सकते हैं।

बेटी हैं अनमोल योजना हिमाचल प्रदेश में ऑफलाइन आवेदन

हिमाचल प्रदेश में आवेदक व्यक्ति "बेटी हैं अनमोल योजना" के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए आवेदककर्ता व्यक्ति को संबंधित ब्लॉक के बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। उसके बाद बाल विकास परियोजना अधिकारी संबंधित आवेदन के लिए संबंधित जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी को मंजूरी के लिए भेज देंगे। बेटी हैं अनमोल योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।

(edistrict.hp.gov.in)

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

सोलर चरखा मिशन ..... रोजगार के क्षेत्र में नया क़दम

सोलर चरखा मिशन योजना

भारत सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी गंभीर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाओं का संचालन किया है, जो महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। ऐसी ही एक योजना की शुरूआत जून 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर सोलर चरखा मिशन के नाम से की गई। ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण आर्थिक भूमिका को चिह्नित किया जा सके। इस योजना का संचालन माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है । गाँव में रहने वाले कई ऐसे लोग हैं जो शिल्पकार भी है, लेकिन बेहतर प्रशिक्षण एवं उनकी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्हें बेरोजगारी में रहना पड़ता है । इसको ध्यान में रखते हुए देश की राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने मिल कर कई कदम उठाये हैं । सोलर चरखा मिशन एक ऐसी ही योजना है जिसके माध्यम से महिला सशक्तिकरण और उन्हें बेहतर रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई गयी है । इस मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा, ताकि वे कपड़ों का निर्माण कर अपनी बेहतर आजीविका चलाने में सक्षम हो सकें । इस योजना के अंतर्गत पहले 2 वर्षों में कुल 550 करोड रुपए सरकार सब्सिडी के रूप में खर्च करेगी । जिससे देश में करीब 5 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाया जाएगा । इसके साथ ही इस योजना द्वारा एक लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां प्राप्त करने का अवसर मिलेगा

सोलर चरखा मिशन से खासकर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सरकार का लक्ष्य है इस योजना से 5 करोड़ भारतीय महिलाओं को जोड़ना । इस बड़ी योजना के द्वारा एक लाख से ज्यादा नौकरियों का अवसर लोगों को मिलेगा । सोलर चरखा मिशन को सरकार ने स्वीकृति दे दी है और 50 क्लस्टर में 550 करोड़ रुपए भी इस योजना में सब्सिडी के लिए स्वीकृति दिए जा चुके । हर एक क्लस्टर में लगभग 400 से 2000 कारीगर काम करेंगे।

सरकार के अनुसार सोलर चरखा मिशन में लगभग 10000 करोड़ रुपए मात्र छोटे कंपनी सेक्टर में खर्च होने वाले हैं। यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत एक बेहतरीन पहल है।

इसके लिए 15 नए टेक्नोलॉजी सेंटर शुरू किए जाएंगे जिनमें से 10 को इसी वर्ष शुरू करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी । यहां सेंटर सभी छोटे उद्यमियों को तकनीकी सुविधाएं प्रदान करेंगे ।

सोलर चरखा मिशन के मुख्य उद्देश्य

- ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके कौशल के आधार पर नौकरी दिलाना।
- एक प्राकृतिक ऊर्जा संरक्षण का मॉडल बनाना है।
- खादी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना।
- हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना।
- गरीब लोगों के लिए स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।

सोलर चरखा योजना का उद्देश्य

- देश के पारंपरिक कला से सम्बंधित कुटीर, लघु एवं माध्यम उद्योग को बढ़ावा देना है।
- सोलर चरखा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कम लागत के प्रोजेक्ट स्थापित करने की योजना से महिला उद्यमियों को नए उद्यम लगाने के लिए प्रेरित करना है।
- खादी उद्योग में सूत कातने का काम ज्यादातर महिलाएं करतीं हैं। अतः सोलर चरखा के द्वारा सूत कम समय में ज्यादा तैयार होगें । जिससे देश की महिलाएं की आय में वृद्धि होगी और वो स्वावलंबी बनेंगी ।
- इस योजना के तहत सोलर चरखा के माध्यम से सूत तैयार करने में कम समय में ज्यादा उत्पादन होगा। पारम्परिक चरखे से बुनकर मजदूर दिन में 8 घंटे काम करने पर रूपए 160 कमाते हैं। वहीँ सोलर चरखे के द्वारा दिन में रूपए 360 तक कमा पाएंगे। इस तरह उनके आमदनी में वृद्धि होगी।
- इस योजना का उद्देश्य बुनकर–शिल्पकार–सूत कातने वाले मजदूरों के आय में वृद्धि करना, तथा उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
- खादी उद्योग को पुनर्जीवित करना है।

सोलर चरखा योजना के लाभ

- इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।
- सोलर चरखा योजना के माध्यम से सोलर ऊर्जा के उपयोग से नागरिकों को परिचित करवाना है।
- पर्यावरण सुरक्षा हेतु सोलर ऊर्जा को देश में बढ़ावा देन है।
- सोलर चरखा के उपयोग से बुनकरों और सूत कातने वाले मजदूरों की आय में वृद्धि करना है ।
- इस योजना के माध्यम से देश भर में 5 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे, तथा प्रत्येक पंचायत में 1100 नए रोजगार का सृजन होगा ।

सोलर चरखा योजना का बिजनेस मॉडल

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लोन दिया जायेगा । इस योजना के तहत सोलर ऊर्जा इकाई स्थापित करने का कुल खर्च 24,87,694/– रूपए है । इसमें से रुपये 22,38,925/ लोन बैंक से प्राप्त हो जायेगा, तथा बची हुई राशि का(मार्जिन मनी) रूपए 621924/ सब्सिडी सरकार की ओर से स्वरोजगार हेतु उद्यम स्थापित करने और देश में रोजगार के अवसर बढ़ने के एवज में च्डम्ळ के अंतर्गत मिलेगा। आपको अपने पास से लगाना है मात्र रूपए 248769/ और आपका सोलर चरखा प्रोजेक्ट लग जायेगा। इस उद्यम को लगाकर आप वार्षिक 80,000– 100000 रूपए तक कम सकेंगे ।

सौर चरखा मिशन के बारे में:

- सौर चरखा मिशन में 50 समूह शामिल होंगे.
- यह मिशन कारीगरों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया गया हैं ।
- यह मिशन 50 क्लस्टर को कवर करेगा तथा प्रत्येक क्लस्टर 400 से 2000 कारीगरों को नियुक्त करेगा ।
- इस मिशन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदिन कर दिया गया है ।
- इस मिशन के लिए एमएसएमई मंत्रालय कारीगारों को 550 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित करेगा ।
- सौर चरखा मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होगा, जो पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा ।
- सौर चरखा मिशन का मुख्य लक्ष्य देश भर में पांच करोड़ महिलाओं को जोड़ना है ।
- इस योजना के तहत, सरकार पहले दो वर्षों के दौरान एक लाख

महिलाओं को नौकरियां देगी ।
- सौर चरखा मिशन 2018 के तहत महिलाओं के लिए एक नया काम पाने का एक शानदार अवसर होगा ।
- इस योजना को विशेष रूप से देश भर में महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई)

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अन्दर रहता है। किसी भी देश के विकास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
- भारत की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष निर्यात में 45 प्रतिशत हिस्सा है। केन्द्रीय या राज्य सरकार और बैंकिंग एमएसएमई अधिनियम के तहत लाभ को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई पंजीकरण आवश्यक है।
- एमएसएमई क्षेत्र उद्यमशीलता के लिए प्रजनन भूमि की तरह होता है, जोकि अक्सर वैयक्तिक सृजनशीलता और नवाचार से संचालित होता है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 8 फीसदी, विनिर्मित उत्पादन में 45 और इसके निर्यात में 40 फीसदी का योगदान देता है।

ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदाम

खाद्यान्नों के सहज और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉक और पंचायत स्तर पर मध्यवर्ती गोदामों का एक नेटवर्क आवश्यक है । वर्तमान में, कई राज्यों में एफसीआई की भंडारण डिपुओं से खाद्यान्न उठाए जाते हैं और उचित दर दुकानों को सीधे भेज दिए जाते हैं । खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग मध्यवर्ती स्तर पर भंडारण सुविधाओं, जहां से खाद्यान्न उचित दर दुकानों तक भेजा जा सकता है, के निर्माण की जरूरत पर समय–समय पर राज्य सरकारों पर दबाव डालता रहा है । पंचायत स्तर पर निर्मित इस तरह का गोदाम किसानों को अपनी फसलों को बेचने, स्टाफ रखने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा ।

ऐसे गोदामों का निर्माण अब राज्य सरकारों द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना के तहत प्रदान की गई निधि का उपयोग कर किया जा सकता है । ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में उपयुक्त संशोधन कर दिया है जिसके परिणामस्वीरूप इस तरह के निर्माण योजना के अंतर्गत पात्र गतिविधियों में शामिल हो गया है ।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा, प्रबन्ध सम्पादक : आनन्द नायर फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
RNI Reference No. 1328500

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कुरुक्षेत्र में ही क्यों हुआ महाभारत का भीषण युद्ध

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ये तो हम सभी जानते हैं कि गीता का उपदेश श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही दिया था और इसी जगह महाभारत का भीषण युद्ध भी हुआ था। ये युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन इससे जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं, जिनके बारे में आज भी बहुत कम ही लोगों को पता है। इन्हीं रहस्यों में एक प्रश्न यह भी है कि क्यों महाभारत का युद्ध आखिर कुरुक्षेत्र में हुआ था?

यह सबसे भीषण युद्ध था। उससे पहले न तो कभी ऐसा युद्ध हुआ था और न ही भविष्य में कभी ऐसा युद्ध होने की संभावना है। कुरुक्षेत्र की धरती को महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने ही चुना था, लेकिन उन्होंने कुरुक्षेत्र को ही महाभारत युद्ध के लिए क्यों चुना, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा है। शास्त्रों के मुताबिक, महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो उसके लिये जमीन तलाश की जाने लगी। भगवान श्रीकृष्ण इस युद्ध के जरिए धरती

पर बढ़ते पाप को मिटाना चाहते थे और धर्म की स्थापना करना चाहते थे।

कहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण को ये डर था कि भाई-भाइयों के, गुरु-शिष्यों के और सगे-संबंधियों के इस युद्ध में एक दूसरे को मरते देखकर कहीं कौरव और पांडव संधि न कर लें। इसलिए उन्होंने युद्ध के लिए ऐसी भूमि चुनने का फैसला किया, जहां क्रोध और द्वेष पर्याप्त मात्रा में हों। इसके लिए श्रीकृष्ण ने अपने दूतों को सभी दिशाओं में भेजा और उन्हें वहां की घटनाओं का जायजा लेने को कहा।

सभी दूतों ने सभी दिशाओं में घटनाओं का जायजा लिया और भगवान श्रीकृष्ण को एक-एक कर उसके बारे में बताया। उसमें से एक दूत ने एक घटना के बारे में बताया कि कुरुक्षेत्र में एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को खेत की मेंड़ टूटने पर बहते हुए वर्षा के पानी को रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर बड़ा भाई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने छोटे भाई को छुरे से गोद कर मार डाला और उसकी लाश को घसीटता हुआ उस मेंड़ के पास ले गया और जहां से पानी निकल रहा था वहां उसकी लाश को पानी रोकने के लिए लगा दिया।

दूत द्वारा सुनाई इस सच्ची घटना को सुनकर श्रीकृष्ण ने तय किया कि यही भूमि भाई-भाई, गुरु-शिष्य और सगे-संबंधियों के युद्ध के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। श्रीकृष्ण अब बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि इस भूमि के संस्कार यहां पर भाइयों के युद्ध में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसके बाद उन्होंने महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में करवाने का एलान कर दिया।

ये है धरती का पाताल लोक यहां जमीन के नीचे रहते हैं लोग

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आपने अक्सर दादी-नानी की कहानियों में पाताल लोक के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पाताल लोक धरती पर भी मौजूद हैं, जहां जमीन के नीचे घर बनाकर लोग रहते हैं। इसकी वजह भी बेहद चौंकाने वाली है।ये है अफ्रीकी देश ट्यूनिशिया का दजेबेल दाहर इलाका, जहां लोग आज भी सैकड़ों साल पुराने घरों में रहते हैं। ये घर जमीन के नीचे बने होते हैं। इस अंडरग्राउंड गांव को तिज्मा के नाम से जाना जाता है।

100 साल पुराने इन घरों में लोग रहते तो हैं ही, साथ ही उन्होंने जीवन यापन की तमाम सुविधाएं भी यहां इकट्ठा कर ली हैं। हालांकि यहां रहने वाले ज्यादातर लोग वही हैं, जिनकी जमीन आसपास है और उन्हें यहां खेती करनी होती है। इसके अलावा काफी लोग इस इलाके को छोड़कर शहरी क्षेत्रों की ओर कूच कर गए हैं।

इस देश में शुरु होने वाली है स्मार्ट पार्किंग सिस्टम, जहां रोबोट कार पार्क करेंगे

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया में पावर हाउस के नाम से विख्यात 'चीन' इन दिनों अपने देश के एयरपोर्ट को स्मार्ट बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। चीन के बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रोबोटिक पार्किंग सिस्टम से लैस करने की तैयारी जोरों पर चल रहीं है। महीने के अंत तक एयरपोर्ट पर ट्रायल शुरू हो जाएगा।

बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आईटी विभाग के इंजीनियर बा जनरल ने कहा कि पार्किंग में 132 गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। यहां पर आठ रोबोट अपनी सेवा देंगे, फिलहाल अभी इस सिस्टम का ट्रायल हो रहा है।

बा जनरल की मानें तो रोबोट 3.5 मीट्रिक टन तक भार ले जानें में सक्षम है। इन रोबोट्स को एक बार चार्ज करने पर यह छह घंटे तक काम कर सकते हैं। साथ ही बैटरी कम होने पर खुद को रिचार्ज करने के लिए वे चार्जिंग स्टेशन पर भी जा सकते हैं।

एयरपोर्ट में काम करने वाले रोबोट कारों की समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं, जिससे पार्किंग में होने वाली दुर्घटनाओं से कारों को बचाया जा सके। ये रोबोट महज एक मिनट में गाड़ी को पार्क कर देंगे।

यदि आप भूल गए हैं कि आपकी कार कहां खड़ी थी, तो आपको केवल पार्किंग टिकट को स्कैन करने या कार पिकअप टर्मिनल पर कार प्लेट नंबर दर्ज करने की आवश्यकता है, कार की जगह आपको अपने आप पता चल जाएगी क्योंकि यहां स्मार्ट पार्किंग में क्यूआर कोड लगाए गए हैं।

ये हैं दुनिया के पांच सबसे छोटे देश, एक की आबादी तो हजार से भी कम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लगभग प्रत्येक दिन हम अमेरिका, चीन, रूस जैसे बड़े देशों की खबरें सुनते रहते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर कई ऐसे देश भी हैं जो आपके शहरों से भी छोटे हैं। इतना ही नहीं एक देश तो ऐसा है जहां की आबादी एक हजार भी नहीं है। लेकिन, इस देश में बड़ी संख्या में लोग घूमने आते हैं। जानिए ऐसे ही देशों के बारे में:

सैन मैरिनो

सैन मैरिनो यूरोप का सबसे पुराना देश है। इसे विश्व का पांचवां सबसे छोटा देश माना जाता है। यहा की भाषा इटालियन है। 61 वर्ग किलोमीटर में फैले इस देश की जनसंख्या तकरीबन 33 हजार के आस पास है।

नौरु

प्रशांत महासागर में स्थित इस देश का क्षेत्रफल 21.3 वर्ग किलोमीटर के करीब है। इस देश की कुल आबादी करीब 13 हजार है। नौरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीप राष्ट्र होने के साथ तीसरा सबसे छोटा देश है। यह दुनिया में एकमात्र ऐसा गणतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी कोई राजधानी नहीं है।

मोनैको

फ्रांस और इटली के बीच समुद्र किनारे बसे इस देश को दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश होने का तमगा प्राप्त है। इस देश का सबसे बड़ा कस्बा मॉन्टे कार्लो है।

वैटिकन सिटी

यूरोप महाद्वीप में स्थित यह दुनिया का सबसे छोटा देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है। जबकि

आबादी लगभग 800 है। इस के अपने सिक्के, अपना डाक विभाग और अपना रेडियो स्टेशन भी है। इसे इसाई धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है।

तुवालु

आस्ट्रेलिया और हवाई के बीच द्वीप पर बसा यह देश कभी ब्रिटेन का उपनिवेश था। हालांकि जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश समुद्र में डूब रहा है। इस देश का क्षेत्रफल 26 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी फुनाफुटी है।

इस देश में रोबोट करता है पुलिस का काम, सुरक्षा के साथ-साथ करता है हर मदद

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आज के समय में गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने और समाज में उचित न्याय व्यवस्था को बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहें है। एक ऐसा ही प्रयास इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसे हम विज्ञान का चत्मकार भी कह सकते हैं कि रोबोट अब समाज के न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी काम करेगा। ऐसा ही एक रोबोकॉप (रोबोट पुलिस) बीते दिनों अमेरिका की सड़कों पर तैनात नजर आया, इस रोबोट को एचपी रोबोकॉप नाम दिया गया है। अंतरिक्ष

कैप्सूल की आकार का यह रोबोट पूरी तरह स्वचलित होगा और सड़कों पर अपनी पैनी नजर रखेगा।

इस रोबोकॉप की खास बात यह है कि पैट्रोलिंग करते समय 360 डिग्री पर नजर रखेगा। अपने पैट्रोलिंग के दौरान यह सड़कों, आस-पास के पार्क और भवनों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखतें हुए, आपराधिक गतिविधियों की सारी जानकारी सीधे पुलिस मुख्यालय को भेजेगा। जिससे किसी भी आपातकालीन स्थिति में पुलिस अपनी सेवा तत्काल रुप से आम नागरिकों तक पहुंचा पाएगी।

मीडिया में आई खबरों के अनुसार इस रोबोकॉप को सबसे पहले हंटिग्टन पार्क की सड़क पर तैनात किया गया, जो लॉस एंजिलिस से 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। इस शहर की आबादी लगभग 50 हजार है।

दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान पर हेलीकॉप्टर हो जाते हैं क्रैश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पूर्वी साइबेरिया में बसा मिरनी माइन दुनिया की सबसे बड़ी हीरे की खदान है। इस खदान से बेहिसाब हीरे निकलते हैं। यह खदान 1722 फीट गहरी और 3900 फीट चौड़ी है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित गड्ढा भी है। इस खदान को 13 जून, 1955 को सोवियत भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा खोजा गया था। इसे खोजने वाले दल में यूरी खबरदिन, एकातेरिना एलाबीना और विक्टर एवदीनको शामिल थे। इसे खोजने के लिए सोवियत भूविज्ञानी यूवी खबरदीन को साल 1957 में लेनिन पुरस्कार दिया गया था। दरअसल इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। यहां साल के ज्यादातर महीनों में मौसम बेहद खराब रहता है। सर्दियों में यहां तापमान इतना गिर जाता है कि गाड़ियों में तेल भी जम जाता है और टायर फट जाते हैं। इसे खोदने के लिए कर्मचारियों ने जेट इंजन और डायनामाइट्स का इस्तेमाल किया था। रात के समय इसे ढक दिया जाता था, ताकि मशीनें खराब ना हो जाएं। इस खदान की खोज के बाद रूस हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया था। पहले इस खदान से हर साल 10 मिलियन यानी एक करोड़ कैरेट हीरा निकाला जाता था।

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा।

द रीव टाइम्स

दूरभाष : 9418404334

Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

प्रिय पाठक बंधुओं,

द रीव टाइम्स समाचार पत्र को आपका अपार स्नेह और सहयोग विगत एक वर्ष में प्राप्त हुआ जिसके लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। जुलाई 2019 से द रीव टाइम्स द्वितीय वर्ष में सफलतम रुप से प्रवेश कर रहा है और 'आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़' के साथ निष्पक्ष, निर्भीक और सत्य की कसौटी पर निरंतर गतिमान रहेगा। इस अवसर पर आप सभी सुधी पाठकों से निवेदन है कि आप द रीव टाइम्स के साथ विगत एक वर्ष के अनुभव को साझा कर सकते हैं। अपने सुझाव आप व्ट्सऐप या मेल पर भेजें -

md@iirdshimla.org/
chauhan.hemraj09@gmail.com

9418404334

द रीव टाइम्स
The RIEV Times
आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़